वर्ष 12 • अंक 269 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

सोमवार 30 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 3

मार्जिन बढ़ाने के लिए गुणवत्ता पर जोर दे रहीं चाय कंपनियां

नरेंद्र मोदी पृष्ठ 4

स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील

एक नज़र

ई-वाणिज्य, नई औद्योगिक नीति इसी वित्त वर्ष में

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) इस वित्त वर्ष के अंत तक ई-कॉमर्स और नई औद्योगिक नीति लाने के लिए सक्रियता से काम कर रहा है। एक शीर्ष अधिकारी ने रविवार को इसकी जानकारी दी। डीपीआईआईटी के सचिव गुरुप्रसाद महापात्र ने कहा कि उनका व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि ये नीतियां चालू वित्त वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि विभाग ने इस संबंध में संबंधित पक्षों से कई दौर की बातचीत की है। सरकार ने फरवरी में राष्ट्रीय ई-वाणिज्य नीति का मसौदा पेश किया था, जिसमें देश से बाहर डेटा का प्रसार रोकने के लिए एक कानूनी एवं तकनीकी ढांचा बनाने का प्रस्ताव दिया था।

करदाताओं को संवाद में डीआईएन का जिक्र जरूरी

सीमा शुल्क विभाग ने ई-मेल सहित सभी संवादों में डॉक्यूमेंट आइडेंटीफिकेशन नंबर (डीआईएन) का जिक्र करना अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने कर प्रशासन में पारदर्शिता लाने के मकसद से यह कदम उठाया है। नवंबर के शुरू में डीआईएन प्रणाली केवल अधिकरण, समन, अरेस्ट मेमो, निरीक्षण नोटिस और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों के लिए अनिवार्य की गई थी। सीबीआईसी द्वारा हाल में जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि देश भर में सीबीआईसी कार्यालय द्वारा करदाताओं एवं संबंधित व्यक्तियों को भेजे जाने वाले संवाद में डीआईएन का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

डीआईसीजीसी के पास आए 14,000 करोड़ रु. के दावे

डिपॉजिट इंश्योरेंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) को भुगतान में चूक करने वाले सहकारी बैंक से जुड़े 14,100 करोड़ रुपये के दावे मिले हैं। ये दावे ऐसे समय में आए हैं जब पंजाब-महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक में हुए फर्जीवाड़े से पूरा बैंकिंग जगत स्तब्ध रह गया है। आरबीआई ने यह जानकारी दी है। वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में आरबीआई ने यह भी कहा कि सभी दावे एक साथ नहीं निपटाए जा सकते और कुछ दोबारा भी अस्तित्व में आ सकते हैं।

डीएचएफएल पर सोमवार को होगी बैठक

संकटग्रस्त दीवान हाउसिंग फाइनैंस (डीएचएफएल) के प्रशासक ने कंपनी के कर्जदाताओं की सोमवार को बैठक बुलाई है। आरबीआई द्वारा नियुक्त प्रशासक ने ऋण शोधन प्रक्रिया में डीएचएफएल में जाने के बाद पहली बार कर्जदाताओं की बैठक बुलाई है। आवास ऋण देने वाली डीएचएफएल पहली ऐसी एनबीएफसी है, जिसे ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता के तहत समाधान के लिए भेजा गया है। कंपनी के कर्जदाताओं की सोमवार को होने वाली बैठक में कंपनी के सभी कर्जदाता शामिल होंगे।

एयरटेल ने प्रीपेड पर बढ़ाया न्यूनतम रिचार्ज

दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने रविवार को प्रीपेड ग्राहकों के लिए रिचार्ज की अनिवार्य न्यूनतम राशि 23 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये कर दी। बढ़ी हुई दर रविवार से ही प्रभावी हो गई। कंपनी ने एक बयान में बताया कि भारती एयरटेल और भारती हेक्साकॉम के प्रीपेड ग्राहकों को 28 दिन की वैधता पाने के लिए कम से कम 45 रुपये का रिचार्ज कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 15 दिन की मोहलत दी जा सकती है और उसके बाद सभी सेवाओं को निलंबित कर दिया जाएगा।

सेल के अगले चेयरमैन के लिए चयन प्रक्रिया शुरू

सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के नए चेयरमैन के चयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेल के मौजूदा चेयरमैन ए के चौधरी दिसंबर 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन्होंने सितंबर 2018 में कार्यभार संभाला था। सरकार की मंजूरी पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के चेयरमैन को सेवा विस्तार भी मिल सकता है।

आज का सवाल

क्या अगले वित्त वर्ष देश की आर्थिक विकास दर में आएगी तेजी

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या बैंकों को एनपीए में कमी लाने के लिए करने चाहिए सख्त उपाय — हां **86.67%**, नहीं **13.33%**

एनपीए पर होगी माथापच्ची

7 जून के आरबीआई के परिपत्र के बाद बैंक अतिरिक्त प्रावधान की कर सकते हैं मांग

रघु मोहन
नई दिल्ली, 29 दिसंबर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) वित्त मंत्रालय के साथ बजट पूर्व बैठक में बैंकों के अतिरिक्त प्रावधान और दूरसंचार कंपनियों के ऋण पर दबाव के मुद्दे पर चर्चा करेगा। आरबीआई के 7 जून के परिपत्र के कारण बैंक अतिरिक्त प्रावधान की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा समायोजित सकल राजस्व पर उच्चतम न्यायालय के आदेश से दूरसंचार कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस आदेश के मुताबिक उन्हें सरकार को ब्याज और जुर्माने सहित 1.33 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करना है।

आरबीआई की पिछले सप्ताह आई वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट (एफएसआर) में कहा गया था कि बैंकों का सकल एनपीए सितंबर 2020 तक बढ़कर 9.9 फीसदी पहुंच सकता है जो सितंबर 2019 में 9.3 फीसदी था। बैंक का मानना था कि इसके लिए वृहद आर्थिक परिदृश्य में बदलाव, राजकोषीय फिसलन में मामूली बढ़ोतरी और उधारी वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं।

बैंक चूककर्ता कंपनियों का समाधान खोजने में नाकाम रहे हैं जिसके कारण आरबीआई ने 7 जून को परिपत्र जारी किया था। इसके कारण वित्त वर्ष 2020 की अंतिम तिमाही में 3.8 लाख करोड़ रुपये के ऋण पर संकट पैदा हो सकता है। आरबीआई रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं था। साथ ही उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद तीसरी तिमाही में दूरसंचार कंपनियों के ऋण पर दबाव के बारे में भी एफएसआर में कुछ नहीं कहा गया था। केंद्रीय बैंक के 12 फरवरी, 2018 के परिपत्र को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। इसके बाद आरबीआई ने इस साल 7 जून को संशोधित परिपत्र जारी किया था। इसमें बैंकों से कहा गया है कि अगर वे समाधान प्रक्रिया में आगे बढ़ने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें अतिरिक्त प्रावधान करने होंगे। यह रकम समीक्षा अवधि के छह महीने बाद बकाया राशि का 20 फीसदी होगी और एक साल बाद इसमें और 15 फीसदी राशि जुड़ जाएगी। छह महीने की अवधि और एक महीने की मुहलत की अवधि 7 जनवरी, 2020 में खत्म होगी और इसके दायरे में 20 बड़े दबावग्रस्त खाते हैं।

- बजट पूर्व बैठक में आरबीआई वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाएगा एनपीए का मुद्दा
- दूरसंचार कपंनियों के ऋण पर भी होगी चर्चा
- चौथी तिमाही में 3.8 लाख करोड़ रुपये के ऋण पर खतरा

7 जून का परिपत्र जब जारी किया गया था तो इसके दायरे में केवल 2,000 करोड़ रुपये से राशि के दबावग्रस्त खाते थे लेकिन यह 1 जनवरी, 2020 से यह 1,500 करोड़ रुपये से 2,000 करोड़ रुपये तक के खातों पर लागू होगा। हालांकि 1,500 करोड़ रुपये से कम राशि के दबावग्रस्त खातों के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है। सूत्रों का कहना है कि जल्दी ही एक परिपत्र जारी किया जाएगा जिसमें इस तरह के दबावग्रस्त खाते शामिल किए जाएंगे।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद दूरसंचार कंपनियों के ऋण पर नया बोझ पड़ा है। इस आदेश के मुताबिक उन्हें सरकार को 1.33 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करना है। दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियां पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रही हैं।

वित्त वर्ष 2019 में उनका सकल घाटा 1.4 लाख करोड़ रुपये और ऋण 4.9 लाख करोड़ रुपये था। इससे बैंक इन कंपनियों की कर्ज चुकाने की क्षमता से चिंतित हैं। पहले ही कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं या उनका मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट में चल रहा है। यही वजह है कि उनके लिए कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया है।

वित्त सचिव राजीव कुमार ने शनिवार को कहा कि आरबीआई की ताजा रिपोर्ट उसकी पिछली रिपोर्ट से मेल नहीं खाती है। कुछ दिन पहले आई रिपोर्ट में कहा गया था कि एनपीए घट रहा है। उन्होंने कहा कि आपको दबावग्रस्त परिसंपत्तियों और कुल परिसंपत्तियों का अनुपात देखना चाहिए जिसमें उल्लेखनीय कमी आई है।

अगले साल जीडीपी रहेगी 6.5 प्रतिशत!

अरूप रॉयचौधरी
नई दिल्ली, 29 दिसंबर

आगामी बजट की तैयारियों के बीच नरेंद्र मोदी सरकार अगले वित्त वर्ष के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दर 6.0 से 6.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद कर रही है। सरकार मोटे तौर पर यह भी मान कर चल रही है कि देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में 4 प्रतिशत तक बदलाव हो सकता है। इस तरह, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश का नॉमिनल जीडीपी 10 प्रतिशत के इर्द-गिर्द या इससे थोड़ा ऊपर रह सकता है। वित्त मंत्रालय नॉमिनल जीडीपी के आधार पर अगले वर्ष के लिए बजट में निर्धारित लक्ष्यों जैसे राजकोषीय घाटे और राजस्व वृद्धि दर का अनुमान तय करता है। देश की अर्थव्यवस्था सुस्त होने के बीच सरकार इससे निपटने के उपाय खोज रही है, इसलिए इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए आगामी बजट बेहद महत्त्वपूर्ण है। बजट की तैयारियों पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,'हम अगले वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 6.0-6.50 प्रतिशत रहने की उम्मीद कर रहे हैं।

बेहतर की उम्मीद!

- वित्त वर्ष **2020-21** में वस्तु एवं सेवा कीमतों में **4** प्रतिशत बदलाव का अनुमान
- वित्त वर्ष **2020** के लिए आर्थिक समीक्षा में वास्तविक जीडीपी दर **7** प्रतिशत रहने का था अनुमान
- सरकार को अब वित्त वर्ष में जीडीपी दर **5** प्रतिशत रहने की उम्मीद

अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं और अगले वर्ष मांग में तेजी और इस वर्ष के कम आधार के कारण अगले वर्ष सभी संकेतक बेहतर रहेंगे।' हालांकि अधिकारी ने यह स्वीकार किया कि परिस्थितियां सभी तरह से बेहतर रहने पर ही इस अनुमान का ऊपरी दायरा हासिल हो सकता है। वास्तविक जीडीपी को लेकर वित्त मंत्रालय का आधिकारिक अनुमान आर्थिक समीक्षा में प्राय: एक दायरे के रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी दर 'बजट एक नजर में' में एक आंकड़े के रूप में दिया जाती है। वर्ष 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने एक संख्या का जिक्र किया था। उन्होंने 2019-20 में जीडीपी दर करीब 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। 2019-20 के बजट में नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 12 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। यह अनुमान कुछ अधिक ही आशवादी साबित हुआ या दूसरे शब्दों में कहें तो वास्तविकता से दूर था।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) चालू वित्त वर्ष में अब जीडीपी वृद्धि दर 5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगा रहा है, जबकि पहले उसने यह आंकड़ा 6.1 प्रतिशत रहने की बात कही थी। वैसे सार्वजनिक रूप से वित्त वर्ष ने संशोधित अनुमान पेश नहीं किया है, लेकिन अधिकारियों के अनुसार आंकड़े आरबीआई के अनुसार ही रहेंगे। एक दूसरे वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हम आरबीआई के आंकड़ों को ही मान रहे हैं। अब हम भी अपने स्तर पर जीडीपी दर 5 प्रतिशत रहने की बात करने लगे हैं।' जुलाई-सितंबर में वास्तविक जीडीपी दर 4.5 प्रतिशत रही, जो पिछली 26 तिमाहियों का सबसे खराब आंकड़ा रहा। नॉमिनल जीडीपी दर महज 6 प्रतिशत थी। 2019-20 की अक्टूबर-मार्च अवधि के लिए आरबीआई अब वास्तविक जीडीपी दर 4.9 से 5.5 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में 5.9 से 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त कर रहा है।

दवा मार्जिन की सीमा धीरे-धीरे होगी तय

सोहिनी दास
मुंबई, 29 दिसंबर

सरकार चरणबद्ध तरीके से दवाओं के कारोबारी मार्जिन की सीमा तय करने पर विचार कर रही है। पहले इसे 45 फीसदी और फिर 30 फीसदी किया जा सकता है। एक बार में एक श्रेणी की दवा पर यह सीमा तय की जा सकती है।

सूत्रों के मुताबिक सिप्ला और अल्केम जैसी प्रमुख दवा कंपनियों ने 30 फीसदी मूल्य नियंत्रण से बाहर की दवाओं पर कारोबारी मार्जिन तय करने के सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन कंपनियों का बिना ब्रांड वाली जेनेरिक दवाओं का अच्छा खासा कारोबार है। ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं का मार्जिन कारोबार द्वारा तय है, लेकिन बिना ब्रांड वाली जेनेरिक दवाओं के मामले में मार्जिन अलग-अलग है। इस बारे में सिप्ला को भेजे गए ईमेल का तुरंत कोई जवाब नहीं आया जबकि अल्केम से प्रतिक्रिया के लिए संपर्क नहीं हो पाया।

- दवाओं के कारोबार में मार्जिन की सीमा को चरणबद्ध तरीके से तय करने पर विचार
- पहले इसे 45 फीसदी और फिर 30 फीसदी किया जा सकता है
- दवा उद्योग ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दी
- उद्योग का इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का अनुरोध

इस बारे में सरकार के साथ चल रही चर्चा में शामिल दवा उद्योग एक सूत्र ने कहा, 'सिप्ला और अल्केम जैसी कंपनियां आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में शामिल दवाओं के इतर सभी दवाओं का कारोबारी मार्जिन तय करने के सरकार के फैसले के खिलाफ हैं। इस सूची में शामिल दवाओं पर 30 फीसदी कारोबारी मार्जिन तय है। इन कंपनियों का जेनेरिक दवाओं का अच्छा खासा कारोबार है और अगर मार्जिन की सीमा तय की जाती है तो उन्हें इसका नुकसान होगा।' उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार के साथ चर्चा जारी है और दवा उद्योग कारोबारी मार्जिन को व्यावहारिक बनाने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है। सरकार ने इस बार में अक्टूबर और नवंबर में दवा उद्योग के साथ बैठक की थी।

उद्योग के कई सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि कारोबारी मार्जिन की सीमा को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए बातचीत चल रही है। पहले इसे 45 फीसदी किया जा सकता है और अंत में इसे 30 फीसदी निर्धारित किया जा सकता है। मुंबई की एक कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'इस एक बार में एक या दो श्रेणियों पर लागू करने की योजना है। उदाहरण के लिए सबसे पहले एंटीबायोटिक्स श्रेणी में इसे लागू किया जा सकता है।' एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि दवाओं का कारोबारी मार्जिन की सीमा तय करने की योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने योजना पर विचार किया जा रहा है। कारोबारी मार्जिन बिक्री के पहले बिंदु और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के बीच अंतर होता है।

अधिसूचित उत्पादों के लिए कारोबारी मार्जिन स्टॉकिस्ट के लिए 8 फीसदी और रिटेलर के लिए 16 फीसदी है। गैर अधिसूचित उत्पादों के लिए यह क्रमश: 10 फीसदी और 20 फीसदी है। अभी दवा मूल्य नियामक राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) अधिसूचित दवाओं की कीमत तय करता है जबकि गैर अधिसूचित दवाओं की कीमत हर साल 10 फीसदी बढ़ाने की अनुमति है। अभी 1.3 लाख करोड़ रुपये के घरेलू दवा बाजार में करीब 19 फीसदी दवाएं मूल्य नियंत्रण के दायरे में हैं। ■ शेष पृष्ठ 4

सुस्त कारोबार, सीलिंग से जूझते रहे कारोबारी

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 29 दिसंबर

दिल्ली के उद्यमी इस साल प्रदूषण, सीलिंग व आर्थिक सुस्ती की मार से जूझते रहे। बढ़ते प्रदूषण के कारण औद्योगिक इकाइयों से भारी प्रदूषण हर्जाना वसूलने के साथ रिहायशी इलाकों में अवैध फैक्टरियों पर सीलिंग लागू की गई। आर्थिक सुस्ती के कारण कारोबारियों को अच्छे सौदे हाथ नहीं लगे। हालांकि डीडीए ने इस साल जिम, योग केंद्र, कुछ रेस्तरां को राहत देने के साथ ही घरेलू उद्योगों की नई परिभाषा को मंजूरी दी और कुछ सेवा क्षेत्रों को उद्योगों का दर्जा भी दिया। हालांकि इसकी अधिसूचना जारी नहीं होने से इस साल इसका लाभ नहीं मिल सका।

- प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर जुर्माना
- सीलिंग की समस्या दूर होने की आस अधूरी
- जिम, योग, कुछ रेस्तरां व सेवा क्षेत्रों को मिली राहत

दिल्ली की हवा खराब होने की गाज औद्योगिक इकाइयों पर पड़ी। इस साल प्रदूषण हर्जाने के तौर पर 16 से 18 करोड रुपये वसूलने के निर्देश दिए गए। यह राशि पिछले साल की तुलना में दोगुनी है। पटपड़गंज आंत्रप्रेन्यौर एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक संजय गौड़ ने कहा कि प्रदूषण हर्जाने का नया फॉर्मूला लागू होने से इस साल प्रदूषण फैलाने वाले उद्यमियों पर जुर्माना लगाया गया।

उद्यमियों के लिए राहत की बात ये रही है कि डीडीए ने कुछ सेवा क्षेत्रों को उद्योग का दर्जा दे दिया। बवाना चैंबर आफ इंडस्टीज के चेयरमैन प्रकाशचंद जैन ने कहा कि प्रदूषण की सबसे ज्यादा मार बवाना के उद्यमियों पर पड़ी। दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बवेजा ने कहा कि इस साल कारोबारियों को सीलिंग की समस्या दूर होने की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हो सकी।

दशक के बदलाव छोड़ेंगे सदी पर असर

प्रांजल शर्मा
नई दिल्ली,
29 दिसंबर

दशक में बदला परिदृश्य

एक दशक पहले तक तकनीक हमारे जीवन का एक हिस्सा थी और अब यह हमारी जिंदगी बन गई है। बीता दशक इस बात के लिए याद किया जाएगा कि तकनीक ने हमारी जिंदगी को किस प्रकार बदल दिया और हम किस हद तक तकनीक का और अधिक उपयोग करने लगे।

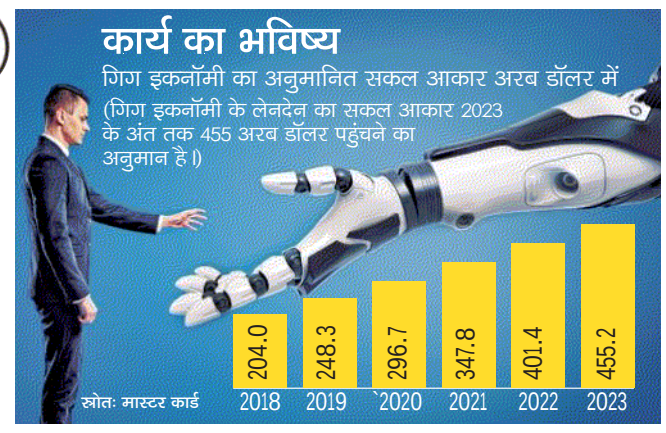

वर्ष 2010 से पहले इंटरनेट और मोबाइल केवल जरूरत पड़ने पर उपयोग में लाए जाते थे। वे ऑनलाइन खोज तथा कनेक्टिविटी के लिए उपकरण मात्र थे। आज हम इन पर पूरी तरह निर्भर हो गए हैं। ऑफिस का काम, आराम, रिश्ते, यात्रा और कारोबार, आदि सभी तकनीक से प्रभावित हो रहे हैं। पहले तकनीक ने सब कुछ आसान किया और आज तकनीक ही इस सब को चला रही है। पिछले दशक तक कांच का अर्थ वही था जो दशकों से समझा जाता रहा लेकिन अब कांच की एक परत को छूते ही हमारा सभी के साथ संपर्क हो जाता है। एक टचस्क्रीन ने हमारे जीवन का खाका बदल दिया है। इसने हमें भाषायी सीमा के पार जाकर काम करने में मदद की है। साल 2007 में आए टच स्क्रीन आईफोन के बाद दूसरी मोबाइल कंपनियों ने भी इसका अनुसरण शुरू कर दिया। वर्ष 2010 के बाद से टचस्क्रीन उपकरण काफी लोकप्रिय हो चुके थे। पिछले एक दशक में टचस्क्रीन तकनीकी बदलाव का परिचायक रहा है। विभिन्न तकनीकों के समूह ने ग्राहकों के व्यवहार और कारोबारी मॉडल को पूरी तरह बदल दिया है।

क्लाउड तकनीक, एआई

वीडियो स्ट्रीमिंग से लेकर कारोबार के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), सब कुछ क्लाउड पर सहेजा और चलाया जा रहा हैं। व्यक्तिगत तथा कारोबारी कंप्यूटिंग प्रक्रिया अब दूर स्थित सर्वर से आसानी से पूरी की जा सकती है। इसके चलते कंप्यूटिंग उपकरणों का संवर्धन हुआ और ऐप आधारित अर्थव्यवस्था का उभार हुआ। फ्लॉपी या सीडी डिस्क पर सॉफ्टवेयर अपग्रेड खरीदने वाला समय बदल गया अब एक क्लिक में अपग्रेड उपलब्ध है। सेहत का ध्यान रखने वाले और पहनने योग्य उपकरण आ चुके हैं और आपसे बात करने के लिए वर्चुअल असिस्टेंस मौजूद है। ऑनलाइन खोज भी कीबोर्ड से हटकर केवल बोलने तक सीमित होती जा रही है।

इस सब चमत्कार के पीछे कृत्रिम मेधा (एआई) तकनीक का हाथ है जो ग्राहक की जरूरत का आंदाजा लगा लेती है। स्वचालन तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्लाइड कंप्यूटिंग तथा एआई के साथ जोड़ दिए गए हैं। संसार वायरस सुरक्षा के बाद अब साइबर सुरक्षा की ओर बढ़ रहा है। ■ शेष पृष्ठ 12

संक्षेप में

मुश्किल में रहा वाहन कलपुर्जा उद्योग

वाहन कलपुर्जा उद्योग को मौजूदा वित्त वर्ष नकारात्मकता के साथ समाप्त होने की संभावना है क्योंकि दूसरी छमाही में पहली छमाही की भरपाई मुश्किल है। यह जानकारी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जैन ने दी। एक्मा को यह भी संभावना लग रहा है कि अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगी। एक्मा को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रहेगी। जैन ने कहा, हमारा अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष की रफ्तार नकारात्मक रहेगी क्योंकि अप्रैल-सितंबर में हम (-)10 फीसदी की रफ्तार पहले ही देख चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इसकी भरपाई मुमकिन है। वाहन कलपुर्जा उद्योग का टर्नओवर अप्रैल-सितंबर में घटकर 1.79 लाख करोड़ रहा जो एक साल पहले के 1.99 लाख करोड़ के मुकाबले 10.1 फीसदी कम है। *एजेंसियां*

देसी कंपनियों ने बाजार से जुटाए 8.7 लाख करोड़ रु.

भारतीय कंपनियों के लिये कोष जुटाने के लिहाज से यह साल अच्छा रहा। कंपनियों ने 2019 में घरेलू और विदेशी बाजारों से 8.7 लाख करोड़ रुपये जुटाये। पिछले साल के मुकाबले यह 20 फीसदी अधिक रहा है। वर्ष के दौरान कारोबार से जुड़े कार्यों के लिये वित्त जुटाने के मामले में बॉन्ड से धन जुटाना सबसे पसंदीदा जरिया रहा। जियोजित फाइनैंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा कि वर्ष 2020 में कोष जुटाने का परिदृश्य बाजार की स्थिति, आर्थिक वृद्धि, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और केंद्रीय बजट में किये जाने वाले उपायों पर निर्भर करेगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में इक्विटी पूंजी बाजार के सह-प्रमुख गौरव सूद ने कहा कि नये साल में भी बॉन्ड बाजारों के लिये अच्छी मांग की उम्मीद है। *भाषा*

कम मांग से एनबीएफसी में सुस्ती

विश्लेषण से पता चलता है कि फंडिंग पर रोक इसलिए थी क्योंकि बाजार अच्छी और खराब इकाइयों के बीच विभेद कर रहा है

सोमेश झा
नई दिल्ली, 29 दिसंबर

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में सुस्ती की मुख्य वजह अर्थव्यवस्था में घटती मांग और बाजार की फंडिंग की अनुपलब्धता रही है। यह जानकारी आईएलऐंडएफएस संकट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से हुए हालिया विश्लेषण से मिली।

आरबीआई के निगरानी विभाग की तरफ से किए गए आंतरिक विश्लेषण से पता चलता है कि बाजार और बैंकों की तरफ से एनबीएफसी को फंडों की अनुलपब्धता हर किसी के लिए नहीं थी और बाजार अच्छी व खराब इकाइयों के बीच विभेद कर रहा है।

एनबीएफसी पर मुख्य रूप से दो वजहों से दबाव है : रियल एस्टेट क्षेत्र में संकट और परिसंपत्ति-देनदारी का बेमेल।

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को अलग से आधिकारिक आंकड़ा पेश किया है, जो इस पर जोर देने के लिए है कि एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों के बीच सुधार हो रहा है और अब ये स्थिर हो रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल होने के बाद वित्त सचिव राजीव कुमार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बाजार बेहतर प्रबंधित और थोड़ी कम बेहतर प्रबंधित कंपनियों के बीच स्पष्ट रूप से विभेद कर रहा है। हर कोई अब सामान्यता की ओर बढ़ रहा है।

एनबीएफसी-एचएफसी का विश्लेषण

- एनबीएफसी पर मुख्य रूप से दो वजहों से दबाव है : रियल एस्टेट क्षेत्र में संकट और परिसंपत्ति-देनदारी में गड़बड़ी
- एनबीएफसी को बैंकों की उधारी सितंबर 2018 और सितंबर 2019 के बीच 17.5 फीसदी बढ़ी है
- इनमें से 107 बड़ी एनबीएफसी को (जिनकी बाजार हिस्सेदारी करीब 67 फीसदी है) उधारी 31 फीसदी बढ़ी है
- एनबीएफसी को बाजार से मिलने वाला वित्त इस अवधि में 4.2 फीसदी बढ़ा है, जो पिछले साल की समान अवधि में करीब 30 फीसदी की रफ्तार से बढ़ा था

मजबूत एनबीएफसी के बीच नकदी संकट मुख्य रूप से बाजार की प्रतिभूतियों से वित्तीय सहारा न मिलने के कारण है, न कि लेनदारों की तरफ से। नियामकीय आंकड़े बताते हैं कि एनबीएफसी को बैंकों की उधारी सितंबर 2018 और सितंबर 2019 के बीच 17.5 फीसदी बढ़ी है। इनमें से 107 बड़ी एनबीएफसी को (जिनकी बाजार हिस्सेदारी करीब 67 फीसदी है) उधारी 31 फीसदी बढ़ी है। हालांकि एनबीएफसी को बाजार से मिलने वाला वित्त इस अवधि में 4.2 फीसदी बढ़ा है, जो पिछले साल की समान अवधि में करीब 30 फीसदी की रफ्तार से बढ़ा था।

इस विश्लेषण से पता चलता है कि अच्छी एनबीएफसी या एचएफसी बाजार से आईएलऐंडएफएस अवधि (अगस्त 2018) से पहले की उधारी दर पर रकम जुटाने में सक्षम हैं।

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को प्रेस को दिए बयान में कहा था, आईएलऐंडएफएस के डिफॉल्ट के बाद एनबीएफसी की परिसंपत्तियां 12.8 फीसदी बढ़कर 28.3 लाख करोड़ रुपये से 31.9 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जिससे सरकाकर से काफी सहारा मिला। 81 फीसदी बाजार हिस्सेदारी वाली 211 बड़ी एनबीएफसी की परिसंपत्तियां 19.7 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी है।

एचएफसी की बात करें तो विश्लेषण बताता है कि कुछ फर्मों से दबाव दूर रहा। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि अगस्त 2018 में आईएलऐंडएफएस संकट सामने आने के बाद 82 फीसदी बाजार हिस्सेदारी वाली 101 एचएफसी में से 76 ने परिसंपत्ति में 18 फीसदी की सकारात्मक बढ़ोतरी दर्ज की और यह सितंबर 2018 के 8.45 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर नवंबर 2019 में 10 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

एचएफसी पर हालांकि कुछ असर मुख्य रूप से नौ बड़ी एचएफसी से पड़ा, जिनकी परिसंपत्ति का आकार सितंबर 2018 के 2.94 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 26 फीसदी घटकर नवंबर 2019 में 2.17 लाख करोड़ रुपये रह गई। भारत में कुल 101 एचएफसी हैं, जिसमें से सात ने परिचालन का लाइसेंस मिलने के बाद कारोबार शुरू नहीं किया है। परिचालन वाली 94 एचएफसी में से 76 को बैंकों, एनएचबी और बाजार से ज्यादा वित्तीय सहारा मिला है, वहीं 18 अग्रणी एचएफसी को उधारी सितंबर 2018 से नवंबर 2019 के बीच 65,595 करोड़ रुपये घटी है।

शेयर कीमतों से डिफॉल्ट की संभावना की तलाश

जश कृपलानी
मुंबई, 29 दिसंबर

- आरबीआई की वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में कहा गया है कि तात्कालिक रेटिंग कार्रवाई के लिए इक्विटी कीमतों का इस्तेमाल किया जा सकता है
- लेकिन इसके इस्तेमाल की सीमा को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी

भारतीय रिजर्व बैंक ने दबाव वाली कंपनी के संभावित डिफॉल्ट के शुरुआती संकेत की खातिर इक्विटी कीमतों की चाल का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव किया है। केंद्रीय बैंक की वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में कहा गया है, बॉन्ड के मूल्यांकन के लिए इक्विटी की चाल शायद प्रासंगिक नहीं भी हो सकती है क्योंकि दावे के पदानुक्रम के लिहाज से बॉन्ड ऊपर है, लेकिन वह दबाव का शुरुआती संकेत दे सकता है।

प्रमुख निवेश कंपनी की चूक करने वाली सहायक का मामला सामने रखते हुए आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि सहायक कंपनी को डिफॉल्ट के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के बाद भी इक्विटी कीमतें सुदृढ़ नजर आईं।

रिपोर्ट में कहा गया है, इक्विटी कीमतों का इस्तेमाल रेटिंग की तात्कालिक कार्रवाई में भी किया जा सकता है, लेकिन केंद्रीय बैंक का यह भी कहना है कि ऐसे मकसद के लिए इसका किस हद तक इस्तेमाल किया जाए, उसके लेकर हमें सतर्कता बरतने की दरकार है।

रिपोर्ट के मुताबिक, चेतावनी के शुरुआती संकेत के तौर पर इक्विटी कीमतों का विश्लेषण सिर्फ डिफॉल्ट की संभावना तलाशता है, लेकिन यह रेटिंग की तात्कालिक कार्रवाई में मददगार हो सकता है। ऐसा तरीका हालांकि आलोचना से बाहर नहीं है क्योंकि ऐसी रेटिंग के आधार पर पोर्टफोलियो का समायोजन गलत संकेत देगा और यह प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा होगी।

हालांकि डेट मार्केट की इलिक्विड प्रकृति को देखते हुए रिपोर्ट में दलील दी गई है कि सक्रिय इक्विटी कीमत रेटिंग एजेंसियों समेत सभी हितधारकों के लिए सूचना के एकमात्र स्रोत के तौर पर उभर सकता है।

बाजार के प्रतिभागियों के मुताबिक, रेटिंग एजेंसियों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहां वे और संकेत सामने रख सकें ताकि निवेशक रेटिंग में हु अचानक बदलाव के कारण न फंस सके, जैसा कि हालिया डेट मार्केट के संकट में देखा गया था।

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में आरकैप की 100 फीसदी हिस्सेदारी बहाल

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 29 दिसंबर

बीमा नियामक आईआरडीएआई ने ट्रस्टी की तरफ से रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के गिरवी रखे गए शेयरों को भुनाने और उनके हस्तांतरण को रद्द कर दिया है। रिलायंस कैपिटल ने स्टॉक एक्सचेंज यह जानकारी दी। इससे पहले 19 नवंबर को रिलायंस कैपिटल ने ऐलान किया था कि ट्रस्टी की तरफ से गिरवी शेयर भुनाने के बाद पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी में उसकी शेयरधारिता आईडीबीआई ट्रस्टी सर्विसेज को हस्तांतरित कर दी गई है।

फोकस्ड स्कीम पर सतर्कता बरतने की सलाह

जश कृपलानी
मुंबई, 29 दिसंबर

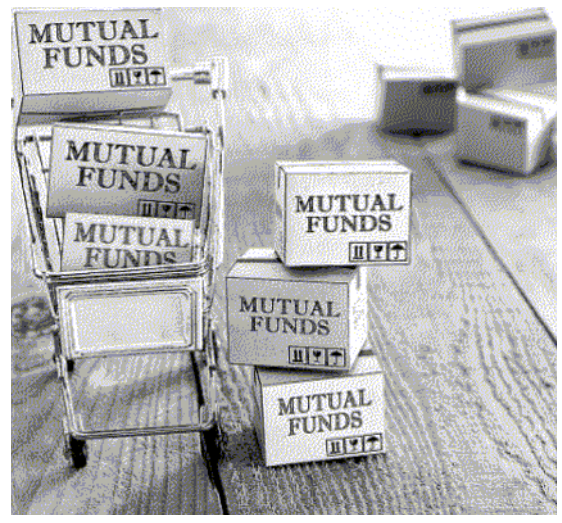

- एक साल में फोकस्ड योजनाओं ने 13 फीसदी रिटर्न दिया है और इस तरह से यह लार्जकैप योजनाओं की श्रेणी के रिटर्न को पीछे छोड़ दिया है
- फोकस्ड फंडों ने मौजूदा वित्त वर्ष में निवेशकों से करीब 6,000 करोड़ रुपये हासिल किए हैं
- ये योजनाओं तभी फायदा दे सकती हैं जब पोर्टफोलियो के कुछ शेयरों में तेज बढ़ोतरी हो
- मौजूदा वित्त वर्ष में फोकस्ड योजनाओं ने म्युचुअल फंड उद्योग को मिले कुल इक्विटी निवेश का करीब 12 फीसदी हासिल किया है

हाल के महीनों में मजबूत रिटर्न देने वाले फोकस्ड फंडों ने मौजूदा वित्त वर्ष में निवेशकों से करीब 6,000 करोड़ रुपये हासिल किए हैं, लेकिन म्युचुअल फंड के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि निवेशक इसमें बड़ी रकम न लगाएं क्योंकि ऐसी योजनाओं के साथ संकेंद्रित दांव का जोखिम रहता है।

एक साल में फोकस्ड योजनाओं ने 13 फीसदी रिटर्न दिया है और इस तरह से यह लार्जकैप योजनाओं की श्रेणी के रिटर्न को पीछे छोड़ दिया है, जिसने इस अवधि में 11.6 फीसदी का रिटर्न दिया है।

प्राइमइन्वेस्टर डॉट इन की सह-संस्थापक विद्या बाला ने कहा, फोकस्ड योजनाओं पर विचार करते समय निवेशकों को निश्चित तौर पर सावधान रहना चाहिए। ये योजनाओं तभी फायदा दे सकती हैं जब पोर्टफोलियो के कुछ शेयरों में तेज बढ़ोतरी हो, लेकिन इसके साथ गिरावट का भी जोखिम है अगर एक या दो बड़े संकेंद्रित दांव में गिरावट देखने को मिले। मौजूदा वित्त वर्ष में फोकस्ड योजनाओं ने म्युचुअल फंड उद्योग को मिले कुल इक्विटी निवेश का करीब 12 फीसदी हासिल किया है। विशेषज्ञों ने कहा, इसकी वजह यह है कि इन फंडों ने हाल में बेहतर प्रदर्शन किया है क्योंकि इन योजनाओं को कुछ मिडकैप निवेश में मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक फंड हाउस के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा, यह जोखिम वाली योजना है और निवेशकों को ऐसे फंडों की तरफ से देखना चाहिए जो ज्यादा विशाखन की पेशकश करे। फोकस्ड फंड को सुनियोजित निवेश के तौर पर देखना चाहिए, जो कुल इक्विटी निवेश में कुछ बढ़त दे सकता है।

सेबी के नियमों के मुताबिक, किसी फोकस्ड योजना के पोर्टफोलियो में एक समय में 30 से ज्यादा शेयर नहीं हो सकते। इस योजना में निवेशकों की दिलचस्पी को देखते हुए छोटे आकार वाले कुछ फंड हाउस ऐसी योजना पेश करने पर विचार कर रहे हैं।

हालांकि सलाहकारों ने कहा है कि निवेशकों को यह निश्चित तौर पर देखना चाहिए कि क्या फंड मैनेजर का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड फोकस्ड फंड में अच्छा प्रदर्शन करने वालों के तौर पर है। यह सही शेयर चुनने की फंड मैनेजर की काबिलियत के साथ जुड़ा है।

विशेषज्ञों ने कहा कि फोकस्ड फंड के हाल में रुझान बढ़ा है क्योंकि निवेशकों ने कुछ नए निवेश गंतव्य पाए हैं जहां बेंचमार्क सूचकांकों के मुकाबले बेहतर रिटर्न मिले हैं। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, सक्रियता से प्रबंधित आधी योजनाएं साल 2019 में बेंचमार्क सूचकांकों को पीछे छोड़ने में नाकाम रही हैं।

स्मॉलकैप व मिडकैप में निवेशकों ने चुनौतीपूर्ण समय देखा है। मिडकैप योजनाओं में एक साल का रिटर्न तीन फीसदी के आसपास रहा है, वहीं स्मॉलकैप योजनाओं ने इस अवधि में करीब दो फीसदी का नकारात्मक रिटर्न दिया है।

इस बीच, लार्जकैप योजनाओं को बाजार के ध्रुवीकरण से फायदा मिला है क्योंकि निफ्टी के पांच अग्रणी बढ़त वाले शेयरों ने इनमें 46 फीसदी का योगदान किया है, जिसकी वजह सितंबर में हुई कंपनी कर में कटौती है।

बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि अगले साल भी ध्रुवीकरण जारी रह सकता है क्योंकि बाजार के विभिन्न हिस्सों में बढ़त को लेकर अनिश्चितता है। म्युचुअल फंड के सलाहकारों ने कहा कि इस वजह से लार्जकैप फोकस्ड फंडों में बढ़त जारी रह सकती है।

कॉफी डे को टेक पार्क सौदा पूरा होने की उम्मीद

देवाशिष महापात्र और विभु रंजन मिश्रा
बेंगलूरु, 29 दिसंबर

- येस बैंक ने हालांकि ग्लोबल टेक पार्क सौदे पर अभी मंजूरी नहीं दी है, लेकिन अगले 10 दिन में यह मंजूरी मिल सकती है

कॉफी डे एंटरप्राइजेज को उम्मीद है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में कार्यशील पूंजी की स्थिति में सुधार हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि कंपनी को इस अवधि में ग्लोबल टेक पार्क की बिक्री से रकम मिलने की संभावना है। इसके अलावा कंपनी को वित्तीय संस्थानों से कर्ज मिलने की भी उम्मीद है।

एक सूत्र ने कहा, येस बैंक ने हालांकि ग्लोबल टेक पार्क सौदे पर अभी मंजूरी नहीं दी है, लेकिन अगले 10 दिन में यह मंजूरी मिल सकती है। सूत्र ने कहा, वी जी सिद्धार्थ की मौत के बाद पिछले पांच महीने में कंपनी को बैंक से एक पैसा नहीं मिला है। अगल ब्लैकस्टोन का सौदा आगे बढ़ता है (जिसके बारे में कंपनी का मानना है कि यह जनवरी के दूसरे हफ्ते में हो जाएगा) तो चीजें सुधरेंगी। उन्होंने कहा, कंपनी अपने लेनदारों को पूरा भुगतान करेगी।

सितंबर में कॉफी डे एंटरप्राइजेज ने ग्लोबल विलेज टेक पार्क प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन और रियल्टी फर्म सलारपुरिया सत्व ग्रुप को 2,700 करोड़ रुपये में बेचने का फैसला लिया था।

सूत्र ने कहा, कार्यशील पूंजी की किल्लत के बावजूद कंपनी की सभी कैफे व वेंडिंग मशीन बिना किसी अवरोध के चल रहे हैं। हालांकि उसकी कुछ सहायक कंपनियां नकदी प्रवाह के बेमेल के कारण कर्ज नहीं चुका पाई हैं। कॉफी डे एंटरप्राइजेज की एक सूचीबद्ध सहायक सिकल लॉजिस्टिक्स ने गुरुवार को एक्सचेंजों को सूचित किया था कि गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र पर अर्धवार्षिक ब्याज 5.5 करोड़ रुपये के भुगतान में देर होगी। सितंबर तिमाही में भी फर्म 10.72 करोड़ रुपये ब्याज लेनदारों को नहीं चुका पाई थी।

उन्होंने कहा, विनिवेश पर बातचीत हालांकि चल रही है, लेकिन इसके साथ ही सिकल कुछ कर्ज जुटाने की कोशिश में है, जिससे कार्यशील पूंजी की दिक्कत में कमी आएगी।

इस बीच, कॉफी डे एंटरप्राइजेज को समूह के दिवंगत संस्थापक वी जी सिद्धार्थ की चिट्ठी पर जांच रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जिसे अगले महीने बोर्ड के सामने रखा जाएगा। अगस्त में समूह ने सीबीआई के पूर्व डीआईजी अशोक कुमार मल्होत्रा और लॉ फर्म अगस्त्य लीगल एलएलपी को इस पत्र की जांच का काम सौंपा था, साथ ही उन्हें बही-खाते की जांच का काम भी दिया गया था। जुलाई के आखिर में समूह का कर्ज 4,970 करोड़ रुपये था, जिसमें टैंगलिन डेवलपमेंट की देनदारी 1,622 करोड़ रुपये थी। इसकी मूल कंपनी कॉफी रिटेलिंग इकाई कॉफी डे ग्लोबल का कुल कर्ज 1,097 करोड़ रुपये था।

इस साल हीरा आयात में आई गिरावट

अप्रैल-नवंबर में अपरिष्कृत हीरे का सकल आयात 17.24 प्रतिशत घटकर 8.55 अरब डॉलर रहा

विनय उमरजी
अहमदाबाद, 29 दिसंबर

बैंकों द्वारा ऋण वितरण में कमी किए जाने से पैदा हुए नकदी संकट से हीरा तराशी और कटाई-छटाई से जुड़े व्यवसायियों ने खरीदारी में कटौती की जिससे भारत में 2019 में अब तक अपरिष्कृत हीरे के शुद्ध आयात में भारी गिरावट दर्ज की गई है। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से नवंबर 2019 के बीच अपरिष्कृत हीरे का सकल आयात अप्रैल-नवंबर 2018 के 10.34 अरब डॉलर के मुकाबले 17.24 प्रतिशत घटकर 8.55 अरब डॉलर रह गया। यह पिछले एक दशक में भारत में हीरे के आयात में सबसे बड़ी गिरावट में से एक है। बेन ऐंड कंसल्टिंग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, शुद्ध आयात में 32 प्रतिशत तक की कमी आई है।

दूसरी तरफ, कटे और तराशे हुए हीरे (सीपीडी) का निर्यात अप्रैल से नवंबर 2019 के बीच 18.96 प्रतिशत तक घटकर 13.41 अरब डॉलर रह गया, जो अप्रैल से नवंबर 2018 के दौरान 16.55 अरब डॉलर था। अकेले नवंबर 2019 में, भारत से सीपीडी निर्यात 25.18 प्रतिशत तक घटकर 1.66 अरब डॉलर पर रहा जो नवंबर 2018 में 1.56 अरब डॉलर था।

हीरे का निर्यात

- कटे और तराशे हुए हीरों का निर्यात अप्रैल-नवंबर के बीच 18.96 प्रतिशत तक घटकर 13.41 अरब डॉलर रहा
- अप्रैल-नवंबर 2018 में यह दौरान 16.55 अरब डॉलर था
- नवंबर में तराशे हुए हीरों का निर्यात 25.18 फीसदी घटकर 1.66 अरब डॉलर रहा

वैश्विक हीरा उद्योग पर बेन ऐंड कंसल्टिंग की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में कमजोर स्थानीय मुद्रा, बैंकों द्वारा ऋण वितरण में कमी किए जाने से पैदा हुए नकदी संकट, और नोटबंदी के प्रभाव से भारत में आगामी माल के भंडारण को बढ़ावा मिला। रिपोर्ट में कहा गया है, '2017 तथा 2018 में तराशे हुए हीरे की कमजोर बिक्री और अत्यधिक इन्वेंट्री के समावेश के साथ 2018 और 2019 में शुद्ध आयात में 3 और 30 प्रतिशत तक की कमी आई। भारत ने इस संदर्भ में भारी गिरावट दर्ज की।'

पूर्ववर्ती वर्ष के मुकाबले चीन द्वारा अपरिष्कृत हीरे के शुद्ध आयात में अनुमानित 5 प्रतिशत गिरावट के विपरीत, भारत में इसके शुद्ध आयात में 2018 में 3 प्रतिशत और 2019 के पहले 8 महीनों में 42 प्रतिशत की कमी आई। फिर भी, चीन के 5 प्रतिशत और शेष दुनिया के 5 प्रतिशत योगदान की तुलना में वैश्विक रूप से अपरिष्कृत हीरे के 90 प्रतिशत आयात के साथ भारत का हीरे की कटाई एवं तराशी के उद्योग में दबदबा बना हुआ है। इसके विपरीत, भारत का शुद्ध अपरिष्कृत हीरा आयात 2016-17 में उससे पहले के वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत तक घटा। इस गिरावट के लिए भारतीय बैंकों द्वारा अपनाया गया सतर्क रुख भी काफी हद तक जिम्मेदार है। भारतीय वित्त क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन और चुनौतियों के बाद बैंकों ने ऋण वितरण को लेकर काफी हद तक सतर्क रुख अपनाया है। इस वजह से देश में हीरे की तराशी और कटाई में लगे व्यवसायियों ने पुराना माल निकालने और अपना नकदी प्रवाह सुधारने के लिए अपरिष्कृत हीरे की खरीदारी में लगभग 30 प्रतिशत तक की कमी की।

भारत में उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक रूप से मांग के अभाव की वजह से खनिकों और छटाई कारोबारियों ने अपरिष्कृत हीरे की अपनी बिक्री और खरीद को तर्कसंगत बनाया है। कटाई और तराशी से जुड़ा 94 प्रतिशत आयातित अपरिष्कृत हीरा भारत से निर्यात किया जाता है, जिससे कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था से मांग में गिरावट आई है और इसलिए भारत में इस धातु की कटाई और तराशी में लगे व्यवसायियों के लिए भी मार्जिन प्रभावित हुआ है।

भविष्य में, अल्पावधि चुनौतियों के बावजूद हीरा बाजार के लिए दीर्घावधि परिदृश्य मजबूत बना हुआ है। परिष्कृत हीरे के लिए मांग में सुधार आने की संभावना है और यह वर्ष 2030 तक या तो सपाट रहेगी या इसमें सालाना 3 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया जाएगा।

मार्जिन बढ़ाने के लिए गुणवत्ता पर जोर दे रहीं चाय कंपनियां

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 29 दिसंबर

लंबे समय तक मुनाफे पर दबाव झेलने के बाद चाय बागान कंपनियां फिर से गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें अपने मार्जिन में सुधार लाने के साथ साथ अपनी स्थिति मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

बागान कंपनियों के लिए कीमत प्राप्तियों की तुलना में बढ़ती उत्पादन लागत के साथ प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए गुणवत्ता एक प्रमुख बाधा रही है। पिछले 5-6 वर्षों में, जहां उत्पादन लागत लगभग 15 प्रतिशत तक बढ़ी है, वहीं कीमतों में सिर्फ 5-7 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ। उदाहरण के लिए, वर्ष 2013-14 के दौरान, वॉरेन टी ने 20.24 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था, जबकि 2018-19 के दौरान कंपनी को 15.92 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान हुआ। पिछले तीन वित्त वर्षों से वारेन टी को मुनाफा नहीं हुआ है। इसी तरह की स्थिति विलियमसन मेगर ग्रुप के स्वामित्व वाली मैकलॉयड रसेल की है, जिसने 2013-14 के दौरान 257.15 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया था, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में उसे 4.42 करोड़ रुपये के शुद्ध नुकसान का सामना करना पड़ा।

हालांकि मैकलॉयड के लिए, कीमतों के अलावा समूह की अन्य समस्याओं से भी उसकी बैलेंस शीट पर दबाव पड़ा जिससे कर्ज का बोझ बढ़कर लगभग 1,700 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

वहीं गुडरिक ने कैलेंडर वर्ष 2014 में 22.24 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जो 31 मार्च 2019 में समाप्त वित्त वर्ष के दौरान घटकर 9.49 करोड़ रुपये रह गया। 2013-14 के दौरान 20.40 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज करने वाली रोसेल इंडिया को भी पिछले वित्त वर्ष में महज 0.57 करोड़ रुपये के मुनाफे से संतोष करना पड़ा।

■ बेहतर गुणवत्ता वाली चाय की औसत कीमत 7-8 प्रतिशत तक बढ़ी है

गुणवत्ता पर फिर से ध्यान केंद्रित किए जाने से वारेन टी के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली चाय की कीमतें 3-5 प्रतिशत तक बढ़ी हैं, जबकि कमजोर गुणवत्ता की चाय की कीमतों में समान मात्रा में कमी आई है। गुडरिक के मामले में भी, असम चाय (उच्च क्वालिटी) की कीमतें 5 प्रतिशत तक बढ़ी हैं। गुणवत्ता सुधरने से गुडरिक, लक्ष्मी टी और एमके शाह एक्सपोर्ट्स ने असम में मैकलॉयड से बागानों की खरीदारी में दिलचस्पी दिखाई थी। गुडरिक ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अतुल अस्थाना ने कहा, 'चाय बागान अच्छी गुणवत्ता के हैं और हम इनमें लगभग 2-3 करोड़ रुपये का निवेश कर रहे हैं।' असम और अफ्रीका में मैकलॉयड से बागान खरीदने वाली लक्ष्मी टी के निदेशक रुद्र चटर्जी ने इसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, 'हमारे द्वारा खरीदे गए बागानों के लिए नीलामी कीमतों में सुधार आया है। औसत नीलामी कीमतें असम में मोरन क्षेत्र के चाय बागानों के लिए सर्वाधिक हैं और हम इसे बागानों को खरीदने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक अच्छे अवसर के तौर पर देख रहे हैं।'

चांदी दो सप्ताह में 8 फीसदी हुई महंगी

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 29 दिसंबर

चांदी के दाम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में आठ फीसदी बढ़े हैं। चीन में 25 जनवरी 2020 को नए वर्ष के जश्न से पहले चांदी की औद्योगिक मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे इस सफेद धातु की कीमतों में तेजी आई है। लंदन के हाजिर बाजार में चांदी के दाम बढ़कर 17.9 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गए हैं। इस तरह इसमें दो सप्ताह पहले के निचले स्तर की तुलना में करीब 8.2 फीसदी तेजी आई है।

मुंबई के जवेरी बाजार में चांदी 4 सितंबर को हाल की ऊंचाई 49,950 रुपये पर पहुंची थी। हालांकि इसके दाम हाजिर बाजार में 9 दिसंबर को गिरकर 43,225 रुपये पर आ गए थे। उसके बाद चांदी की कीमतें गुरुवार को फिर से चढ़कर 46,580 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं। घरेलू बाजार में चांदी की कीमतों में हलचल बेंचमार्क लंदन हाजिर बाजार के समान है। लंदन में चांदी 4 सितंबर को हाल के अपने सर्वोच्च स्तर 19.6 डॉलर प्रति औंस पर थी, जो छह दिसंबर को गिरकर 16.58 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

मुंबई की इक्विटी ऐंड जिंस ब्रोकिंग कंपनी केडिया स्टॉक ऐंड कमोडिटीज रिसर्च के निदेशक अजय केडिया ने कहा, 'आम तौर पर चीन के निवेशक नए वर्ष पर दो-तीन सप्ताह के अवकाश पर जाने से पहले अपना स्टॉक तैयार करते हैं। उनका मकसद यह होता है कि जब वे छुट्टियों से लौटकर फैक्टरियों को शुरू करें तो कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में हो। इसलिए औद्योगिक जिंसों की मांग में बढ़ोतरी से चांदी की कीमतें बढ़ी हैं। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी तनाव कम होने के संकेतों से औद्योगिक जिंसों को सहारा मिला है और इसलिए इससे चांदी भी अछूती नहीं रही है।' इस बीच सोने में भी तेजी आई है, लेकिन यह बहुत धीमी है।

तालाबंदी से कानपुर के चमड़ा निर्यात में 29 फीसदी की गिरावट

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 29 दिसंबर

कानपुर के चमड़ा कारखानों में करीब 13 महीने की तालाबंदी होने से तैयार चमड़े के निर्यात में कमी आई है। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त के दौरान चमड़ा निर्यात में करीब 29 फीसदी की कमी आई है। भारत ने अप्रैल-अगस्त 2018 के दौरान करीब 33.46 करोड़ डॉलर कीमत के तैयार चमड़े का निर्यात किया था जबकि चालू वित्त वर्ष की इसी अवधि में विदेश भेजे जाने वाली खेप 29 फीसदी कम होकर 23.77 करोड़ डॉलर रह गई है। चमड़े की अन्य श्रेणियों के निर्यात में भी कमी आ रही है।

देश के तैयार चमड़े में कानपुर की हिस्सेदारी करीब 30 फीसदी है। इस साल प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में गंगा के साफ बहाव के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन चमड़ा कारखानों को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया था। इससे इस उद्योग को जोरदार झटका लगा है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने कानपुर शहर में करीब 400 चमड़ा कारखानों को 15 दिसंबर, 2018 से 15 मार्च 2019 के बीच बंद रखने का निर्देश दिया था। इन इकाइयों ने 15 दिसंबर से करीब एक महीने पहले ही अपने शटर बंद कर दिए थे ताकि कचरा न निकले।

कानपुर के चमड़ा कारखानों में तालाबंदी के कारण देश के तैयार चमड़ा उद्योग में मंदी की स्थिति बनी और देश के चमड़ा उद्योग में कानपुर की हिस्सेदारी पिछले साल के 14 फीसदी से घटकर 11 फीसदी से कम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के बाद कानपुर की करीब 40 टेनरियों को अब तक पश्चिम बंगाल स्थानांतरित किया जा चुका है क्योंकि प्रदूषण और कच्चे चमड़े की आपूर्ति में बार बार बाधा आ रही है। टेनरियों और चमड़े के सामान निर्माताओं सहित कानपुर का चमड़ा उद्योग करीब 12,000 करोड़ रुपये का है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कानपुर और उन्नाव जिलों के करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इस कलस्टर से खाड़ी देशों, यूरोप, चीन और ईरान आदि को 6,000 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 दिसंबर को केंद्र की नमामी गंगे परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने और गंगा में बह रहे पानी की गुणवत्ता में आए कथित सुधार को व्यक्तिगत स्तर पर देखने के लिए कानपुर का दौरा किया था।

मोदी के दौरे के तुरंत बाद

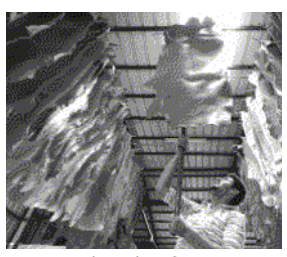

■ उत्तर प्रदेश में हरित अधिकरण ने अब कुछ शर्तों के साथ इन्हें चलाने की दी है इजाजत

यूपीपीसीबी ने कानपुर के जाजमऊ इलाके में 248 चमड़ा टेनरियों को 50 फीसदी क्षमता पर परिचालन की शर्त के साथ चलने की अनुमति दी। हरित समूह दो महीने बाद स्थिति का आकलन करेगा और अनुमति आगे जारी रखने पर निर्णय करेगा। स्मॉल टैनर्स एसोसिएशन के सदस्य नैयर जमाल ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि टेनरियों का परिचालन शुरू करने में 15-20 दिन और लगेंगे क्योंकि उनमें बहुत सारे मरम्मत कार्य होने हैं।

इन टेनरियों के बंद होने से उत्तर प्रदेश में कच्चे चमड़े की कीमतों पर भी बुरा असर पड़ा था और उसमें 60 फीसदी से अधिक की गिरावट आई। उन्होंने बताया कि इस बीच व्यापारी कच्चे चमड़े को प्रसंस्करण के लिए चेन्नई, जालंधर, कोलकाता जैसे शहरों में भेज रहे थे। इस साल कुंभ मेले के समापन के बाद यूपीपीसीबी ने 122 टेनरियों को 50 फीसदी क्षमता पर परिचालन चालू करने की अनुमति दी थी। हालांकि, बाद में एनजीटी के दिशानिर्देशों का हवाला देकर परिचालन बंद करने का आदेश दिया गया। एक ओर जहां कानपुर की टेनरियों को पटरी पर लौटने में एक वर्ष से अधिक का समय लगने की उम्मीद है वहीं उद्योग के मालिकों का कहना है कि विदेशी खरीदारों का विश्वास जीत पाना मुश्किल काम होगा।

शर्त के साथ काम चालू करने से हमें निर्यात आर्डर हासिल करने में मदद नहीं मिलेगी। कारण कि विदेशी खरीदारों के मन में भविष्य में फिर से कारखानों के बंद होने की आशंका घर कर गई होगी। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स (सीएलई) सेंट्रल रीजन के चेयरमैन जावेद इकबाल ने कहा यदि राज्य सरकार हमें स्थायी रूप से परिचालन की इजाजत दे तो उद्योग का उद्देश्य ठीक से पूरा हो पाएगा क्योंकि उसी स्थिति में हम अपने खरीदारों को नियमित आपूर्ति को लेकर मना पाएंगे।

हालांकि, उन्होंने टेनरियां चालू करने के आदेश को सकारात्मक करार दिया और भरोसा जताया कि सरकार उद्योग की बेहतरी के लिए और अधिक कदम उठाएगी।

डीएफसी से माल पहुंचाएंगे ई कॉमर्स दिग्गज!

डीएफसी के स्टेशनों को लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने से पार्सल कारोबार पकड़ सकता है रफ्तार

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 29 दिसंबर

भारत के पार्सल उद्योग में पश्चिमी और पूर्वी समर्पित मालवहन गलियारे (डीएफसी) परिवर्तनकारी साबित हो सकते हैं। भारतीय समर्पित मालवहन गलियारा निगम (डीएफसीसीआईएल) एमेजॉन और फ्लिपकॉर्ट जैसी दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ बात कर रहा है, जिससे ई-कॉमर्स दिग्गज उसके सभी स्टेशनों को लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में इस्तेमाल कर सकें। इस कदम से पार्सल डिलिवरी के वक्त में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।

दिसंबर 2021 तक दो गलियारे पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद ई-कॉमर्स कंपनियां सभी डीएफसी स्टेशनों को लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। इस मामले से जुड़े एक नजदीकी सूत्र ने कहा, 'यह पार्सल उद्योग के लिए परिवर्तनकारी साबित होगा क्योंकि छोटे व बड़े सभी स्टेशनों पर पार्सल की आवाजाही के समर्पित केंद्र होंगे। उम्मीद की जा रही है कि इससे मुंबई से दिल्ली तक पार्सल में लगने वाला वक्त 4 से 5 दिन वक्त घटकर 24 घंटे रह जाएगा। इसके अलावा दूरस्थ इलाकों के ग्राहकों को भी हमारे मध्यस्थ स्टेशनों के माध्यम से लाभ मिलेगा।'

डीएफसी में मालगाड़ियों की रफ्तार को लेकर बन रही योजना समय बचने की प्रमुख वजह है। मालगाड़ियों की औसत रफ्तार भारतीय रेल लाइनों पर 2019-20 तक 22.4 किलोमीटर प्रति घंटे रही है, जबकि डीएफसी में रफ्तार बढ़कर 75 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी।

प्रायोगिक आधार पर रेलवे बोर्ड एमेजॉन के साथ समझौता किया है। इसके तहत ई-खुदरा दिग्गज दो प्रमुख रेलगाड़ियों सियालदह और मुंबई राजधानी में जगह मिलेगी। एमेजॉन से लिया जाने वाला शुल्क उस ट्रेन की सबसे ज्यादा लीज दर है। ई-कॉमर्स क्षेत्र में तेजी को भारत में पार्सल की आवाजाही का प्रमुख संचालक माना जा रहा है। पिटनी बॉवेस पार्सल शिपिंग इंडेक्स की ओर से इस उद्योग की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले साल की तुलना में 2018 में पार्सल की मात्रा और राजस्व में 20 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

दूसरी तरफ भारतीय रेल के पार्सल कारोबार में गिरावट आ रही है। अप्रैल से अक्टूबर 2019-20 में इसका पार्सल कारोबार 5 प्रतिशत गिरकर 811.38 करोड़ रुपये रह गया जो 2018-19 की समान अवधि में 851.45 करोड़ रुपये था। पूरे वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान भी कारोबार में करीब 8 प्रतिशत की गिरावट आई है और यह 2017-18 के 1895.9 करोड़ रुपये से घटकर 1,744.77 करोड़ रुपये रह गया है।

यह परियोजना पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से होकर गुजरेगी। दिसंबर में डीएफसीसीआईएल ने कुछ राज्यों से संपर्क साथा था, जिससे डीएफसी के हर स्टेशन से सड़क का बेहतर संपर्क स्थापित किया जा सके और उद्योग डीएफसी के हर स्टेशन से आसानी से ढुलाई कर सकें। हरियाणा के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में यह कहा गया था कि सड़क संपर्क से इन्वेंट्री व लॉजिस्टिक्स लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। हरियाणा में कुल 14 स्टेशन हैं, जिनमें 7-7 स्टेशन पूर्वी व पश्चिमी डीएफसी में हैं।

81,400 करोड़ रुपये लागत से तैयार हो रही पूर्वी और पश्चिमी समर्पित मालवहन गलियारे का ट्रैक 3,360 किलोमीटर है। यह उन कुछ अहम परियोजनाओं में से है, जिसकी निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय कर रहा है। रेलवे को उम्मीद है कि ईडीएफसी के सोननगर से दानकुनी खंड को छोड़कर शेष परियोजना 2021 तक पूरी हो जाएगी। दादरी से शुरू होकर पश्चिमी खंड जेएनपीटी तक जाएगा, जिसमें राजस्थान के फुलेरा और मारवाड़ जंक्शन, गुजरात के पालनपुर, अमली रोड (साबरमती), मकरपुरा (वडोदरा), गोथंगम/कोसड और महाराष्ट्र का वसई रोड स्टेशन शामिल है। पूर्वी खंड का विस्तार लुधियाना से दानकुनी तक होगा, जिस पर ढंडारीकला, सरहिंद, टुंडला, भाऊपुर, प्रेमपुर, करछना, जिवनाथपुर, मुगलसराय, गंजख्वाजा, सासाराम, सोननगर, गोमोह, अंडाल और बर्धमान स्टेशन होंगे।

अब तक रेल गलियारे पर खर्च

वर्ष	खर्च
2007-08	10
2008-09	160
2009-10	496
2010-11	1,384
2011-12	1,968
2012-13	3,095
2013-14	3,243
2014-15	2,886
2015-16	8,508
2016-17	9,777
2017-18	6,703
2018-19	10,649
कुल	48,879

*जमीन सहित कुल खर्च करोड़ रुपये में

स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की मोदी की अपील

भाषा
नई दिल्ली, 29 दिसंबर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को साल के आखिरी 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा कि नई पीढ़ी को अराजकता, जातिवाद, परिवारवाद आदि पसंद नहीं है और उन्हें अव्यवस्था से चिढ़ है। ऐसे में आने वाला दशक निश्चित तौर पर युवाओं और उनके सामर्थ्य के साथ देश के विकास का दशक साबित होगा।

आकाशवाणी पर प्रसारित 'मन की बात' में अपने संबोधन में उन्होंने लोगों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा, 'मेरा सुझाव है कि क्या हम स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को प्रोत्साहन दे सकते हैं? क्या उन्हें अपनी खरीदारी में स्थान दे सकते हैं?' उन्होंने कहा कि 2022 में आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में देशवासियों के हाथों की बनी चीजें खरीदने का आग्रह करता हूं। स्थानीय उत्पादों पर बल दें। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए जरूरी है कि देश के नागरिक आत्मनिर्भर बनें और सम्मान से जिंदगी जीयें। उन्होंने कहा कि देशवासियों के हाथों से बना, जिसमें देशवासियों के पसीने की महक हो, ऐसी चीजों को खरीदने का आग्रह कर सकते हैं? 'मैं लंबे समय के लिए नहीं कहता हूँ, सिर्फ 2022 तक, आजादी के 75 साल होने तक।'

उन्होंने कहा कि ये काम, सरकारी नहीं होना चाहिए, स्थान-स्थान पर नौजवान आगे आएं, छोटे-छोटे संगठन बनाएं, लोगों को प्रेरित करें, समझाएं और तय करें- आओ, हम लोकल खरीदेंगे, स्थानीय उत्पादों पर बल देंगे, देशवासियों के पसीने की जिसमें महक हो- वही, मेरे आजाद भारत का सुहाना पल हो, इन सपनों को लेकर हम चलें।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'आने वाला दशक न केवल युवाओं के विकास का होगा, बल्कि युवाओं के सामर्थ्य से, देश का विकास करने वाला भी साबित होगा और भारत को आधुनिक बनाने में इस पीढ़ी की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है।'

गोविंदाचार्य का गृहमंत्री को खत

नेहा अलावधी
नई दिल्ली, 29 दिसंबर

> पुराने आंकड़ों के एकीकरण और तकनीक के इस्तेमाल से एनआरसी और एनपीआर पर गतिरोध खत्म करे सरकार

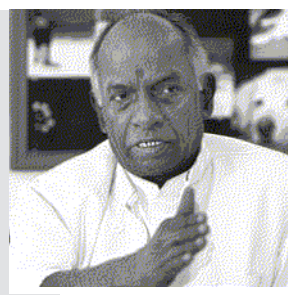

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक रहे केएन गोविंदाचार्य ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी पर चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार को तकनीक माध्यम से डेटा के एकीकरण के इस्तेमाल पर विचार करने की जरूरत है, जिससे इस काम में लगने वाली कवायद, कोशिश और व्यय को कम किया जा सके।

गोविंदाचार्य ने सुझाव दिया है कि सरकार ने करीब देश के 125 करोड़ नागरिकों को आधार नंबर मुहैया कराया है और एनपीआर के पिछले आंकड़ों के साथ इसे जोड़कर जनसंख्या की मैपिंग की जा सकती है। इस पत्र को बिजनेस स्टैंडर्ड ने देखा है।

उन्होंने सुझाव दिया है, 'केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना कार्यों के लिए 8,754.23 करोड़ रुपये और एनपीआर के लिए 3,941.35 करोड़ रुपये जारी किए हैं। आंकड़ों के एकीकरण से न सिर्फ राष्ट्रीय संसाधनों की बचत होगी बल्कि इससे करोड़ों लोगों को होने वाली असुविधा से भी बचा जा सकेगा।'

एनपीआर में भौगोलिक और बायोमेट्रिक दोनों ही आंकड़े तैयार किए जाएंगे। एनपीआर का विचार 2001 में आंतरिक सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक में सामने आया था। 1999 में करगिल युद्ध के बाद यह अनुभव किया गया कि घुसपैठियों को अलग करने की जरूरत है। नागरिकों को बहुद्देश्यीय राष्ट्रीय परिचय पत्र देने का विचार था और इसी से एनपीआर का विचार सामने आया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए) संसद ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

संशोधन के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन और ईसाई अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी।

दवाओं पर कारोबारी मुनाफे की सीमा धीरे धीरे होगी तय

पृष्ठ 1 का शेष

कारोबारी मार्जिन मानकीकृत हैं और यह दवा कंपनियों और कारोबार के बीच एक स्थापित उद्योग मानक हैं। यह पहले से ही करीब 30 फीसदी के स्तर पर है। अहमदाबाद की एक कंपनी में दिल की बीमारियों और मधुमेह से संबंधित दवाओं के बिक्री प्रमुख ने कहा, 'निर्माता के तौर पर एमआरपी तय करना हमारा अधिकार है और फिर ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं के लिए कारोबारी मार्जिन मानकीकृत है। लेकिन प्रचार वाली योजनाओं के लिए कभी-कभी कंपनियां ज्यादा मुनाफा देती हैं।' उन्होंने कहा कि कारोबारी मार्जिन को व्यावहारिक बनाना अच्छा कदम है जिससे ब्रांडेड दवा बनाने वाली कपंनियों को फायदा होगा।

लेकिन ट्रेड जेनेरिक्स के लिए मार्जिन मानकीकृत नहीं है। यह 30 से 80 फीसदी होता है। ट्रेड जेनेरिक्स बिना ब्रांड वाली दवाओं होती हैं जिन्हें सीधे वितरकों को भेजा जाता है और मेडिकल रिप्रजेंटेटिव्स बाजार में इसका प्रचार नहीं करते हैं। इससे निर्माता कंपनियों का प्रचार का पैसा बचता है और वे अपने उत्पादों के लिए ज्यादा प्रोत्साहन राशि देती हैं। सिप्ला, अल्केम, ल्यूपिन, कैडिला हेल्थकेयर, सन फार्मा सहित देश की सभी बड़ी दवा कंपनियों का ट्रेड जेनेरिक्स का कारोबार है जिससे उन्हें अपनी घरेलू बिक्री बढ़ाने में मदद मिलती है। सिप्ला का करीब 20 फीसदी घरेलू राजस्व ट्रेड जेनेरिक्स से आता है और यही वजह है कि मार्जिन की सीमा तय करने से उसे नुकसान होगा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2019 में अपने घरेलू वितरण नेटवर्क में व्यापक बदलाव किया था।

बाजार शोध फर्म एआईओसीडी फार्मासॉफ्टेक अवाक्स के निदेशक अमीश मसुरेकर ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा था कि जब कोई कंपनी किसी अस्पताल को इंजेक्शन से लगने वाली एंटीबायोटिक्स बेचती है तो कभी-कभार इसमें दी जाने वाली छूट या कीमत में कुछ बदलाव आ सकता है। उन्होंने कहा, अगर कारोबारी मार्जिन की सीमा तय की जाएगी तो इससे दवा कंपनियों की बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं होगा लेकिन अस्पताल का मार्जिन प्रभावित हो सकता है।

अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र से पावर एक्सचेंज लिमिटेड में लौटी जान

श्रेया जय
नई दिल्ली, 29 दिसंबर

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज की बिजली कारोबार करने वाली कंपनी पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) अपना परिचालन दोबारा शुरू करने के बाद अक्षय ऊर्जा पर अपना जोर लगा रही है। उसकी नजर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) के बाजार को ऊपर उठाने पर होगी जिसमें बाजार की रुचि उत्साहहीन बनी हुई है।

साल 2017 में जब पीएक्सआईएल के शुद्ध मुनाफे में गिरावट आई तो कंपनी को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था और उसके प्रमोटरों एनएसई और एनसीडीईएक्स इसे बंद कर देना चाहती थी। यह बात एनएसई की प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से पहले की है।

पीएक्सआईएल के प्रबंध निदेशक प्रभजीत कुमार सरकार ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'प्रमोटर इस बात को लेकर बेचैन थे कि वे भिन्न मार्केट प्लेस तैयार कर रहे हैं। शुद्ध संपत्ति में आई गिरावट विषम परिस्थिति में फंसने वाली बात थी और बाहर से पैसा जुटाना मुश्किल हो गया था। लेकिन वित्त वर्ष 2018 से पीएक्सआईएल मुनाफा दर्ज कर रही है। इसकी मुख्य वजह यह है कि हमने अपने मजबूत क्षेत्रों पर ध्यान लगाया।'

सरकार ने कहा पीएक्सआईएल का जोर पिछले दो वर्षों में मुख्य तौर पर एक अवधि के लिए खरीदी जाने वाली बिजली बाजार (टीएएम) और आरईसी पर रहा है। उन्होंने कहा, 'और अब हमारे पास बड़े पैमाने पर एक दिन पहले के लिए खरीदी जाने वाली बिजली के हाजिर बाजार के लिए भी प्रयास नकदी है।'

भारत में बिजली व्यापार बाजार के लिए दो प्लेटफॉर्म है- पीएक्सआईएल और इंडिया एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स)। एक दिन पहले बिजली खरीद के हाजिर बाजार के 95 फीसदी हिस्से पर आईईएक्स का कब्जा है। पीएक्सआईएल के पास आरईसी और टीएएम में 40 फीसदी बाजार हिस्सेदारी है।

कंपनियों और राज्य सरकारों की ओर से नवीकरणीय बिजली संयंत्र स्थापित किए बिना ही अक्षय ऊर्जा की खरीद के लिए आरईसी की शुरुआत 2010 में हुई थी। परियोजना डेवलपर उत्पादित ऊर्जा को आरईसी के रूप में बेच सकते हैं। एक आरईसी का मतलब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से 1 मेगावॉट घंटा उत्पादित बिजली है और इसका व्यापार बिजली एक्सचेंजो पर किया जाता है। इसे सौर आरईसी और गैर-सौर आरईसी में बांटा गया है।

हालांकि, सरकार इस बात से सहमत हैं कि आरईसी अभी भी एक कठिन क्षेत्र बना हुआ है। बाजार की रुचि में कमी और 2017 में 1 करोड़ से अधिक आरईसी अनबिके रह जाने के कारण इसका बाजार धराशायी हो गया था। सरकार ने कहा कि तब से व्यापार प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध आरईसी की संख्या कम हो गई है लेकिन उसने बाजार के आकार को कम कर दिया है।

चालू वित्त वर्ष में 2,21,000 सौर आरईसी और 13.5 लाख गैर-सौर आरईसी का व्यापार किया गया है। सौर आरईसी के लिए पिछला बंद भाव 2,400 रुपये प्रति आरईसी (उत्पादित बिजली का 2.4 रुपये प्रति किलोवाट घंटा) और गैर-सौर के लिए यह 1,850 प्रति आरईसी (1.85 रुपये प्रति किलोवॉट घंटा) था। यह भाव ग्रिड से जुड़े सौर और पवन बिजली परियोजनाओं की मौजूदा कीमत से कम है।

सरकार ने कहा, 'पिछले कुछ महीनों से उपलब्ध आरईसी की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। लेकिन खरीदारों की संख्या में इजाफा हुआ है। ये सभी ऐसे राज्य हैं जो अपनी अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) पूरी करना चाहते हैं।' उन्होंने कहा कि आरईसी उपभोक्ताओं के एक ऐसे खास वर्ग के लिए फायदेमंद है जो अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित नहीं कर सकते लेकिन उन्हें हरित ऊर्जा की बाध्यता पूरी करनी है। ये औद्योगिक संकुल और वाणिज्यिक केंद्र आदि हैं।

उन्होंने कहा कि आरईसी तंत्र केवल तभी काम करता है जब परियोजना डेवलपर सौर बिजली परियोजनाओं की दीर्घावधि कीमत से कम कीमत पर बिक्री करते हैं। सरकार ने कहा, 'बहुत कम डेवलपर आरईसी के रास्ते आ रहे हैं।'

उन्होंने कहा कि कंपनी केंद्रीय बिजली नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत के लिए एक स्वेत पत्र तैयार कर रही है जिसमें मांग की जाएगी कि अक्षय ऊर्जा बाजार में आरईसी के अलावा विभिन्न तरह के ठेकों और उत्पादों को अनुमति दी जानी चाहिए।

एनएसई और एनसीडीईएक्स के अलावा पीएक्सआईएल बोर्ड में शामिल अन्य कंपनियां जीएमआर एनर्जी, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सरकारी क्षेत्र की पावर फाइनैंस कॉर्पोरेशन, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) और वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैं।

पीएक्सआईएल को पिछले दो वर्षों में मुनाफा

- वित्त वर्ष 2020 में आरईसी का कारोबार - सौर ऊर्जा में 2.2 लाख, 2,400 रुपये प्रति आरईसी की दर से और गैर-सौर में 13.5 लाख 1,800 रुपये प्रति आरईसी की दर से (नवंबर महीने की कीमत के अनुसार)
- साल 2017 में 2 करोड़ आरईसी अनबिके रह गए थे जिससे आरईसी का बाजार धराशायी हो गया था
- पीएक्सआईएल भी अक्षय ऊर्जा बाजार में अधिक ठेके हासिल करने और उत्पादों के लिए सीईआरसी पर देगी ध्यान
- पीएक्सआईएल के प्रमोटरों एनएसई-एनसीडीईएक्स ने 2017 में अपने शुद्ध मुनाफे में कमी आने के बाद इसे बंद करने का निर्णय लिया

समय बचने के साथ फास्टैग से बढ़ रहा है टोल भी

अमृता पिल्लई
मुंबई, 29 दिसंबर

नजर आने लगे फायदे

- यातायात संचालन बेहतर होने के साथ फास्टैग से टोल संग्रह भी बढ़ने की उम्मीद
- राजमार्गों पर काम कर रहे ठेकेदार व निजी कंपनियां नहीं छिपा पाएंगी टोल
- फास्टैग की पहुंच 30 प्रतिशत से बढ़कर इस समय 55 प्रतिशत तक हो चुकी है
- फास्टैग के गति पकड़ने से एनएचएआई का बढ़ चुका है कुल 10 प्रतिशत राजस्व
- सड़क मंत्रालय ने 1 दिसंबर, 2019 से टोल प्लाजा में सड़क के दोनों तरफ एक लेन छोड़ सभी को फास्टैग लेन बनाने की घोषणा की

केंद्रीय सड़क मंत्रालय की ओर से लाए गए फास्टैग की मदद से राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात संचालन न केवल बेहतर होने की उम्मीद है बल्कि टोल संग्रह में भी इजाफा होने की उम्मीद है। उद्योग के अधिकारी और विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि डिजिटल व्यवस्था से नहीं चुकाए जाने वाले टोल भुगतान की संख्या भी कम करने में मदद मिलेगी।

इस कदम से न केवल और अधिक पारदर्शिता आएगी बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परिचालित राजमार्गों पर काम कर रहे ठेकेदारों के साथ साथ निजी कंपनियों द्वारा टोल संग्रह छिपाने जैसी स्थिति भी समाप्त होने की उम्मीद है।

डेलॉयट में पार्टनर कुशल सिंह ने कहा, 'जब आप हर चरण पर जांच करेंगे तो उससे व्यवस्था में कुछ शुद्धता आएगी। इस समय फास्टैग की पहुंच 30 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो चुकी है और एनएचएआई का कुल राजस्व 10 फीसदी ऊपर जा चुका है। इसकी एकमात्र वजह यह है कि राजस्व के इस हिस्से को बताया नहीं जा रहा था। टोल प्लाजा पर कोई वाहन बिना भुगतान के गुजर गया हो अमूमन ऐसा सुनने में नहीं आता है। इसका मतलब है कि यदि टोल नहीं मिलने की कोई बात थी तो वह जानबूझ कर की जाती थी।'

नवंबर में सड़क मंत्रालय ने कहा था कि 1 दिसंबर, 2019 से टोल प्लाजा में सड़क के दोनों तरफ एक लेन को छोड़कर सभी लेनों को टोल की फास्टैग लेन घोषित किया जाएगा। लेकिन इस समय सीमा को 15 दिसंबर किया गया। मंत्रालय का कहना है कि फास्टैग लागू करने से समय की बचत और प्रदूषण में कमी के साथ ही ट्रैफिक की आवाजाही बगैर किसी बाधा के होगी। हालांकि, एनएचएआई को तुरंत मिलने वाला लाभ केवल पैसे भर का नहीं है।

एलऐंडटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स (आईडीपीएल) के लिए मुख्य कार्याधिकारी शैलेश पाठक ने कहा, 'एनएचएआई के लिए फास्टैग पहले ही ज्यादा राजस्व देने वाला साबित हो चुका है। ऐसा शायद रिसाव या टोल संग्रह की जानकारी छिपाने के मामले घटने से हुआ है।' उद्योग के सूत्रों ने कहा कि अब तक टोल की जानकारी नहीं देने की घटनाएं वाहनों को अकारण छूट देने और कुछ मामलों में कुछ लेनों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली बंद रखने से चल रही थी।

पाठक ने कहा फास्टैग की व्यवस्था अपनाने से नकद लेनदेन पर लगने वाले शुल्क से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा, 'हमारी जैसी कंपनियों ने उपयोगकर्ता के अनुभव को बेहतर बनाया है और नकद लेनदेन में दो तिहाई की कमी की है। इस व्यवस्था से संभावित हेरफेर, नकद लेनदेन पर लगने वाले शुल्क और बीमा से छुटकारा मिलेगा।' उन्होंने कहा कि इस सुविधा के सबसे बड़े लाभार्थी आम उपयोगकर्ता हैं जो टोल प्लाजा पर बिना किसी जाम के गुजर रहे हैं। इससे उनके समय और ईंधन दोनों की बचत हो रही है।

फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि कैशलेस व्यवस्था लागू होने से न बताए जाने वाले टोल की घटनाओं की जांच की कोई गुंजाइश बन सकती है या नहीं। डेलॉयट के सिंह ने कहा, 'इस बात की जांच कौन करेगा और कैसे साबित करेगा कि अब जिन 10 अतिरिक्त वाहनों से टोल मिल रहा है, वे ही वाहन फास्टैग की सुविधा शुरू होने से पहले भी गुजर रहे थे।'

बीएस सूडोकू 3625 | परिणाम संख्या 3624

5	9	4						
			1				4	9
1					7			8
2				6	5			
		5	7		3	6		
			9	2				5
4			2					6
3	1				4			
						1	8	4

2	8	7	3	5	6	4	1	9
4	9	3	2	8	1	6	7	5
5	1	6	7	9	4	8	3	2
7	6	4	9	2	3	1	5	8
8	5	2	6	1	7	3	9	4
9	3	1	8	4	5	7	2	6
6	2	5	1	3	8	9	4	7
3	4	8	5	7	9	2	6	1
1	7	9	4	6	2	5	8	3

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत मुश्किल ★★★★★

असम की अशांति को देखते हुए एमएफआईएन ने मांगी राहत

नम्रता आचार्य
कोलकाता, 29 दिसंबर

असम और आसपास के इलाकों में भुगतान में हो रही देरी को देखते हुए माइक्रोफाइनैंस इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधि निकाय माइक्रोफाइनैंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआईएन) ने भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान में देरी के लिए राहत की मांग की है।

इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण पूरे पूर्वोत्तर इलाके, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में पुनर्भुगतान में देरी हो रही है। बहरहाल इस देरी की वजह से चूक नहीं हो रही है और एमएफआई को स्थिति सुधरने के बाद रिकवरी की उम्मीद है।

एमएफआई ने पहले ही असम में चूक के कारण चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में ज्यादा एनपीए की सूचना दी है। एमएफआईएन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमने रिजर्व बैंक से फॉरबियरेंस के लिए कहा है क्योंकि असम के कुछ जिलों में भुगतान प्रभावित हुआ है। कुछ मामलों में जनवरी तक चूक 90 दिन की हो जाएगी।'

असम में माइक्रोफाइनैंस का कुल पोर्टफोलियो 12,000 करोड़ रुपये के करीब का है। इसमें से करीब 40 प्रतिशत पोर्टफोलियो जानी 4,800 करोड़ रुपये ऊपरी असम में केंद्रित है, जिस इलाके में माइक्रोफाइनैंस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। एमएफआईएन के आंकड़ों के मुताबिक असम में एनबीएफसी एमएफआई का सकल कर्ज पोर्टफोलियो करीब 2,500 करोड़ रुपये का है।

विलेज फाइनैंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ कुलदीप मैती ने कहा, 'कुछ इलाकों में पुनर्भुगतान में देरी हो रही है, लेकिन इस देरी की वजह से पीएआर 30 (पोर्टफोलियो ऐट रिस्क बियॉन्ड 30 डेज) पर असर नहीं होगा।'

सीआरआईएफ हाई मार्क की हाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोफाइनैंस क्षेत्र के लिए क्रेडिट ब्यूरो वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में विलंब का स्तर पहली तिमाही के स्तर से ज्यादा रहा। पीएआर 1-30 (कर्ज के भुगतान में 1 से 30 दिन की देरी) जून 2019 को समाप्त तिमाही में 1 प्रतिशत रहा, जबकि सितंबर 2018 के अंत में समाप्त तिमाही के दौरान यह बढ़कर 2.9 प्रतिशत पर पहुंच गया था। बहरहाल यह एक बार फिर एक प्रतिशत के स्तर से ज्यादा हो गया है और इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत में यह 1.3 प्रतिशत रहा। ज्यादा चिंता की बात यह है कि पीएआर 180 प्लस (जिसमें बकाया 180 दिन से ज्यादा हो गया है) 4.5 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बना हुआ है। यह इसके पहले की तिमाही से 0.2 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान यह 1 प्रतिशत से नीचे था।

प्राकृतिक आपदा और कर्ज ज्यादा लेने जैसी वजहों से देरी हो रही है। असम में माइक्रोफाइनैंस संगठनों के खिलाफ विरोध का नेतृत्व जगराता महिला सुरक्षा समाज कर रहा है, जिसका दावा है कि राज्य में आत्महत्या के लिए माइक्रोफाइनैंस का कर्ज जिम्मेदार है। ध्यान देने की बात है कि एमएफआई सेग्मेंट में इस समय बैंकों की भूमिका प्रमुख हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 269

बैंकों को करें दुरुस्त

बैंकिंग क्षेत्र में चुनौतियां बरकरार रहने के बावजूद हालात में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से जारी नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में कहा गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) सितंबर 2019 के 9.3 फीसदी से बढ़कर सितंबर 2020 में 9.9 फीसदी के स्तर तक जा सकती हैं। वृहद-आर्थिक हालात में बदलाव, फिसलन में बेहद कम बढ़त और गिरती ऋण वृद्धि इसकी बड़ी वजह है। सुस्त आर्थिक वृद्धि बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र (एनबीएफसी) के लिए जोखिम पैदा करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में नॉमिनल वृद्धि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में गिरकर 6.1 फीसदी रही है जो करीब दो दशकों में सबसे कम है। नॉमिनल वृद्धि कम होने से कारोबारों के राजस्व पर असर पड़ेगा जिससे सेवा क्षेत्र को ऋण बांटने की उनकी क्षमता प्रभावित होगी।

एनपीए के अलावा वृहद-आर्थिक एवं नीतिगत पर्यावरण खासकर सार्वजनिक बैंकों के लिए हालात को मुश्किल बना सकता है। ऋण वृद्धि अब जमा वृद्धि को पीछे खींच रही है। जहां बैंकिंग प्रणाली का एक हिस्सा अपने बहीखाते के विस्तार की हैसियत में नहीं हैं वहीं भारतीय कंपनियां तेजी से विदेशी उधारी ले रही हैं। इस समाचारपत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉलर बॉन्ड के जरिये फंड का उठान 2019 में पांच गुना बढ़कर 23.6 अरब डॉलर हो गया। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति समायोजन ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में हालात को थोड़ा सरल बनाया है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में हस्तांतरण की अपेक्षाकृत सुस्त रफ्तार ने आरबीआई की कम ब्याज दरों का फायदा कंपनियों तक नहीं पहुंचने दिया है और बाह्य उधारी को अधिक आकर्षक भी बना दिया है। विदेशी मुद्रा उधारी में तेजी बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित करने के अलावा आरबीआई के लिए नीतिगत दरों के प्रबंधन को भी जटिल बना सकती है।

भले ही वृहद-आर्थिक हालात अनुकूल नहीं हैं लेकिन बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली का लचीलापन बढ़ाने के लिए एक बढ़िया कदम उठाया जा सकता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एफएसआर रिपोर्ट की भूमिका में निजी बैंकों समेत बैंकिंग क्षेत्र के बेहतर संचालन की जरूरत पर बल दिया है। समूची ऋण बाजार पारिस्थितिकी में कामकाजी मानकों की समीक्षा की जरूरत है। मसलन, वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने भी कहा है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने लिखित समझौतों के बगैर निर्देशात्मक रेटिंग दी थी। रेटिंग एजेंसियों ने इन निर्देशात्मक रेटिंग की जानकारी नहीं दी है लिहाजा रेटिंग खरीद की आशंका का पता लगा पाना मुश्किल है। हालांकि एक एजेंसी के रेटिंग वापस लेने और दूसरी एजेंसी से रेटिंग देने की प्रवृत्ति रेटिंग की खरीद की संभावना का संकेत देती है। इसकी वजह यह है कि नई रेटिंग भी अक्सर पुरानी रेटिंग के समान या उससे बेहतर होती है। ऋण आवंटन में रेटिंग की भूमिका अहम होने से रेटिंग एजेंसियों द्वारा समझौतापरक मूल्यांकन करने से उधार देने के फैसले प्रभावित हो सकते हैं। सेबी ने हाल ही में आईएलऐंडएफएस मामले में रेटिंग एजेंसियों पर जुर्माना लगाया है। यह कदम नियम अनुपालन की अहमियत के बारे में ठोस संदेश देने में मददगार होगा। फिर भी, रेटिंग एजेंसियां इस पारिस्थितिकी का ही हिस्सा हैं। एक हद तक बैंकिंग प्रणाली की सेहत सरकार और खुद केंद्रीय बैंक पर भी निर्भर करती है। आरबीआई बैंकों एवं एनबीएफसी के कई मामलों में परिचालन की नाकामी का अंदाजा लगा पाने में नाकाम रहा है। यहां हमें आईएलऐंडएफएस मामले को याद करना चाहिए। बैंकिंग नियामक की निगरानी क्षमता में सुधार से वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। वहीं सरकार को सक्षमता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बैंकों में कामकाजी सुधार लाने की जरूरत है ताकि वे वित्तीय प्रणाली और समग्र आर्थिक वृद्धि में अवरोध न बने।

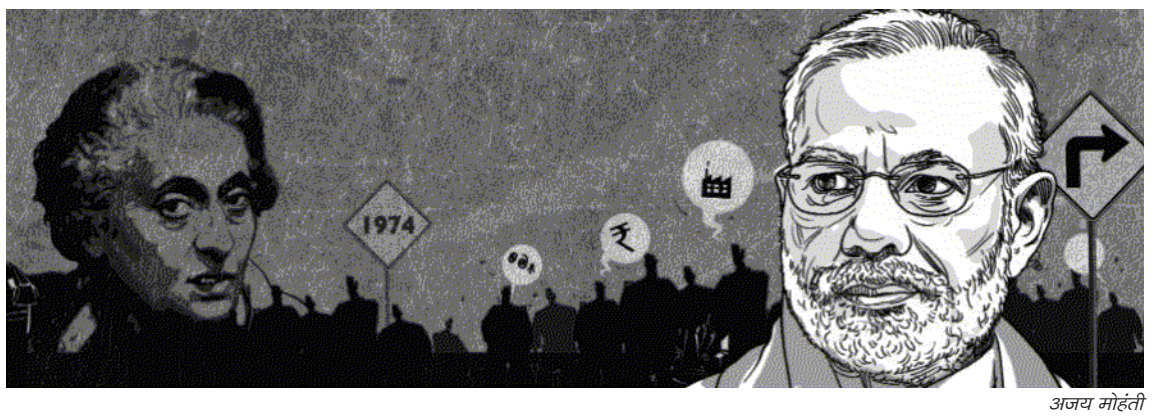

अजय मोहंती

अतीत की खतरनाक राह पर लौटता भारत

इतिहास खुद को दोहरा रहा है और 1974 के दिनों जैसा अहसास हो रहा है। मगर मोदी के लिए इंदिरा गांधी सरीखे काम करना आसान नहीं है क्योंकि भारत एकदम अलग परिस्थितियों में जी रहा है

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

एक के बाद एक बिगड़ते आर्थिक सूचकांकों के बीच यह बात साफ नजर आती है कि आज बेरोजगारी 45 साल के सबसे भीषण स्तर पर है। बेरोजगारी का यह हाल हमें सीधे 1974 में ले जाता है।

उस वक्त इंदिरा गांधी लोकप्रिय थीं, लेकिन धीरे-धीरे उनसे मोहभंग हो रहा था। फिर भी निराश मतदाताओं को यही लगता था कि दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। सभी आर्थिक सूचकांक लुढ़क रहे थे, मुद्रास्फीति 35 फीसदी पर थी फिर भी राष्ट्रवाद चरम पर था।

यह सब जाना पहचाना लग रहा है न? मुद्रास्फीति यानी महंगाई को छोड़ दें तो आज बाकी सब कुछ 1974 जैसा ही लग रहा है। निष्ठावान अनुयायियों वाली पार्टी का जबरदस्त लोकप्रियता वाला नेता, बिखरा हुआ विपक्ष, राष्ट्रवादी उफान और ढहती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी। भारत विरोधाभासों की धरती भर नहीं है। यह तो एक ही पीढ़ी के भीतर दो एकदम विपरीत विचारधाओं के अंतर्गत एक ही जैसा बड़ा विरोधाभास पैदा करके भी दिखा सकता है।

थोड़ा और पीछे, 1971 में चलते हैं। इंदिरा गांधी ने उसी साल कांग्रेस के दोफाड़ किए और विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने के बाद भी कांग्रेस के दूसरे खेमे के पुराने कद्दावरों को हराकर प्रसिद्ध चुनाव जीता।

1971 के आरंभ में उन्होंने 'गरीबी हटाओ' का जनवादी नारा दिया। साल बीतते-बीतते वह पाकिस्तान को हटाकर और दो टुकड़ों में बांटकर 'मां दुर्गा' का अवतार बन चुकी थीं। वह चमत्कारी बन चुकी थीं।

लेकिन समाजवाद और राष्ट्रवाद का यह दोहरा मुलम्मा भारत के विद्रूप यथार्थ को ढक रहा था। राष्ट्रीयकरण की उनकी सनक से अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, उद्यमी लाइसेंस कोटा राज तले कराह रहे थे, कराधान की बेहद ऊंची दर (97.5 फीसदी) ने काली यानी समांतर अर्थव्यवस्था तैयार कर दी थी, जिसे मात नहीं दी जा सकी थी। जंग पर हुए खर्च ने हालत और बुरी कर दी थी। लेकिन याद रखिए कि राजनीति आंकड़ों से नहीं चलती बल्कि जनता की मंशा या 'हवा' पर चलती है।

1971 ही वह साल था, जब कवि-गीतकार गुलजार ने अपनी पहली फिल्म 'मेरे अपने' बनाई थी। फिल्म मीना कुमारी के इर्द-गिर्द घूमती थी, जो शहर में गरीब और बेसहारा बूढ़ी के तौर पर आईं और युवाओं के एक झुंड ने उन्हें सहारा दिया। युवाओं के किरदार निभाने वाले कुछ नाम आगे जाकर बहुत बड़े हो गए। उनके पास डिग्रियां थीं, सपने थे, लेकिन नौकरी नहीं थी। इसलिए उनके पास नाउम्मीद रहने, शरारत करने या सड़कों पर लड़ने के अलावा कोई और काम ही नहीं था।

मगर वे युवक खुद पर हंस सकते थे और गुलजार ने उनके लिए हताशा भरे उन दिनों का गीत भी लिखा था: 'हाल चाल ठीक ठाक है...' इसे चलाइए, पंक्तियां सुनिए। हर पंक्ति पर आप रुकेंगे और सोचेंगे कि मैं उन दिनों की बात क्यों कर रहा हूं।

नमूना देखिए: 'बीए किया है, एमए किया, लगता है वह भी ऐवेंइ किया/काम नहीं है वरना यहां, आपकी दुआ से बाकी ठीक-ठाक है...' गुलजार 2019 में भी यही लिखते। लेकिन वह इसे फिर से पेश कर सकते हैं और कह सकते हैं कि अभी लिखा है। आपको पता नहीं चलेगा।

2014 की दुनिया जीत लेने वाले आशावाद से हम इस हालत तक कैसे पहुंच गए, इस पर बात करने से पहले देखना चाहिए कि 1971 में अर्श पर उड़ रहे भारत और इंदिरा गांधी का 1974 जैसा हश्र क्यों हुआ। मार्च 1971 की अभूतपूर्व जीत और विपक्ष की दुर्गति का ऐसा नशा चढ़ा कि इंदिरा और उनके विचारधारा (वामपंथी) में पगे सलाहकार समाजवाद के जहर में डूबते ही चले गए।

उसके बाद जब भारत की अर्थव्यवस्था सबसे नाजुक दौर में थी तब दोहरी चोट लगी। पहला योम किपर युद्ध (अक्टूबर 1973) के कारण लगा तेल का झटका था, जिसे वह काबू नहीं कर सकीं। दूसरा, गेहूं के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण था, जो उन्होंने 'आ बैल मुझे मार' की तरह खुद किया। उनके कम्युनिस्ट सलाहकारों ने कहा कि अगर यह सोवियत संघ में कारगर रहा तो यहां भी होगा। लेकिन यह कारगर नहीं रहा।

इसके बाद दुर्गति बढ़ती गई, गेहूं के दाम चढ़ते गए, किसानों में आक्रोश भरता गया और कारोबारी तथा निजी ग्रामीण बिचौलिये बेरोजगार हो गए। उनकी यह हरकत चीन की गौरैया के खिलाफ माओ की जंग सरीखी थी। इंदिरा ने यह फैसला वापस तो ले लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1974 की आखिरी तिमाही आते-आते भारत की मुद्रास्फीति दर 34.7 फीसदी तक चढ़ गई और इंदिरा की लोकप्रियता बहुत घट गई। देश भर में विरोध, नवनिर्माण आंदोलन फूट पड़ा, जिसमें बेरोजगार युवक और गुस्साए छात्र शामिल थे। यह भी आजकल की ही बात लग रही है न?

कोई रास्ता नहीं बचा तो इंदिरा ने 'राष्ट्रवाद' का अपना पुराना पत्ता फेंका। पहले पोकरण-1 परमाणु परीक्षण (मई 1974) हुआ। उसका खुमार कुछ हफ्ते ही रहा क्योंकि लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी थीं। उन्होंने आखिरी पासा मई 1975 में फेंका, जब सिक्किम का विलय किया गया। लेकिन नाराज जनता पीछे हटने का तैयार नहीं थी। एक महीने बाद आपातकाल लग गया।

मैं यह नहीं कह रहा कि इस बार भी हम उसी हालत में पहुंच जाएंगे। मैं केवल इतना कह रहा हूं: यदि लोगों को लंबे समय तक बेरोजगारी और आर्थिक ठहराव झेलना पड़ता है तो राष्ट्रवाद से उनका गुस्सा शांत नहीं होता।

इसी बात पर एक बार फिर फिल्मों का रुख करते हैं क्योंकि हमें पता है कि फिल्मकार किसी भी विश्लेषक से पहले ही अपने बाजार यानी जनता की नब्ज पकड़ लेते हैं। 'मेरे अपने' के बाद 'शोर', 'रोटी कपड़ा और मकान' और गरीबी, शोषण, महंगाई (बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई बड़ा हिट हुआ था) के इर्द-गिर्द बुनी गई तथा बेरोजगार नायकों वाली फिल्मों का दौर आ गया। यही आगे चलकर 'एंग्री यंग मैन' के दौर में बदल गया। लेकिन फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं।

आपको क्या लगता है? इतिहास ने खुद को दोहराना कब से शुरू किया? आपमें से कुछ को हालिया आम चुनाव से इसकी शुरुआत लग सकती है, जिसमें मिली जीत ने डगमगाती अर्थव्यवस्था के बाद भी मोदी सरकार को घमंडी बना दिया। अगर लोग अर्थव्यवस्था की इतनी बुरी गति के बाद भी हमें वोट देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको सामाजिक-राष्ट्रवादी खुमार बनाए रखना है। आप इसमें धर्म का तड़का भी लगा सकते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था सुधारने में जुटने के बजाय अनुच्छेद 370 ले आओ, मंदिर की बात करो, नागरिकता संशोधन कानून ले आओ। आर्थिक आंकड़े हर तिमाही बद से बदतर होते भी जाएं तो फिक्र कैसी।

आप नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के शुरुआती दिनों को याद करें, जब 'सूट-बूट की सरकार' के साथ ही भूमि अधिग्रहण कानून पर सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी। यह देखते ही मोदी ज्यादा राष्ट्रवाद और सामाजिक जनवाद का रास्ता पकड़कर भ्रष्टाचार से लड़ने वाले बन गए थे। नोटबंदी के जरिये उन्होंने अपने पांव पर पहली कुल्हाड़ी मारी। सीएए-एनआरसी-एनपीआर का झमेला दूसरी कुल्हाड़ी लग रहा है क्योंकि सबसे पहले तो यह देश को इस तरह बांट रहा है, जैसा दशकों में नहीं हुआ। दूसरा, इस पर दुनिया भर में सीधी आलोचना बेशक नहीं हुई हो, लेकिन निराशा तो जताई ही गई है, जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम वैश्विक दुनिया में रह रहे हैं, जहां भारत के हित 1974 से काफी अलग हैं। तीसरा, इंदिरा के अच्छे दिनों के उलट अब भारत संघशासित है। आप मुख्यमंत्रियों को हुक्म नहीं दे सकते और न ही अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं।

1974 वाले इस अहसास से हम कहां जाएंगे? हमें पता है कि 1975 की गर्मियों तक इंदिरा हमें कहां ले गई थीं। फैसला मोदी के हाथ है। बेशक वह उस वक्त की इंदिरा से ज्यादा लोकप्रिय और ताकतवर हैं, लेकिन भारत आज 1975 से बहुत अलग है।

अंशकालिक कर्मियों की बारी भारतीय उद्योग भी करें तैयारी

इंसानी पहलू

श्यामल मजूमदार

गिग इकनॉमी कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों के लिए लाभदायक है। कर्मचारियों को जहां इससे लचीलापन और आजादी मिलती है, वहीं नियोक्ता की लागत कम होती है

इसे व्यापक तौर पर काम के 'उबरीफिकेशन' (मांग पर सेवा मुहैया कराना) के तौर पर जाना जाता है। तमाम अध्ययन और सर्वेक्षण यही बताते हैं कि सन 2000 के बाद पैदा हुए युवाओं में से अधिकांश अपने जीवन और कामकाज में बेहतर संतुलन कायम करने की कोशिश में अंशकालिक तौर पर और जरूरत के मुताबिक काम करने में यकीन करते हैं। कई कंपनियों का बदलता कारोबारी मॉडल भी यही सुझाता है कि बड़ी तादाद में लोगों को जरूरत के मुताबिक काम पर रखा जाएगा।

यानी यह तय है कि नए वर्ष में गिग इकनॉमी (उपरोक्त लक्षणों वाली अर्थव्यवस्था) को लेकर बात और मुखर होगी। परंतु कंपनियों का यह मानना गलत होगा कि केवल वाहन चालक, डिलिवरी बॉय या होटलों के बार आदि में काम करने वाले कर्मचारी ही गिग इकनॉमी का हिस्सा होंगे।

तकनीक आधारित काम मसलन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या वेब डिजाइन, या कानूनी काम अथवा अंकेक्षण का काम आदि पहले ही इस नई व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। आगे इनकी हिस्सेदारी और बढ़ेगी। नए वर्ष में और अधिक विशेषज्ञता वाले रोजगार सामने आ सकते हैं क्योंकि संस्थान कुशल श्रमिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों को तलाशेंगे क्योंकि स्थायी कर्मचारियों में ऐसे लोग नहीं हैं।

सवाल यह है कि कंपनियां इस नए माहौल से निपटने के लिए क्या कर रही हैं? क्या नियोक्ता श्रम के मॉडल में अपरिहार्य बदलाव की चुनौती से निपटने को तैयार हैं? इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है 'बहुत कम'। यह बात चकित करती है क्योंकि अधिकांश कंपनियां और उनके एचआर पेशेवर जानते हैं कि उनके कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा जल्दी ही अनुबंधित या अस्थायी कर्मचारियों से बनने वाला है। बात यह भी है कि गिग इकनॉमी कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों के लिए लाभदायक है। कर्मचारियों को जहां इससे लचीलापन और आजादी मिलती है, वहीं नियोक्ता की लागत कम होती है। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल आधी कंपनियां अंशकालिक श्रमिकों को प्रशिक्षण देती हैं और उनमें भी एक तिहाई ही उनको प्रदर्शन के आधार पर बेहतर वेतन-भत्ते प्रदान करती है। ऐसे कर्मचारियों में संबद्धता की कमी की आशंका के बीच आधे से कम नियोक्ता उन्हें आंतरिक संवाद में शामिल करते हैं या उन्हें पुरस्कृत करते हैं।

ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि अधिकांश कंपनियां बाहरी कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। साथ ही वे इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हैं कि उन्हें प्रतिभा कहां से और कैसे जुटानी है। आखिरकार, कई योग्य स्वतंत्र पेशेवरों के पास अक्सर क्लाइंट प्रतीक्षारत रहते हैं। उन्हें निपटने में कई महीनों का समय लग जाता है। ऐसे में मूल विचार यह है कि वे अपनी ब्रांडिंग इस तरह करें जिससे पता लगे कि वे गिग अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक हैं। ऐसा करने से लोग उनके साथ काम करना पसंद करेंगे।

इसके पीछे आर्थिक कारण भी है। गैलप के आंकड़ों के मुताबिक यदि शीर्ष 20 प्रतिशत प्रत्याशियों का चयन किया जाए तो मुनाफे में 21 फीसदी की उछाल आती है। यह भी कहा गया कि अस्थायी कर्मचारी भी उतने ही महत्त्वपूर्ण होते हैं जितने पूर्णकालिक कर्मचारी। एक दिक्कत यह है कि अधिकांश कंपनियां अभी भी वार्षिक या अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन की परंपरा में विश्वास करती हैं। परंतु जो लोग कम समय के लिए काम संभालते हैं। उनके लिए वार्षिक समीक्षा शायद प्रासंगिक न हो। जबकि जरूरत नतीजे आधारित लक्ष्य तय करने की है। अंशकालिक कर्मचारियों के लिए भी प्रतिपुष्टि तीव्र होनी चाहिए। खासतौर पर उनके लिए जिनका कौशल उन्नत होता है वे यह जानना चाहते हैं कि क्लाइंट उनके काम से खुश है या नहीं। ऐसे में नेतृत्व संस्कृति में बदलाव लाकर उसे अधिक सहयोगात्मक और साझेदारी वाला बनाना होगा। दूसरा पहलू पूर्णकालिक कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने का है। उन्हें ऐसे अंशकालिक कर्मचारियों की भर्ती से आशंकित नहीं होना चाहिए। पूर्णकालिक कर्मचारियों की तात्कालिक प्रतिक्रिया तो प्रतिरोध की होगी। ऐसे में उन्हें इस बदलाव के बारे में अच्छी तरह बताया जाना चाहिए कि बाहरी लोग उनके स्थानापन्न बनने नहीं आ रहे हैं।

मिलीजुली श्रमशक्ति में स्थायी और अंशकालिक दोनों तरह के कर्मचारी हो सकते हैं। ये अलग-अलग जगह पर रहकर एक ही परियोजना में काम कर सकते हैं। वे अबाध रूप से काम करें यह तय करने के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सभी कर्मचारी एक दूसरे से जुड़े रहें। दो तरह के कर्मचारियों के बीच पूर्ण सांस्कृतिक एकीकरण के साथ यह व्यवस्था विश्वसनीय होगी। इन्हें यथासंभव एक दूसरे के साथ जोड़े रखने का प्रयास होना चाहिए।

लब्बोलुआब यह है कि सन 2020 ऐसे ही गिग कर्मचारियों का वर्ष साबित हो सकता है। कंपनियों की बात करें तो उनके लिए भी नई कर्मचारी भर्ती व्यवस्था बेहतर होगी। अमेरिकी मानव संसाधन कंपनी मर्सर के मुताबिक गिग मॉडल में अधिक लचीलापन है, इससे तयशुदा लागत में कमी आती है और बदलाव को लेकर प्रतिक्रिया देने की क्षमता सुधरती है। इसमें एक अवसर यह भी छिपा है कि मांग के अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं और विशेषज्ञों को साथ जोड़ा जा सके। आने वाले दिनों में वही कंपनियां सफल होंगी जिनके पास मांग और जरूरत के अनुसार गिग कर्मियों को साथ जोड़ने की क्षमता होगी।

कानाफूसी

राजद का सुरक्षित ठिकाना

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को वर्ष 2013 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने मवेशियों के चारे की खरीद तथा वितरण के लिए आवंटित धन के गबन से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराया था। इसमें बिहार के विभिन्न स्थानों से पैसे निकालने के अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे और अंत में सीबीआई अदालत ने उन्हें लगभग 14 साल की जेल की सजा सुनाई थी। लेकिन इस मामले में एक रोचक मोड़ है। फिलहाल वह रांची जेल में हैं। पिछले पांच वर्षों तक राज्य में रघुबर दास के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस दौरान राज्य के अधिकारियों से उन्हें 'अपेक्षित तवज्जो' नहीं मिली। लेकिन पहले, जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तो उन्हें जेल से सरकारी अतिथि गृह में भेज दिया गया था जहां उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई थीं। अब एक बार फिर सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शायद ही किसी को अचरज हुआ हो, जब लालू ने सोरेन को चुनाव जीतने की गर्मजोशी से बधाई दी और भाजपा के भविष्य को लेकर गंभीर भविष्यवाणी की थी। इन चुनावों में लालू की पार्टी राजद और सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच गठबंधन हुआ और इस बात की काफी संभावना है कि जेल से जुड़ा विभाग राजद के पास जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी राजद कोई बेहतर उपाय खोज लेगा। इससे, बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर चर्चा तथा राय के लिए लालू प्रसाद की राजनीतिक विशेषज्ञता आसानी से उपलब्ध होगी। यह सब इस बात पर भी निर्भर करता है कि यह कदम कितनी जल्दी उठाया जाता है और लालू प्रसाद को 'तरजीह' दिए जाने पर कोई अदालत का दरवाजा तो नहीं खटखटाता है।

आपका पक्ष

जल संरक्षण की नई अटल योजना

केंद्र सरकार ने पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 95वें जन्मदिन पर अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य गिरते भूजल का स्तर रोकना और जल संरक्षण करना है। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है कि उसने गिरते भूजल स्तर और पानी की कमी को दूर करने के लिए सही समय पर कदम उठाया है। इस योजना को जमीन पर लाने के लिए सरकार को पर्याप्त समय मिलेगा जिससे पानी को संरक्षित किया जा सकेगा। इसके लिए कई दिशानिर्देश मिलेंगे जिनसे जल संरक्षण किया जा सके। इनमें मुख्य रूप से सूक्ष्म सिंचाई, पेयजल के लिए नई तकनीक का उपयोग कर पानी को शुद्ध करना आदि है। हमें पानी की बरबादी को कम करना है। इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर से निकलने वाले पानी को आंगन में गड्ढा बनाकर डालना चाहिए। इससे नालियों से बहने वाला गंदा पानी का जल संरक्षण में इस्तेमाल हो सकेगा जिससे भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान पर गड्ढे बनाए जाएं जो मनरेगा के तहत बनाए जा सकते हैं। इससे रोजगार भी मिलेगा और ढलानों से बहने वाले पानी का संचयन हो सकेगा। इस कदम से बंजर जमीन पर कृषि के लिए पानी उपलब्ध होगा। घरों के नलों में आने वाला पानी बहुत अधिक बरबाद होता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया

इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की तरह पानी का मीटर लगाने चाहिए जिससे पानी की बचत की आदत पड़ेगी।

रविंद्र कुमरावत, खरगोन

कृषि का राष्ट्रीयकरण

देश में बार-बार की कर्जमाफी, मुआवजे की मांग आदि के दुष्चक्र को तोड़ने तथा कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए कृषि का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। इससे रोजगार के अवसर, घरेलू सकल उत्पाद बढ़ने के साथ कृषि व कृषक दोनों की दुर्दशा भी समाप्त होगी, जो इतना कुछ करने के बाद भी खत्म नहीं हो रही है।

श्याम शालिग्राम शर्मा, इंदौर

आज भी दूसरों देशों पर निर्भर भारत

देश की 50 प्रतिशत आबादी शिक्षित नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे का अभाव होता है। इस वजह से विज्ञान में हमारे वैज्ञानिकों के हाथ दूसरे देशों के मुकाबले तंग है। इससे देश में वैज्ञानिक खोज काफी कम हो पाती है। नई तकनीक के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। हम फ्रांस से लड़ाकू विमान राफेल खरीदते हैं। रूस के साथ मिलकर उनकी तकनीक के सहारे राइफल बनाने का कारखाना स्थापित करते हैं। कृषि उन्नति के लिए जर्मनी के साथ कृषि तकनीक के लिए समझौता करते हैं। दो दशक पहले राकेश शर्मा को अंतरिक्ष भेजना भी दूसरे देशों की मदद के कारण ही संभव हो सका था। दूसरे देशों पर निर्भरता के कारण पाकिस्तान और चीन को शांत नहीं करा पाना भी एक समस्या है। देश में कई बच्चे अपने परिवार के साथ भूखे सोते हैं। ऐसे में उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा। ऐसे परिवारों के पास डॉक्टर के पास जाने तक की फीस नहीं होती है। अशिक्षित होने के कारण उन्हें उचित काम भी नहीं मिल पाता है जिससे कम आमदनी के कारण वे जैसे तैसे अपना जीवन गुजर बरस करते हैं। भारत आज भी दूसरे देशों पर निर्भर है और इस निर्भरता को खत्म करने की दिशा में प्रयास होने चाहिए।

राकेश जैन, सतना

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

सरकार ने उठाए बड़े कदम, मगर नतीजे उम्मीद से कम

दीपक शर्मा

चुनौतीपूर्ण रहा साल

कर दरों में कमी तथा ई-मूल्यांकन जैसे फैसले कारोबार के हक में किए गए। कर दरों में कमी होने से निवेश की संभावना अधिक होनी चाहिए थी पर दुर्भाग्यवश मंदी और मुद्रास्फीति ने उस पर पानी फेर दिया। इस वर्ष चुनाव और पाकिस्तान के मुद्दों ने मेक इन इंडिया को वो गति नहीं दी जिसकी जरूरत थी। कॉर्पोरेट कर में कमी नए कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त थी पर जागरूकता के अभाव में सब जस का तस बना रहा। वहीं दूरसंचार उद्योग ने आम जनता पर खासा दबाव बनाया है। सरकार की अदूरदर्शिता की वजह से व्यवसाय का नूर गायब ही रहा।

डॉ रसिकेश

जौनपुर, उत्तर प्रदेश

निराशाजनक रहा कारोबार

इस साल वाहन, विनिर्माण व इंजीनियरिंग क्षेत्र में गिरावट के कारण आर्थिक विकास दर में सुस्ती छाई रही। कंपनियों ने नई नियुक्तियों की बजाय मौजूदा कर्मचारियों की कुशलता वर्धन की ओर ध्यान दिया। परिणामस्वरूप जिन संगठनों में रोजगार बढ़ा उनकी संख्या कम रही। बाजार में सुस्ती के कारण रोजगार क्षेत्र में कमी आई। जीडीपी और अन्य आर्थिक संकेतक में गति नहीं आ सकी। धनतेरस, दीवाली, शादी विवाह के अवसरों पर जरूर अच्छा कारोबार हुआ। इन अवसर विशेष के अलावा कारोबार निराशाजनक रहा। अगले साल की पहली तिमाही में सुधार भी संदेहास्पद है।

एम राज राकेश

अलवर, राजस्थान

मिला जुला रहा साल

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे साल मंदी के बादल छाए रहे। भारतीय अर्थव्यवस्था भी इसकी चपेट में आ गई। इसका असर कारोबार पर भी पड़ा। कुछ क्षेत्रों में सुस्ती का माहौल बना रहा। इस संदर्भ में मूल समस्या मांग में कमी थी। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार की तरफ से कुछ उपाय किए गए मसलन रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए 25,000 करोड़ रुपये का एक कोष बनाया गया। बैंकिंग क्षेत्र को 70,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए। जीएसटी परिषद ने जीएसटी में बदलाव किए। विदेशी और निजी निवेश को आकर्षित करने के कई उपाय किए गए। इस प्रकार मंदी की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए भरसक प्रयास किए गए जिसके बाद कारोबार में सुधार के संकेत मिले।

डॉ एम एस सिद्दीकी

फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश

अब कृषि से उम्मीद

वर्ष 2019 कारोबार के लिहाज से उत्साहजनक नहीं रहा। मांग में आई कमी से सभी कारोबारी बुरी तरह प्रभावित हुए। भले ही वस्तुओं की मांग में कमी रही हो, लेकिन सोने, चांदी से लेकर आलू, प्याज तक की कीमतों में अचानक भारी तेजी आई। हालांकि, इसका लाभ कारोबारियों को नहीं मिल पाया क्योंकि कीमतों में तेजी ने मांग को और कम कर दिया। बहरहाल सरकार ने कॉरपोरेट कर कम कर कंपनियों को लाभ जरूर पहुंचाया। वाहन उद्योग ने छूट देकर अपने बलबूते पर मंदी का सामना करने का प्रयास किया। मंदी के बावजूद शेयर बाजार में उछाल आश्चर्यचकित करने वाला है। अच्छी बारिश से आगामी रबी फसल बेहतर होने के आसार हैं।

अजीत सिंह चौधरी

इंदौर, मध्य प्रदेश

उलझन भरा साल

वर्ष 2019 बहुत से लोगों के हिसाब से एक उदासीन वर्ष कहा जा सकता है। इस साल सुस्ती और मुद्रास्फीति जैसी समस्याओं से देश की अर्थव्यवस्था त्रस्त रही जिसका खमियाजा व्यापार और कारोबार दोनों को भुगतना पड़ा। जीएसटी और सरकार की नई नीतियां इस साल भी कारोबार के लिए अनुकूल नहीं रहीं। किसी भी एजेंसी की गणना के हिसाब से व्यवसाय गति नहीं पकड़ पा रहा था। सभी लोग इससे प्रभावित हुए। इस साल रोजगार की संभावनाएं भी क्षीण हुईं पर इसका मतलब ये कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि पूरे साल सब कुछ प्रतिकूल ही रहा। सरकार की नीतियां दीर्घकालिक परिप्रेक्ष में अत्यंत ही लाभकारी हैं जिसके सकारात्मक नतीजे वर्ष 2020 में आने निश्चित हैं।

डॉ आंजनेय गुप्ता

वाराणसी, उत्तर प्रदेश

मुश्किल भरा साल

विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से भारत भी इस साल अछूता नहीं रहा। जीएसटी और नोटबंदी के प्रभाव से इस साल भी कारोबारी और आम आदमी त्रस्त रहे। दीवाली पर भी बाजारों से रौनक गायब रही क्योंकि सस्ते चीनी उत्पादों ने भारतीय बाजारों पर लगभग कब्जा कर लिया था। रही सही कसर ऑनलाइन खरीदारी में कार्यरत ई-कॉमर्स की नामी गिरामी कंपनियों ने ग्राहकों को भारी छूट, सेल, महासेल का लालच देकर पूरी कर दी। सरकार ने रियल एस्टेट को 25 हजार करोड रुपये, बैंकों में 70 हजार रुपये का पूंजी निवेश, आयकर में छूट, कॉरपोरेट कर में कमी, सुपररिच चार्ज का खात्मा कर अपने स्तर पर मंदी से लड़ने का भरपूर प्रयास किया। इससे कारोबार ठीक ठीक चला।

अनिल कोथुलकर

इंदौर, मध्य प्रदेश

दशक का उथल पुथल भरा साल

वर्ष 2019 पिछले एक दशक का सबसे अस्थिर साल रहा। नोटबंदी से अभी व्यवसायी उबरे भी नहीं थे कि इधर जीएसटी कानून और इसके करों को निर्धारित करने वाले घटकों को लेकर उहापोह की स्थिति बरकरार रही। भारत जैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश मे पूंजीवादी व्यवस्था की सोच लेकर जो सरकार चल रही है उसके विरोधाभास से उपजे संकट के कारण कारोबार और कारोबारी दोनों के लिए अनिश्चय की स्थिति रही। वैसे सरकार अभी भी कई करों की समीक्षा कर रही है जो कि शायद आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम लेकर आए। कारपोरेट कर की दरों में कटौती के लाभ अभी तो दिखे नहीं है। वर्ष 2020 में कारोबार सुधर सकते हैं अगर कारोबारियों में सुरक्षा का भाव पैदा हो और निवेशक भी निश्चिंत भाव से निवेश कर सकें।

डॉ राम हर्ष गुप्त

मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

प्रयोग हुए, परिणाम आने बाकी

सरकार आगामी वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 खरब अमेरिकी डॉलर के बराबर करने की जद्दोजहद करती दिखी। इसी के तहत डीजल के दामों में जब गिरावट आई तो महंगाई पर अनुकूल प्रभाव देखने की आशंका जताई जा रही थी। परंतु रोजमर्रा की जरूरतों तथा खाद्य सामग्री पर इसका बहुत अनुकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला। सरकारी बैंकों का विलय कर उसे 27 से 12 पर अच्छी पहल रही। इस साल अर्थव्यवस्था में कई प्रयोग देखने को मिले। अलग-अलग परियोजनाएं बहुत कम अंतराल पर लागू की गईं जिसके सार्थक परिणाम आने बाकी हैं। अब देखना यह है कि वर्ष 2019 में आयकर तथा कॉरपोरेट कर की दरों में बदलाव देश के लिए कितना हितकारी साबित होता है। अंतत: कारोबार की दृष्टि से अर्थव्यवस्था मिश्रित रही। कारोबार को अब सिर्फ आक्रामक बिक्री और मार्केटिंग रणनीति से ही सुधारा जा सकता है। पर वर्ष 2019 की भरपाई कर पाना फिलहाल संभव नहीं दिखता ।

दिव्या सेठी

नोएडा, उत्तर प्रदेश

कारोबारी सुगमता के लिए अच्छा साल

विश्व बैंक द्वारा जारी कारोबारी सुगमता सूचकांक में भारत को वर्ष 2019 में 190 देशों में से 63 वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस वर्ष भारत ने 14 स्थान के सुधार के साथ अपने स्कोर को भी 71.0 कर लिया है। हमारा देश लगातार तीसरे वर्ष कारोबार वातावरण में सुधार करने वाली शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल है। इस सूची में भारत को प्रदर्शन के आधार पर विशेष रूप से सराहनीय श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया। इन सबके बावजूद भारत को इस वर्ष के सूचकांक में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, क्योंकि भारत का उद्देश्य इस वर्ष सूचकांक के शीर्ष 50 में स्थान प्राप्त करना था, जो संभव नहीं हो पाया। वर्तमान समय में देश की कम विकास दर भी एक चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि इससे बेरोजगारी, कम उत्पादन जैसी अहम समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं।

सुधीर कुमार सोमानी

देवास, मध्य प्रदेश

धीमी कारोबार वृद्धि

भारत की जीडीपी वृद्धि दर वैसे तो दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल रही लेकिन वर्ष 2019 में इसकी रफ्तार बहुत धीमी रही जो कारोबार के लिए अच्छा नहीं है। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर बात है। 2019 में साल की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी 4.5 फीसदी रही है। जीडीपी वृद्धि दर में लगातार छह तिमाही में गिरावट देखी गई है। इस साल महंगाई भी पलटी मारती दिखी तो बेरोजगारी दर में भी बढ़त देखी गई। हालांकि शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सेसेंक्स ने 41,000 अंक को पार किया तो वहीं निफ्टी ने 12,000 के नए रिकॉर्ड स्तर को छू लिया। विदेशी निवेशकों का भी भारतीय बाजार कारोबार में भरोसा घटा है। ऑटो, दूरसंचार जैसे रोजगार देने वाले क्षेत्र भी मंदी की चपेट में रहे।

अमित जायसवाल

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

म्युचुअल फंड के लिए अच्छा

म्युचुअल फंड कंपनियों के प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (एयूएम) में इस साल जोरदार इजाफा हुआ है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से निवेशकों का भरोसा कायम करने के लिए उठाए गए कदम तथा ऋण योजनाओं में मजबूत प्रवाह से म्युचुअल फंड उद्योग की यह रफ्तार अगले साल भी जारी रहेगी। ऋण आधारित योजनाओं में भारी निवेश की वजह से वर्ष 2019 म्युचुअल फंड उद्योग के लिए एक अच्छा वर्ष साबित हुआ है। बाजार में उतार-चढ़ाव की वजह से इक्विटी कोषों में इस साल निवेश का प्रवाह घटा है। म्युचुअल फंड कंपनियों के प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां वर्ष 2019 में 18 प्रतिशत बढ़कर नवंबर के अंत तक 27 लाख करोड़ रुपये सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गईं। 2019 लगातार सातवां साल रहा है जब म्युचुअल फंड उद्योग का एयूएम बढ़ा है। लेकिन आर्थिक सुस्ती, क्रेडिट संकट और बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए यह तेजी उल्लेखनीय है।

कुमारी कबिता

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

कारोबारी सुगमता से मिलेगी राह

कारोबारी लिहाज से वर्ष 2019 को देखने के लिए दो पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला कारोबार में वृद्धि, दूसरा कारोबारी सुगमता। अगर वृद्धि की बात की जाए तो यह नकारात्मक रही जो पहली और दूसरी तिमाही के आंकड़े बता रहे हैं। कारोबारी जगत की रीढ़ निर्माण क्षेत्र तो नकारात्मकता का रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। लेकिन वैश्विक रूप में देखें तो चीन अमेरिका व्यापार युद्ध से भी कारोबारी लाभ लेने के मौके थे किंतु वो फायदा भी हमसे ज्यादा ताइवान, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन जैसे राष्ट्रों व राष्ट्र समूहों ने ज्यादा अच्छे से भूनाया। हालांकि भारत ने भी 755 मिलियन डॉलर का निर्यात कर इस समय का सदुपयोग करने की कोशिश की है। वहीं हम दूसरे पहलू को देखें तो विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता सूचकांक में रिकॉर्ड स्तर पर सुधार हुआ। बहरहाल यह कहने में कोई दो राय नहीं कि कारोबारी मंदी की मार देश झेल रहा है और पूरे साल इस परिस्थिति से झूझता रहा है। कारोबारी सुधार इस स्थिति से बाहर आने का मार्ग जरूर बन सकता है।

कृष्ण चंद्र त्रिपाठी

उज्जैन, मध्य प्रदेश

प्रमुख आर्थिक ताकत बनने की ओर

देश में इस साल आर्थिक मंदी की सुगबुगाहट के बीच अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लिए राहत भरी खबर है कि विश्व बैंक की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 63वें स्थान पर है। यह उपलब्धि 14 पायदान के सुधार के साथ हुआ है। भारत इस साल शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में भी शामिल है। अगर सभी जिला और राज्य अपने यहां कारोबार को आसान बनाते तो इसका सीधा असर भारत की रैंकिंग पर भी पड़ता। कारोबार की सुगमता में किसी देश की रैंकिंग के जो 10 पैमाने होते हैं उसके 10 में से 7 संकेतकों में विश्व के सबसे अच्छे मानकों में भारत और करीब पहुंचा गया है। रैंकिंग सुधारने की वजह से भारत एशिया का प्रमुख आर्थिक ताकत के तौर पर उभर सकता है। कुल मिलाकर बेहतर कारोबारी माहौल से विदेशी निवेश भी बड़े पैमाने पर भारत आ रहे हैं।

अजीत कुमार गौतम

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

बकौल विश्लेषक

सरकार ने उठाए जरूरी कदम, हालांकि चुनौतियां रहीं बरकरार

साल 2019 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए केंद्र सरकार द्वारा बहुत सी नई योजनाएं शुरू की गईं। इनमें ब्याज दरों में 2 प्रतिशत की छूट, 25 करोड़ रुपये तक के कर्ज का पुनर्गठन, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी योजना, 59 मिनट में कर्ज मिलने की सैद्धांतिक मंजूरी देना और सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एमएसएमई उद्योग से खरीदे जाने वाले सामान की सीमा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना आदि शामिल हैं। इन सभी कदम से छोटे तथा मझोले उद्योगों को अपना कारोबार बढ़ाने में काफी मदद मिली है। हालांकि वैश्विक स्तर पर आई आर्थिक मंदी और बैंकों द्वारा क्रेडिट सुविधा देने के लिए सक्रियता नहीं दिखाने के कारण एमएसएमई उद्योग बेहतर प्रगति नहीं कर पा रहा है। एक समस्या यह भी है कि सरकारी कंपनियों, सरकारी विभागों और बड़े कारोबारी समूहों के पास लंबे समय से एमएसएमई उद्योगों का बकाया शेष है जिसका भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 'एमएसएमई फॉर्म 1' जारी किए जाने से भुगतान में देरी की समस्या को काफी हद तक सुलझाने का प्रयास किया गया है। प्रदूषण मानकों के चलते भी एमएसएमई उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि उन्हें निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए डीजल इंजन चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि इस साल वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) ने एक सीमा तक एमएसएमई उद्योग की मदद की है लेकिन कुछ चुनौतियां बरकरार हैं। एमएसएमई कंपनियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें इनवॉइस जारी होते ही जीएसटी चुकाना होता है, भले ही उस संबंधित इनवॉइस का भुगतान हुआ हो अथवा नहीं। हालांकि उम्मीद है कि आगामी वर्ष में इन सभी चुनौतियों का समाधान कर लिया जाएगा और सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए जाने वाली सकारात्मक पहल से एमएसएमई उद्योग का भविष्य बेहतर होगा।

बातचीत: **वीरेश्वर तोमर**

मुकेश मोहन गुप्ता

अध्यक्ष, चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल ऐंड मीडियम एंटरप्राइजेज

सकारात्मक बदलावों के लिए याद किया जाएगा 2019

साल 2019 राजनीतिक और कारोबारी लिहाज से भारी उतार चढ़ाव वाला साल रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह साल छोटे-बड़े सभी कारोबारियों के लिए मुश्किल भरा साल रहा, नीतियों में बदलाव के कारण कारोबारियों को नुकसान हुआ और कई कारोबार प्रभावित हुए। बैंकिंग सिस्टम में सुधार के लिए बैंकों के पूंजीकरण और समावेशन शुरू किए गए। साथ ही आईबीसी अध्यादेश 2019 भी लाया गया। कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस से पहले किए गए अपराध के लिए कॉर्पोरेट देनदार का दायित्व समाप्त हो जाएगा। इस कदम का उद्देश्य दिवाला संकल्प प्रक्रिया को आसान बनाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। 2014 में हम 142वें स्थान पर थे और उछलकर 63वें स्थान पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक बार सभी संरचनात्मक सुधार होने के बाद, हम विदेशी निवेश आकर्षित करने में सक्षम होंगे और साथ ही दुनिया भारत को निर्माण के हब के रूप में देखना शुरू करेगी और इस तरह, हमारे लिए 5 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त होगा। इस साल शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, बीएसई सेंसेक्स 41,164 अंकों के शिखर पर पहुंच गया। आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की लेकिन बैंकों द्वारा ग्राहकों को ब्याज दरों का अंतिम प्रसारण आवश्यक है। बिग बैंग कॉर्पोरेट कर की दर 22 फीसदी तक कम की गई जिससे भारत में करों की दर दुनिया भर में सबसे कम हो गई। दिसबंर 2018 में विदेशी मुद्रा भंडार 393 अरब अमेरिकी डॉलर था जो दिसंबर 2019 में बढ़कर 453 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। मेरा विश्वास है कि यदि हम 5 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी विकास दर और तेज होगी। संरचनात्मक नीति सुधार तेज गति से किए जा रहे हैं और यह सरकार व्यापार और उद्योग को सुन रही है जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कारोबारियों को सफल होने के लिए नए ढांचे के साथ पारदर्शी तरीके से काम करना होगा। अब हम 2020 में एक नए दशक की शुरुआत में हैं और 2020 में एक स्पष्ट दृष्टि के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ब्याज दरें, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी पर ध्यान देना होगा। हमें निडर होकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना होगा क्योंकि हमारे पास एक बड़ा बाजार है और जनसांख्यिकी भी हमारे पक्ष में है। हमें कड़ी मेहनत से सफलता पानी है।

बातचीत: **सुशील मिश्र**

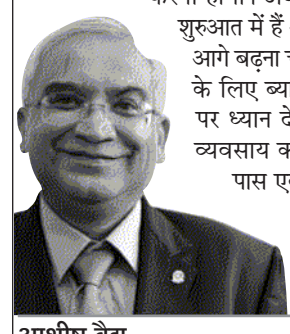

आशीष वैद्य

अध्यक्ष - आईएमसी

पुरस्कृत पत्र

कारोबार पर आर्थिक मंदी की मार

साल 2019 में कारोबार की बात की जाए तो मोदी सरकार ने अपनी दूसरी पारी में पहली पारी के नोटबंदी और जीएसटी से जो देश के कारोबार को नुकसान हुआ था, उसके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। सरकार ने कॉरपोरेट कर में कटौती की। रिजर्व बैंक ने भी मोदी सरकार को वित्तीय सहायता देकर देश को आर्थिक मंदी से उबारने में मदद की। हालांकि, सरकार केंद्रीय बैंक की सहायता या अन्य उपायों से देश को आर्थिक मंदी से उबारने में सक्षम नहीं हो सकी। यह बात जीडीपी की वृद्धि दर मात्र 4.5 प्रतिशत रह जाने से स्पष्ट हो जाती है। कृषि और घरेलू उद्योगों के प्रति सरकारों की सुस्ती भी देश की आर्थिक सुस्ती का कारण है। कृषि क्षेत्र में सुधार नहीं किया गया, तभी तो देश को प्याज और अन्य सब्जियों की भारी कीमतों का सामना करना पड़ा। अगर सरकार इस तरफ भी गंभीर हो तो यह आर्थिक सुस्ती को तोड़ने में महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

राजेश कुमार चौहान
जालंधर, पंजाब

पुरस्कार राशि
500 रुपये

श्रेष्ठ पत्र

संजय डागा
इंदौर, मध्य प्रदेश

आर्थिक मंदी में भी नियंत्रित रहा बाजार

वर्ष 2019 में ऑटो, बैंकिंग, एनबीएफसी, रियल्टी और एफएमसीजी क्षेत्र इस आर्थिक संकट से पूरे साल जूझते रहे, हालांकि सरकार ने कॉरपोरेट कर में कटौती और बैंकिंग क्षेत्र को राहत पैकेज भी दिए, पर यह सब मंदी के दौर में ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुए। आर्थिक मंदी के बावजूद इस साल देश के शेयर बाजार ने रिकॉर्ड ऊंचाइयों को पार कर नया कीर्तिमान कायम किया। सोने और चांदी ने भी इस साल करीब 23 फीसदी प्रतिफल दिया और पहली बार सोने ने 40,000 रुपये और चांदी ने 50,000 रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। इस मंदी के दौर से निपटने के लिए सरकार भी सभी फॉर्मूले पर वर्ष भर काम करती रही और कुछ हद तक सरकार की कोशिशें सराही भी गईं।

प्रदीप माथुर
अलवर, राजस्थान

नहीं हुआ सुधार, फीका रहा कारोबार

वर्ष 2019 में भी न तो नोटबंदी और जीएसटी के दिए गए पुराने घाव ही भर पाए और न ही उपयुक्त जमीन ही तैयार हो पाई। सरकार अर्थव्यवस्था को कारोबारियों के अनुकूल बनाने के लिए प्रयास करती रही, वहीं कारोबारियों से नियमबद्ध रहने की अपेक्षा में कई तरह से जुर्माने लगाने में भी जुटी रही। रियल एस्टेट उद्योग नोटबंदी के बाद से खराब स्थिति में है। इसमें सुधार के लिए इस साल प्रयास भी हुए। इधर दूरसंचार कंपनियों ने कॉल दरों में इजाफा कर महंगाई से त्रस्त जनता की परेशानी और बढ़ाई। पेट्रोलियम पदार्थों, फल, सब्जियों के बढ़ते दामों ने भी कारोबार को प्रभावित किया। क्रय क्षमता घटने से विभिन्न कारोबारों पर विपरीत प्रभाव देखा गया। सुधार के लिए आशान्वित कारोबार पटरी पर आकर गतिमान नहीं हो सका।

उद्देश्य
पटना, बिहार

संतोषजनक रहा साल 2019

वर्ष 2019 में न ज्यादा प्रगति देखने को मिली है न ज्यादा गिरावट। कुल मिलाकर कहा जाए तो कारोबार के लिहाज से साल संतोषजनक रहा। लेकिन अंत में कुछ खास प्रगति देखने को नहीं मिली बल्कि बहुत से कारोबार बंद होने लगे। बाजार में मांग घटने से ऑटोमोबाइल क्षेत्र, कपड़ा उद्योग में कई इकाइयां बंद होने से काफी बेरोजगारी फैल गई। बाजार में निवेश घट गया। सरकार ने कॉर्पोरेट कर में कमी की किंतु यह भी ज्यादा सफल नहीं रही। सकारात्मक बात यह रही कि लगातार दूसरे साल विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत ने सुधार किया है। इस साल भारत की रैंकिंग 23 स्थान के सुधार के साथ 77वीं रही। इससे पहले 2018 की रिपोर्ट में भारत 100वें पायदान पर था।

सूर्यभानु बांधे
रायपुर, छत्तीसगढ़

मंदी के दौर ने कारोबार को किया प्रभावित

कारोबार की दृष्टि से इस वर्ष लाभ और नुकसान दोनों का समन्वय रहा। मंदी के दौर ने पूरे कारोबार जगत को प्रभावित किया। एनपीए की समस्या बरकरार है, एनबीएफसी में नकदी की कमी रही। जीडीपी में सुस्ती देखी गई जो अनेक तिमाहियों की तुलना में निम्न स्तर पर रही। बेरोजगारी की दर 45 वर्षों में सबसे ज्यादा 6.1 फीसदी रही। ऑटोमोबाइल क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हुआ। सरकार ने मंदी से उबरने और अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए कई कदम उठाए। आरबीआई ने रीपो दर में कुल 135 आधार अंकों की कमी की, सरकार ने सरकारी बैंकों में 75,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जिससे बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ हो सके और उद्योग एवं कारोबार जगत को राहत देते हुए कार्पोरेट दर में कमी की।

... और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी नाम का विशेष पृष्ठ प्रकाशित करते हैं। इसमें आपके विचारों को प्रकाशित किया जाता है। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय।

इस बार का विषय है –

नए साल से आर्थिक और कारोबारी उम्मीद ?

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें:
बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002

फैक्स नंबर- 011-3720201
या फिर ई-मेल करें
goshthi@bsmail.in

एक से ज्यादा कार्ड रखें पर इन बातों का ध्यान रहे

आपके क्रेडिट स्कोर पर इस बात का बड़ा असर पड़ता है कि आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं और आप उनका इस्तेमाल किस तरह करते हैं

बिंदिशा सारंग

आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी कि कर्ज कभी नकद जितना अच्छा नहीं हो सकता। फिर भी आज हमारे बटुए में पड़े क्रेडिट कार्ड की कीमत बहुत अधिक है। अब कोई यह नहीं पूछता कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या नहीं। अब सवाल यह है कि कितने कार्ड होने चाहिए? केवल एक या ढेरों कार्ड? आपके पास कितने कार्ड हैं और आप उनका इस्तेमाल किस तरह करते हैं, इसका सीधा असर आपके क्रेडिट स्कोर यानी आपकी साख पर पड़ता है। इसीलिए कार्ड के बारे में सही चुनाव करना बेहद जरूरी है।

कैसे संभालें ढेर सारे क्रेडिट कार्ड

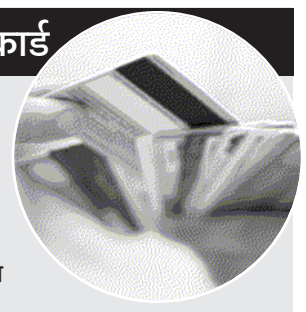

- हरेक कार्ड पर पूरी बकाया रकम चुकाएं और बकाये को अगले महीने के बिल में न जाने दें ताकि आप कर्ज के जाल में नहीं फंसें
- अपने सभी कार्डों में मौजूद समूची क्रेडिट लिमिट का कभी पूरा इस्तेमाल नहीं करें और न ही इतना इस्तेमाल कर लें कि लिमिट खत्म होने के कगार पर आ जाए
- अगर आप क्रेडिट या कर्ज के मामले में नौसिखिये हैं तो साल भर केवल एक ही कार्ड रखें। जब कार्ड इस्तेमाल करने की तमीज आ जाए तो दूसरा कार्ड ले लें
- अगर आप कई क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वे कार्ड ही चुनें, जिनकी आपको जरूरत है और जिनका शुल्क आप चुका सकते हैं

आपकी उम्र क्या है?

अगर हम इस्तेमाल करने वाले की उम्र जानते हैं तो कई सवालों के जवाब एकदम सीधे मिल जाते हैं। मनीमंत्रा के प्रबंध निदेशक राज खोसला का कहना है, 'पिछले दो दशकों में जन्मे जिन युवाओं के लिए कर्ज एकदम नई बात है, उनके पास एक कार्ड होना चाहिए। इसका इस्तेमाल समझदारी के साथ किया जाए, वक्त पर बकाया चुकाया जाए और अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री तथा स्कोर तैयार किया जाए ताकि आगे चलकर बेहतर शर्तों पर कर्ज हासिल किया जा सके।'

अगर आपने पहले कभी कर्ज नहीं लिया है तो केवल एक कार्ड लेकर उसका ककहरा सीखना बेहतर है। अगर आप दूसरा कार्ड भी लेना चाहते हैं तो पहले खुद से पूछिए कि आपको वाकई उसकी जरूरत है या नहीं। कई बार आपको दूसरे क्रेडिट कार्ड की जरूरत ही नहीं होती। कुबेरा के मुख्य कार्य अधिकारी आदित्य कुमार समझाते हैं, 'क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल गैर जरूरी खर्च और रोजमर्रा के खर्च में ही किया जाता है। हर महीने पूरा बकाया चुकाना चाहिए ताकि करीब 40 फीसदी सालाना की महंगी दर से ब्याज नहीं देना पड़े। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर्ज के तौर पर मत कीजिए। आप कार्ड पर खर्च कर मासिक किस्त बनवा सकते हैं मगर यह 12 से 18 फीसदी की ब्याज दर पर मिलने वाले उपभोक्ता ऋण या पर्सनल लोन के मुकाबले महंगी ही पड़ेगी।'

यह तो युवाओं के लिए सलाह हो गई, लेकिन दूसरे लोगों को क्या करना चाहिए? इंडियालेंड्स के मुख्य कार्य अधिकारी गौरव चोपड़ा सरल गणित में बताते हैं, '20 साल की उम्र में ज्यादा से ज्यादा दो कार्ड हों, 30 साल की उम्र में अधिक से अधिक चार। आपके पास कभी इससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड नहीं होने चाहिए।'

कर्ज का इस्तेमाल असली कुंजी

यह अहम नहीं है कि आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं, अहम बात यह है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर तौर पर एक ही कार्ड आपके लिए काफी है। कुमार की सलाह है, 'अगर आप बार-बार अपने कार्ड की पूरी क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल करने के करीब पहुंच जाते हैं तो एक और कार्ड ले लीजिए। अगर आपके कार्ड पर बकाया बहुत अधिक है और क्रेडिट लिमिट के आसपास है तो वक्त पर बकाया चुकाने के बाद भी आपके क्रेडिट स्कोर पर इसका असर पड़ेगा।' अगर आपके पास केवल एक कार्ड है और आप इसकी 95 फीसद क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल कर चुके हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर कुछ कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक से अधिक कार्ड हैं आपने दोनों की क्रेडिट लिमिट का केवल 60 फीसदी तक ही इस्तेमाल किया है तो आपका इस्तेमाल का अनुपात अच्छा रहेगा।

कई बार व्यक्ति की जरूरतें केवल एक कार्ड से पूरी नहीं होतीं। इसलिए आपकी पसंद के यानी कस्टमाइज्ड विकल्प भी मौजूद हैं। लोग केवल सुविधा के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं लेते, उसके साथ ही उन्हें रिवार्ड भी मिलते हैं। खोसला बताते हैं, 'कई कार्ड होने का एक फायदा यह ह कि आप कई रिवार्ड योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे अच्छे यात्रा लाभ, ऑनलाइल डील, कैशबैक, छूट आदि देने वाले कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कई कार्डों का इस्तेमाल समझदारी से करने के गुर पता हैं तो आपको ब्याज मुक्त रकम भी मिल सकती है और ढेर सारे रिवार्ड भी हासिल हो सकते हैं।'

अगर आप कई क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वे कार्ड ही चुनें, जिनकी आपको जरूरत है और जिनका शुल्क आप चुका सकते हैं। ढेर सारे कार्डों पर अच्छा खासा बकाया होने का मतलब है कि आप क्रेडिट का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं यानी आप कर्ज लेने के आदी हैं। इस सूरत में आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा।

कुमार बताते हैं, 'अलग-अलग बैंक अलग-अलग समय पर क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी देते हैं। मान लीजिए किसी कार्ड में जानकारी देने की तारीख 20 है और आपने उस कार्ड का बकाया 31 तारीख को चुकाया तो बैंक 31 तक इंतजार करने के बजाय 20 को ही आपका विवरण क्रेडिट ब्यूरो के पास भेज देगा। ब्यूरो को यही पता चलेगा कि आपके कार्ड पर अच्छी खासी रकम बकाया है।' इसीलिए कार्ड एक रखना है या ढेर सारे लेने हैं, इसका फैसला यह देखकर कीजिए कि आप क्रेडिट कार्ड का कितना इस्तेमाल करते हैं। साथ ही क्रेडिट यानी कर्ज के इस्तेमाल का अनुपात भी मत भूलिए।

बकाया चुकाने की तारीख ध्यान रखें

आपके क्रेडिट उपयोग अनुपात की दर और बकाया चुकाने का आपका रिकॉर्ड आपके क्रेडिट स्कोर के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम पहलू होते हैं। खोसला का मशविरा है, 'अलग-अलग बिलिंग चक्र रखिए। यदि किसी कार्ड का बिल 30 तारीख को बनता है तो दूसरे कार्ड में बिल की तारीख महीने के बीच में रखने के लिए कहिए। यदि 10 तारीख को आपको कार्ड के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है तो वह कार्ड मत निकालिए, जिसका बिल 5-10 दिन में बनने वाला है। उस कार्ड का इस्तेमाल कीजिए, जिसका बिल करीब महीने भर बाद चुकाना होगा। अगर आप हरेक कार्ड का पूरा बकाया चुकाते रहते हैं तो आप ढेर सारे कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, मुफ्त फायदे उठा सकते हैं और आपको कभी ब्याज भी नहीं चुकाना होगा।' हालांकि केवल एक कार्ड हो तो बिल याद रखना और चुकाना कई कार्डों के मुकाबले आसान रहता है। कई कार्ड होने पर आपको हरेक के रिवार्ड कार्यक्रम, बिल की तारीख और भुगतान की तारीख याद रखनी पड़ती है। इसलिए एकदम पेशेवर व्यक्ति की तरह जांचिए कि आप कई कार्डों का बकाया चुका पाएंगे या नहीं। अगर ज्यादा कार्ड संभालना आपके वश की बात नहीं है तो केवल एक कार्ड रखिए।

चोपड़ा इस बारे में आगाह करते हैं, 'यदि आप ढेर सारे कार्डों का इस्तेमाल समझदारी से नहीं करते हैं तो हरेक कार्ड का बकाया अगले महीने के बकाये में जुड़ता रहेगा (क्रेडिट रोलओवर) और आप कर्ज के जाल में फंस जाएंगे।'

आपको खुद से ही यह सवाल भी करना होगा कि इन सभी कार्डों पर आप कुल कितना शुल्क चुका सकते हैं और वह शुल्क ज्यादा कार्ड रखने से होने वाले फायदों पर भारी तो नहीं पड़ रहा है। कुमार बताते हैं, 'प्रीमियम कार्ड पर जो फायदे मिलते हैं, उनकी कीमत शुल्क के तौर पर अदा की गई रकम से कई गुना होती है। लेकिन अगर आप फायदों का इस्तेमाल ही नहीं करते तो वह कार्ड आपके लिए बेकार है।' अगर आप कई कार्ड रखना चाहते हैं तो उसमें से एक बिना शुल्क का कार्ड होना चाहिए और दूसरा प्रीमियम कार्ड, जो आपकी जरूरत या इस्तेमाल के मुकाबिक फ्यूल कार्ड या ट्रैवल कार्ड हो सकता है।

शिशु की देखभाल में फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान फायदेमंद

संजय कुमार सिंह

स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ रहा है और यह केवल बड़े-बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं रह गया है। इन दिनों अस्पताल माता-पिता पर बच्चों (छोटे शिशु से लेकर स्कूल जा रहे बच्चों की) की सालाना स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए जोर दे रहे हैं। अस्पतालों ने ऐसी जांच के लिए अलग-अलग पैकेज भी तय कर रखे हैं। जिन शादी-शुदा जोड़ों के नवजात शिशु होते हैं उनके खर्च में अचानक तेजी आ जाती है।

शिशु के जन्म से पहले ही स्वास्थ्य संबंधी खर्च शुरू हो जाते हैं। सामान्य जांच के अलावा किसी नामचीन अस्पताल में सामान्य प्रसव पर 50,000 से 70,000 रुपये खर्च आ सकता है, जबकि किसी महानगर में सी-सेक्शन (शल्य चिकित्सा के जरिये प्रसव कराने का विभाग) में 1.0 से 1.5 लाख रुपये का बिल आ सकता है। पॉलिसीबाजार डॉट कॉम में बिजनेस हेड (हेल्थ इंश्योरेंस) अमित छाबड़ा कहते हैं,'ज्यादातर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां प्रसव को बीमा लाभ के दायरे में नहीं रखती हैं। इस तरह, इसका भुगतान अपनी जेब से ही करना होगा। कुछ पॉलिसियों की जद में यह खर्च आता है, लेकिन इसे लिए एक से चार वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है।'

नियोक्ता द्वारा दिए गए स्वास्थ्य बीमा में मातृत्व खर्च शामिल हो सकता है, लेकिन यह प्राय: 25,000 से 50,000 रुपये तक सीमित होता है। ज्यादातर मामलों में यह अर्याप्त साबित होता है। छाबड़ा का कहना है कि अगर आप स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, जिसमें मातृत्व सुरक्षा भी शामिल है तो विवाह उपरांत तत्काल इस दिशा में पहल करें ताकि शिशु के आने से पहले ही प्रतीक्षा अवधि निकल जाए।

शिशु के जन्म के बाद महीने में कम से कम एक बार शिशु रोग विशेषज्ञ के पास जाना पड़ सकता है। महानगरों में शुरुआती कुछ वर्षों में माता-पिता केवल सामान्य जांच और टीकाकरण पर सालाना 10,000 से 30,000 रुपये खर्च कर देते हैं। इन दिनों माता-पिता दर्द रहित टीकाकरण (पेनलेस वैक्सीनेशन) का विकल्प चुनते हैं, जिससे बच्चों को कम से कम तकलीफ होती है और टीकाकरण के बाद बुखार भी नहीं लगता है। हालांकि ऐसे टीकों की कीमत 3 से 4 गुना अधिक हो सकती है।

किसी वयस्क के मुकाबले बच्चों में संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। किसी संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर 1.5 से 5.0 लाख रुपये या इससे अधिक बिल आ सकता है। शिशु के 90 दिन के होने के साथ ही उसे फैमिली हेल्थ फ्लोटर कवर में शामिल कर लेना चाहिए। कुछ बीमा कंपनियां वर्ष में कभी भी ऐसा करने की अनुमति देती हैं और कुछ पॉलिसी के नवीकरण के समय यह सुविधा देती हैं। बाद के मामले में शिशु को बिना किसी बीमा सुरक्षा के कई महीनों तक रहना पड़ सकता है।

पॉलिसी में व्यक्तियों की संख्या बढ़ने के साथ ही बीमित राशि भी बढ़नी चाहिए। ऐसा प्रीमियम भुगतान के समय किया जा सकता है। मणिपालसिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस में उपाध्यक्ष एवं प्रमुख (उत्पाद विभाग) आशिष यादव कहते हैं,'शिशु के पॉलिसी में जुड़ने के बाद बीमित राशि कम से कम 30 से 50 प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए।'

किसी परिवार की बीमित रकम की जरूरत उसके बजट सहित कई बातों पर निर्भर करती है। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस में हेड (रिटेल अंडरराइटिंग) गुरदीप सिंह बत्रा कहते हैं, 'जिस तरह स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ रहा है उस स्थिति में 10 लाख रुपये की बीमित रकम लेने की सलाह दी जाती है। किसी परिवार को कम से कम 5 लाख रुपये बीमित रकम होनी चाहिए।'

पति-पत्नी को संतानोत्पत्ति की योजना बनाने के साथ ही संबंधित खर्चों के लिए कोष तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। हालांकि इस कोष का आकार परिवार की माली स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन फिनस्कोलार्ज वेल्थ मैनेजनर में सह-संस्थापक एवं मुख्य सलाहकार रेणु माहेश्वरी एक मोटा अनुमान आंकड़ा बताती हैं। वह कहती हैं, 'सबसे पहले पति-पत्नी को तीन से छह महीने की आय का एक आपात कोष तैयार करना चाहिए। इसके अलावा अगर पत्नी कामकाजी है तो उसे कम से कम दो वर्षों के बराबर व्यक्तिगत खर्च के लिए रकम जमा करनी चाहिए।'

रेणु के अनुसार युवा महिलाएं यह अक्सर मान कर चलती हैं कि छह महीने का मातृत्व लाभ अवकाश समाप्त होने के बाद वे काम पर दोबारा लौट जाएंगी। वह कहती हैं, 'अगर उपलब्ध समय तीन साल से अधिक है तो यह कोष तैयार करने के लिए इक्विटी फंड का इस्तेमाल करना चाहिए और समय अवधि इससे कम है तो बैलेंस्ड फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। शिशु के जन्म का समय नजदीक पहुंचने पर यह कोष लिक्विड फडों में डाला जा सकती है।'

तैयार करें शिशु कोष

- किसी नामचीन अस्पताल में सामान्य प्रसव पर 50,000 से 70,000 रुपये खर्च आ सकता है
- किसी महानगर में सीजेरियन (शल्य चिकित्सा के जरिये प्रसव कराने का विभाग) में 1.0 से 1.5 लाख रुपये का बिल आ सकता है
- पति-पत्नी को संतानोत्पत्ति की योजना बनाने के साथ ही संबंधित खर्चों के लिए कोष तैयार करना शुरू कर देना चाहिए
- कोष का आकार परिवार की माली स्थिति पर निर्भर करता है

म्युचुअल फंड का बदले प्रारूप तो बदल लीजिए अपनी रणनीति

निवेशकों को भविष्य में होने वाले बदलावों पर शोध करना चाहिए और देखना चाहिए कि नई रणनीति कितनी कारगर है

सर्वजित के सेन

सुंदरम म्युचुअल फंड ने हाल में ही अपने ग्लोबल एडवांटेज फंड का नाम बदल दिया है। अब यह फंड सुंदरम ग्लोबल ब्रांड फंड नाम से जाना जाता है। इस फंड के निवेश के रुख में भी बदलाव आया है और अब यह केवल वैश्विक शेयरों में निवेश करेगा। पहले यह फंड ऑफ फंड के रूप में विदेशी फंडों और तेजी से उभरते बाजारों के शेयरों, जिंसों एवं एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में निवेश किया करता था। सुंदरम म्युचुअल फंड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी सुनील सब्रमण्यन कहते हैं, 'इस बदलाव के बाद इस फंड में निवेश करना अपेक्षाकृत अधिक सरल हो गया है। इसकी वजह यह है कि अब नए रूप में यह केवल एक ही परिसंपत्ति श्रेणी-शीर्ष वैश्विक शेयरों- में निवेश करेगा। इससे विभिन्न परिसंपत्ति श्रेणियों और तेजी से उभरते बाजारों में दांव खेलने वाले निवेशकों का जोखिम कम हो जाएगा।'

कई दूसरी म्युचुअल फंड कंपनियां भी हैं, जिन्होंने निवेश के ढर्रे में बदलाव किए हैं या योजनाओं का आपस में विलय कर

फंडों का विलय

- कई म्युचुअल फंड कंपनियों ने निवेश के ढर्रे में बदलाव किए हैं या योजनाओं का आपस में विलय कर दिया है
- एचडीएफसी ग्रोथ फंड ने अपना नाम बदलकर एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रख दिया है
- इसके बाद एचडीएफसी प्रूडेंस फंड का इसमें विलय कर दिया गया है
- मिराई ऐसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड अब मल्टी-कैप फंड से लार्ज-एवं मिड-कैप फंड बन गया है

दिया है। उदाहरण के लिए एचडीएफसी ग्रोथ फंड ने अपना नाम बदलकर एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रख दिया है। इसके बाद एचडीएफसी प्रूडेंस फंड का इसमें विलय कर दिया गया। मिराई ऐसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड भी अब मल्टी-कैप फंड से लार्ज-एवं मिड-कैप फंड बन गया है। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अक्टूबर 2017 में म्युचुअल फंडों से जुड़े दिशानिर्देशों में कुछ बदलाव कर इन्हें अधिक तर्कसंगत बनाने की कोशिश की थी। एक अहम बात यह है कि नियमों में बदलाव के बाद इन योजनाओं के मौजूदा निवेशकों पर कोई असर नहीं हुआ है। अब सवाल खड़ा होता है कि निवेशकों को इन बदलावों को किस तरह से देखना चाहिए?

निवेश के लिए अलग-अलग माध्यम

किसी योजना के निवेश से संबंधित शर्तें निवेशकों को ध्यान में रखते हुए तय की जाती हैं। इससे निवेशक यह पूरी तरह समझ जाते हैं कि आने वाले समय में संबंधित योजना किस तरह आगे बढ़ेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों को मालूम होता है कि फंड प्रबंधक किसी खास शेयर या परिसंपत्ति श्रेणी में प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति का निवेश करेंगे। कभी-कभी किसी योजना में निवेशकों की दिलचस्पी कम हो जाती है और वे धीरे-धीरे निकलने लगते हैं। इससे निपटने के लिए भी फंड कंपनियां निवेश के ढर्रे एवं प्रारूप में बदलाव करती हैं। उदाहरण के लिए जिंस बाजार में तेजी के समय निवेशक ऐसे शेयरों की मांग कर सकते हैं, जो जिंस उत्पादकों से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि हालात बदलने के बाद ऐसी योजना अपना महत्त्व खो देती हैं। नियामक स्तर पर नियमों में बदलाव से योजनाओं का स्वरूप बदलना पड़ता है।

निवेशकों के लिए निकलने का अवसर

फंड कंपनियां निवेशकों को बाहर निकलने का मौका भी देती हैं। फंड्सइंडिया डॉट कॉम के शोध प्रमुख अरुण कुमार कहते हैं,'योजना से जुड़ी शर्तों में बदलाव के लिए नियामक की मंजूरी मिलने के बाद निवेशक बिना किसी एक्जिट लोड का भुगतान किए एक महीने के अंदर निवेश निकाल सकते हैं। हालांकि योजना से बाहर आने पर होने वाले कराधान का वहन निवेशकों को करना होगा।'

अगर आप निवेश भुनाना चाहते हैं तो जितने समय तक आपने निवेश बनाए रखा था उस आधार पर प्राप्त लाभ पर कराधान होगा। योजना में बदलाव के बाद इससे निकलना निवेशकों के लिए अनिवार्य नहीं होता है। अगर योजना में बदलाव होने के बाद भी आप उसमें बने रहते हैं तो तय नियमों का पालन करना होगा।

निवेश बनाए रखने का लाभ

योजना की मूल बातों में बदलाव निवेशकों के लिए प्रतिकूल हों यह जरूरी नहीं है। कभी-कभार बदलाव छोटे स्तर पर या केवल योजना के दायरे में विस्तार से जुड़े होते हैं। इससे योजना के प्रदर्शन पर कोई बड़ा अंतर नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जिसमें साधारण जोखिम लेने वाले किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे फंड में निवेश किया है, जो बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 200 शेयरों में निवेश करता है। अगर योजना शेयरों का दायरा छोटा कर 100 करना चाहती है तो जोखिम नहीं बढ़ेगा और यह लार्ज-कैप योजना ही रहेगी। अगर योजना शेयरों की संख्या बढ़ाकर 500 करता है तो निवेशक अपने अनुसार निर्णय ले सकते हैं। मोटे तौर पर योजना से बाहर तभी निकलें जब किसी तरह के बदलाव से आपके पोर्टफोलियो में श्रेणीगत आवंटन पर असर पड़ता है।

लक्ष्य का रखें ध्यान

योजना का प्रारूप बदलने पर प्रस्तावित बदलाव के असर को समझने की कोशिश करें। जिन योजनाओं का विलय हुआ है उनका अध्ययन निवेशकों को करना चाहिए यह भी समझना चाहिए कि अमुक योजना उसके लक्ष्यों को पूरा कर पाएगी या नहीं। वेल्थ लैडर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स में हेड (फाइनैंशियल प्लानिंग) एस श्रीधरन कहते हैं, 'मान लें कि निवेशक ने अपने बच्चे की शिक्षा के लिए पांच वर्षों में धन जुटाने का लक्ष्य रखा है। वह एक ऐसे फंड का चयन करता है, जो 60 प्रतिशत लार्ज-कैप फंड में 40 प्रतिशत शॉर्ट टर्म डेट फंड में निवेश करता है। अगर लार्ज-कैप फंड का विलय लार्ज एवं मिड-कैप में निवेश करने वाले फंड के साथ होता है तो जोखिम का स्तर भी बदलता है। इसकी वजह यह है कि इस फंड का निवेश मझोले शेयर में बढ़ जाएगा। हालांकि निवेश लक्ष्य के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, इसलिए निवेशकों को विलय के बाद ऐसी योजनाओं में बने रहने के बजाय इनसे बाहर निकल जाना चाहिए।' निवेशकों को भविष्य में होने वाले बदलावों पर शोध करना चाहिए और देखना चाहिए कि नई रणनीति कितनी कारगर है। निर्णय नहीं ले पाने पर वित्तीय सलाहकार से संपर्क करना चाहिए।

नोटबंदी, जीएसटी और अन्य चुनौतियों के बावजूद मूल्यांकन चढ़ा

विशाल छाबड़िया

दशक बाजार का प्रदर्शन

कुछ खास घटनाक्रम और नोटबंदी, जीएसटी क्रियान्वयन जैसे कुछ ढांचागत सुधारों, कुछ बड़े व्यावसायिक घरानों पर दबाव की वजह से पिछले दशक में भारतीय बाजारों में अनिश्चितता दर्ज की गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बीएसई के सेंसेक्स और निफ्टी-50 में सालाना आधार पर 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो दशक के पहले पांच वर्षों में ऊंची मुद्रास्फीति को देखते हुए औसत दर्जे का प्रतिफल है।

हालांकि मिड-कैप और स्मॉल-कैप सूचकांकों ने इस अवधि के दौरान 5 और 8 प्रतिशत के बीच प्रतिफल दिया। बाजारों में मजबूती आई है और निवेशक सतर्क हो गए हैं, लेकिन कुछ खास जोखिमों को मौजूदा समय में नजरअंदाज किया जा रहा है।

पिछले दशक से पहले वैश्विक वित्तीय संकट देखने को मिला था। वर्ष 2008 में अमेरिका स्थित लीमन ब्रदर्स के पतन के साथ इस वित्तीय संकट की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद पैदा हुए नकदी दबाव से केंद्रीय बैंकों को अपने संबद्ध देशों में कंपनियों से बॉन्ड खरीदारी के लिए बड़ी पूंजी लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा जिसे 'क्वांटीटेटिव ईजिंग' (क्यूई) करार दिया गया। यह एक निर्णायक घटनाक्रम था जिसमें ब्याज दरें घटकर शून्य के आसपास आ गई थीं और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए पैसा जुटाना सस्ता माध्यम हो गया था। बोफा सिक्योरिटीज में भारतीय इक्विटी रणनीतिकार संजय मुकीम का कहना है, 'कई तेजी के दौर के साथ पिछले 10 वर्ष वैश्विक इक्विटी के लिए असामान्य अवधि रही। सभी वैश्विक इक्विटी बाजारों में घटनाक्रम वृद्धि के रुझानों के बजाय केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियों से ज्यादा संबद्ध रहे।'

हालांकि, वैश्विक रूप से अर्थव्यवस्थाएं चिंताओं से बाहर निकलती नहीं दिख रही हैं। इसका एक संकेतक यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फेडरल रिजर्व द्वारा क्यूई वापस लिए जाने और ब्याज दरें बढ़ाने के बाद मंदी का सामना करना पड़ा। अर्थव्यवस्था में नकदी डाले जाने से भारतीय बाजारों को भी फायदा हुआ, हालांकि आर्थिक और कॉरपोरेट आय वृद्धि की रफ्तार धीमी बनी रही। मुकीम का मानना है, 'भारतीय भारतीय मजबूत हो रहे हैं, भले ही अर्थव्यवस्था कमजोर है।' हालांकि प्रमुख घटनाक्रम और ढांचागत सुधारों ने बीच बीच में बड़ी तेजी में योगदान दिया है। जहां इन घटनाक्रम का समाज के बड़े वर्ग पर विपरीत प्रभाव पड़ा, वहीं शेयर बाजार से भी आय सीमित रही। पिछले पांच वर्षों में से तीन में सेंसेक्स की आय में कमी दर्ज की गई और पिछले पांच साल में 1 प्रतिशत से ज्यादा की औसत आय वृद्धि दर्ज की गई।

एडलवाइस फाइनैंशियल सर्विसेज के उप-मुख्य कार्याधिकारी (पूंजी बाजार परामर्श) शिव सैगल ने कहा, 'जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर 2008-09 में शेयर बाजार से आय 5.6 प्रतिशत पर अपने चरम पर थी जो गिरकर 2.7 प्रतिशत के सर्वाधिक निचले स्तर पर आ गई। अमेरिका में यह 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 13 प्रतिशत हो गई।'

आय में इस गिरावट की वजह से भारतीय बाजार अपने वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से पिछड़ गए। नोटबंदी, जीएसटी और रियल एस्टेट में मंदी, नकदी संकट जैसे बड़े घटनाक्रम रोजगार सृजन और खपत में कमजोरी के लिए काफी हद तक जिम्मेदार रहे।

कमजोर गुणवत्ता, कम वृद्धि या कर्ज से जुड़ी कंपनियां बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए जिम्मेदार रहीं और इससे कुछ खास शेयरों का मूल्यांकन वर्ष के ऊंचे स्तरों पर पहुंच गया। निफ्टी-50 के 28 शेयर 20 गुना के पीई अनुपात से ऊपर कारोबार कर रहे हैं, जिनमें 14 शेयर 30-81 गुना के दायरे में हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख (इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज) गौतम दुग्गड का कहना है, 'निवेशक अब कॉरपोरेट प्रशासन, प्रबंधन, ऑडिटिंग और बैलेंस शीट की गुणवत्ता पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, बाजार कुछ शेयरों के पक्ष में केंद्रित हो गए हैं।'बाजार अब ज्यादा तरल हो गए हैं क्योंकि इनमें निवेश के लिए ज्यादा शेयर/क्षेत्र मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, वित्तीय क्षेत्र में, परिसंपत्ति प्रबंधक (एएमसी), जीवन और सामान्य बीमा कंपनियां, ब्रोकरेज और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं। खपत सूची वाले क्षेत्रों में अब डिस्क्रेशनरी, क्विक सर्विस कंपनियां, मल्टीप्लेक्स, रिटेलर आदि शामिल हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि निवेशक और बाजार अब सतर्क हो रहे हैं। मुकीम कहते हैं, 'निवेशक (भारतीय और विदेशी) अधिक सक्षम हो गए हैं। शोधों और विश्लेषणों की गहनता बढ़ी है।'

निवेशकों के समझदार होने का एक अन्य संकेत यह है कि एसआईपी (व्यवस्थित निवेश योजनाओं) का मासिक योगदान 5-6 साल पहले के लगभग 2,000 करोड़ रुपये से बढ़कर पिछले 18 महीनों में 8,000 करोड़ रुपये हो गया, भले ही जीडीपी वृद्धि घटकर 4.5 प्रतिशत रह गई।

उनका कहना है, 'पिछले 7-8 वर्षों में, संस्थागत पूंजी प्रवाह का रुझान घरेलू निवेशकों के पक्ष में रहा। वर्ष 2006 और सितंबर 2019 के बीच, कुल घरेलू संस्थागत पूंजी प्रवाह 55 अरब डॉलर का था। इसमें 45-46 अरब डॉलर वर्ष 2014 के बाद एसआईपी और एकमुश्त निवेश के जरिये आया। इसका मतलब है कि खुदरा निवेशक अपनी दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं और बाजार में उतार-चढ़ाव से ज्यादा डरे हुए नहीं हैं।' वह कहते हैं, 'शुरू में, निवेशक तेजी के उत्साह में निवेश करते थे और अनिश्चितता के समय बिक्री करते थे। अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। यह बेहद सकारात्मक बदलाव है।' वैकल्पिक निवेश फंडों, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों, इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्टों की बढ़ती लोकप्रियता, और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं की परिसंपत्तियों में तेजी से जोखिमों और नई योजनाओं के लिए निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी का पता चलता है।

विश्लेषकों को वित्त वर्ष 2021 में भी आय में कमी आने की आशंका है

ज्यादा सॉवरिन वेल्थ फंडों, पारिवारिक कार्यालयों, जीवन एवं सामान्य बीमा कंपनियों, और पेंशन फंडों के साथ बाजार अब ज्यादा सक्षम हो गए हैं। आय में कमी स्पष्ट दिख रही है। मुकीम कहते हैं, 'हम वित्त वर्ष 2021 में भी आय अनुमानों में कटौती देखेंगे, क्योंकि उम्मीदें गैर-वास्तविक हैं। बाजार वैश्विक कारकों की वजह से चढ़े हैं। लेकिन क्या आय में कमी बाजारों में गिरावट का संकेत है? मैं इसे लेकर आश्वस्त नहीं हूं।'

अन्य जोखिम तब पैदा हो सकता है जब बाजार 'ग्रोथ' से 'वैल्यू' थीम पर केंद्रित हों। यदि निवेशक सतर्कता के साथ दांव नहीं लगाते हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैश्विक व्यापारिक तनाव अन्य निर्णायक कारक हो सकता है। हालांकि अमेरिका-चीन व्यापारिक टकराव का पहला चरण समाप्त हो चुका है, जिससे लंबे 'वैश्वीकरण' थीम की वापसी का संकेत माना जा रहा है।

अल्पावधि में, भारतीय बाजार अस्थिर बने रह सकते हैं, क्योंकि देश की जीडीपी और कॉरपोरेट आय में धीमी गति से सुधार आने का अनुमान है। दीर्घावधि में, जहां कुछ मौजूदा कंपनियां/क्षेत्र अग्रणी बने रहेंगे, वहीं नए क्षेत्र और कंपनियां भी इस दौड़ में शामिल हो सकती हैं। विश्लेषकों को यह भी उम्मीद है कि वृद्धि काफी हद तक सभी बाजारों में दिखेगी। दुग्गड़ का कहना है, 'हमें अब तक जनसांख्यिकी का कोई लाभ नहीं मिला है। लेकिन जब हम 2.7 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था से 5 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा की अर्थव्यवस्था में तब्दील हुए हैं, तो बाजार में कुछ सेगमेंट (बचत का लाभ, अधिक खपत वाले क्षेत्रों का उभार आदि) पर इसका असर दिखेगा और शेयरधारकों को फायदा होगा।'

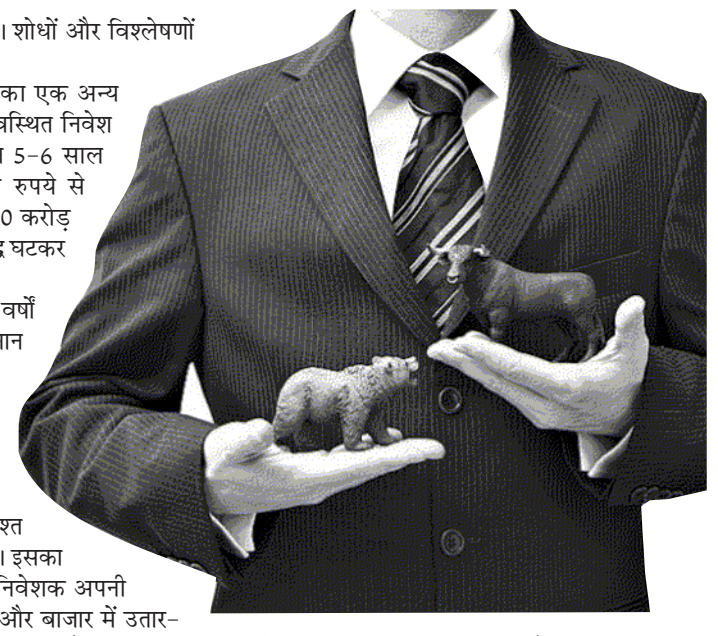

सेंसेक्स

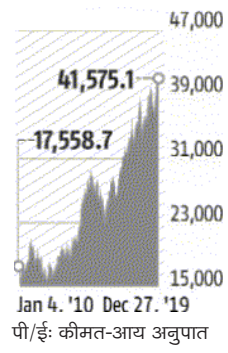

सेंसेक्स पी/ई

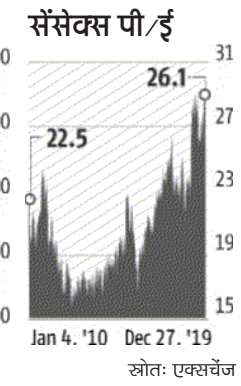

पी/ई: कीमत-आय अनुपात — स्रोत: एक्सचेंज

घरेलू प्रवाह में फिर आई तेजी

इक्विटी निवेश (करोड रुपये में)

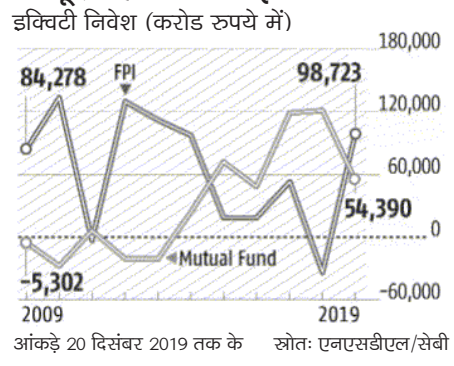

आंकड़े 20 दिसंबर 2019 तक के — स्रोत: एनएसडीएल/सेबी

सेंसेक्स की आय रही अस्थिर

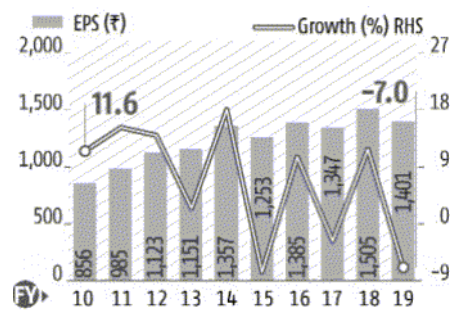

ईपीएस: प्रति शेयर आय — स्रोत: ब्लूमबर्ग

निवेशकों की पसंद बन रहे चीनी कंपनियों के शेयर

उज्ज्वल जौहरी

चीनी उत्पादन मौसम अनुकूल होने के साथ अगर चीनी उत्पादक कंपनियों के शेयरों में तेजी आ रही है तो इसमें किसी तरह के आश्चर्य की बात नहीं है। उदाहरण के लिए ईआईडी-पैरी, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, द्वारिकेश शुगर और धामपुर शुगर में तेजी आई है और अगस्त के अपने निचले स्तरों से ये 30-58 प्रतिशत तक उछल गए हैं। इनमें हाल में ही बलरामपुर चीनी अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और इस समय उन्हीं स्तरों पर कारोबार कर रही है।

चीनी भंडार में कमी और खरीद कीमतें स्थिर रहने से चीनी उत्पादक कंपनियां लाभ अर्जित करने की स्थिति में आ गई हैं। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 1 अक्टूबर 2019 से आरंभ चालू चीनी सत्र (2019-20) में चीनी उत्पादन में सालाना आधार पर 35 प्रतिशत कमी आई है। उत्तर प्रदेश को छोड़कर महाराष्ट्र (देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश) और कर्नाटक में उत्पादन में कमी दर्ज की गई है।

चालू सत्र में चीनी उत्पादन 2.65 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो 2019-19 के चीनी सत्र (1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019) के 3.31 करोड़ टन से कम रहेगा।

उत्पादन में कमी से चीनी का पुराना भंडार कम जरूर होगा, वहीं अनुकूल सरकारी नीतियां जैसे 60 लाख टन तक चीनी के निर्यात की अनुमति आदि सकारात्मक हैं। चीनी के रस से बनने वाले एथनॉल और 'बी' एवं 'सी' प्रकार शीरे की ऊंची कीमतें भी कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की तरफ से एथनॉल की खरीदारी से संबंधित नई निविदाओं की तादाद बढ़ रही है।

इलारा कैपिटल के विश्लेषकों का कहना है कि चीनी मिलों और स्वतंत्र डिस्टिलरियों ने 163 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति की पेशकश की है और इनमें गन्ना रस से बनने वाले एथनॉल और 'बी' श्रेणी के 73 करोड़ लीटर भारी शीरे की मात्रा पिछले वर्ष की मात्रा से दोगुनी है। इस लिहाज से विश्लेषकों का मानना है कि चालू सत्र में पिछले सत्र के मुकाबले एथनॉल उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में गन्ने का इस्तेमाल होगा।

इंटरनैशनल शुगर एसोसिएशन से भी चीनी कंपनियों को अच्छी खबरें मिल रही हैं। एसोसिएशन ने वैश्विक स्तर पर चीनी की कमी से जुड़ा अनुमान संशोधित कर दिया है। इसके अनुसार दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक देशों थाईलैंड, भारत, यूरोप, ब्राजील आदि में चीनी उत्पादन के अनुमानों में कमी से यह परिस्थिति उत्पन्न हुई हैं। इससे घरेलू स्तर पर चीनी कंपनियों की प्राप्तियां बढ़ेंगी और इससे भारतीय उत्पादकों को निर्यात के मोर्चे पर भी मदद मिलेगी।

अनुकूल चालू चीनी सत्र में बलरामपुर चीनी जैसी मजबूत बहीखाते वाली कंपनियां विश्लेषकों की पहली पसंद हैं। हालांकि दूसरी कंपनियों को भी लाभ मिलता दिख रहा है। चीनी उत्पादक कंपनियों के शेयरों के लिए परिस्थितियां फिलहाल अनुकूल दिख रही हैं। गन्ना उत्पादन बेहतर रहने से उत्तर प्रदेश से जुड़ीं कंपनियों को अधिक लाभ मिल सकता है। इनकी तुलना में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु पर केंद्रित कंपनियों का चीनी उत्पादन अपे क्षाकृत कम हो रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें इस साल ओएमसी को अधिक मात्रा में एथनॉल की आपूर्ति करेंगी।

बलरामपुर चीनी की 160,000 लीटर प्रति दिन क्षमता वाला संयंत्र अपनी क्षमता 2018-19 में 11 करोड़ लीटर क्षमता को 2020-21 को बढ़ाकर 17 करोड़ लीटर करेगी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि वित्त वर्ष 2019-21 के दौरान कंपनी की एथनॉल की बिक्री में 30.6 प्रतिशत वृद्धि होगी। एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने का लाभ धामपुर शुगर को भी मिल सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि 'बी' भारी शीरे का इस्तेमाल कर एथेनॉल का उत्पादन करने वाली यह पहली कंपनी है। द्वारिकेश शुगर ने भी हाल में ही 10,000 एलपीडी क्षमता वाले नए संयंत्र की शुरुआत की है। कंपनी की रोजाना 21,500 टन चीनी उत्पादन क्षमता है और वित्त वर्ष 2019 में इसकी शुगर रिकवरी दर सर्वाधिक रही थी।

वित्त वर्ष 2021 से उम्मीदें

करोड़ रुपये में	बलरामपुर चीनी	द्वारिकेश	धामपुर शुगर
राजस्व	4,792	1,236	2,971
सालाना बदलाव %	6.6	4.5	0.9
एबिटा	803	283	584
सालाना बदलाव %	8.3	54.3	15.7
शुद्ध लाभ	531	211	362
सालाना बदलाव %	9.6	77.4	27.1

टेबल में ब्रोकरों की निगरानी वाली प्रमुख कंपनियां शामिल हैं

स्रोत: विश्लेषकों की रिपोर्ट

चीन की बढ़ती मांग से इस्पात कंपनियों को मिलेगी मदद

उज्ज्वल जौहरी

पिछले कुछ समय से टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और जिंदल स्टील ऐंड पावर (जेएसपीएल) जैसी घरेलू इस्पात कंपनियों के शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर चढ़ रहे हैं क्योंकि फंडामेंटल में सुधार के चलते ब्रोकरेज कंपनियों ने इन शेयरों को अपग्रेड किया है। ये शेयर अपने अक्टूबर के निचले स्तरों की तुलना में करीब 24 से 63 फीसदी चढ़ चुके हैं और यह तेजी आगे भी जारी रह सकती है।

चीन में इस्पात की बढ़ती मांग के चलते बाजार का इन शेयरों में भरोसा बढ़ रहा है। चीन में मांग बढ़ने से इस्पात की वैश्विक कीमतों को ऐसे समय सहारा मिल रहा है, जब अमेरिका और चीन के बीच शुल्क को लेकर बातचीत सफल होती नजर आ रही है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन में वर्ष 2019 में मांग पहले के अनुमानों से अधिक रही है। हालांकि दुनिया के शेष बाजारों में मांग कमजोर बनी हुई है। हालांकि चीन में इस्पात का स्टॉक कम है और उसके ज्यादातर उत्पादन की खपत देश के भीतर ही होगी। इसलिए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सर्दियों में उत्पादन में कटौती का मतलब है कि चीन का निर्यात कम रहेगा।

यह भारतीय इस्पात उत्पादकों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि इससे घरेलू कीमतों को सुधरने में मदद मिल रही है। भारत में हॉट रोल्ड कॉइल की कीमतें अक्टूबर में 34 महीने के निचले स्तर करीब 34,250 रुपये प्रति टन पर आ गई थीं, जो 2017-18 और 2018-19 में अधिसूचित डंपिंग रोधी शुल्क के स्तरों से नीचें थीं। हालांकि यह गिरावट एक सीमित अवधि के लिए थी। हालांकि स्टॉक को खाली करने का दौर खत्म होने लगा तो घरेलू कीमतें नवंबर और दिसंबर में बढ़ गईं। वैश्विक कीमतों में तेजी से भी घरेलू कीमतों को सहारा मिल रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि इन दोनों कारकों की वजह से घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी के लिए काफी गुंजाइश है क्योंकि इससे दक्षिण कोरिया, जापान और चीन जैसे अहम देशों से आयात करना आकर्षक नहीं रह जाता है।

चीन की बढ़ती मांग, सर्दियों में आपूर्ति में संभावित कमी और वैश्विक कीमतों के डंपिंग रोधी शुल्क के स्तरों से ऊपर पहुंचना घरेलू कंपनियों के लिए सकारात्मक

इस्पात की कीमतों में सुधार का मतलब है कि लाभ मार्जिन में भी सुधार आएगा। लाभ मार्जिन 2019-20 की जुलाई-सितंबर अवधि में निचले स्तरों पर पहुंच गया था। हालांकि मांग में सुधार पर बाजार की नजर रहेगी क्योंकि इसका बिक्री मात्रा और मार्जिन पर सीधा असर पड़ेगा।

देश में इस्पात की मांग चालू वित्त वर्ष में अब तक सपाट या मामूली कम रहने के आसार हैं। हालांकि विश्लेषकों का रुख मांग में सुधार को लेकर सकारात्मक है। सिटी रिसर्च के विश्लेषकों का कहना है कि भारत की मांग निचले स्तरों से बढ़ेगी। इस तरह वे इस्पात कीमतों में आगे बढ़ोतरी के आसार देख रहे हैं। सिटी का अनुमान है कि चीन से कम निर्यात और बाकी दुनिया में मांग बढ़ने से वैश्विक कीमतों में तेजी आएगी, इसलिए उसने टाटा स्टील को अपग्रेड कर टॉप पिक बनाया है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू को बिक्री की जगह खरीद श्रेणी में डाला गया है। सिटी का सेल को लेकर रुख 'तटस्थ' है। ज्यादातर विश्लेषकों की इस्पात क्षेत्र में पहली पसंद टाटा स्टील है क्योंकि कंपनी घरेलू बाजार पर नए सिरे से ध्यान दिया है और परिचालन में तालमेल कायम किया है।

इस्पात मांग बढ़ने से मजबूत होंगी घरेलू कंपनियां

जेएसडब्ल्यू स्टील की आमदनी में नरमी के कारण उसके मुनाफे पर दबाव रहा है। लेकिन अब कीमतों और मांग में सुधार से कंपनी को न केवल लाभ होने होने का अनुमान है बल्कि कच्चे माल की नरम कीमतें विशेष रूप से कोकिंग कोल की कीमतें सकारात्मक साबित होंगी।

जेएसडब्ल्यू अपनी कोयले और लौह अयस्क की जरूरत के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर है। एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग के विश्लेषकों के मुताबिक कंपनी के लिए मिश्रित कोकिंग कोयले की लागत वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में 10 डॉलर प्रति टन कम हुई है और इसमें अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 25 से 30 डॉलर प्रति टन की और कमी आने के आसार हैं। जेएसडब्ल्यू को अपनी सालाना 50 लाख टन क्षमता की डोल्वी विस्तार परियोजना से उत्पादन मात्रा बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे भी कंपनी के लाभ में इजाफा होगा।

सेल को भी अपने उत्पादों की अधिक कीमत मिलने का फायदा मिलेगा। लेकिन कंपनी के मार्जिन में सुधार के लिए लागत को नियंत्रित करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसके स्टॉक को लेकर विश्लेषकों का रुझान सुधर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि जेएसपीएल को क्षमता विस्तार और परिचालन कुशलता का फायदा मिलेगा।

एसएमई का संकट मझोले बैंकों पर पड़ सकता है भारी

हंसिनी कार्तिक

मझोले आकार के निजी बैंकों आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक (सीयूबी), डीसीबी बैंक और करूर वैश्य बैंक (केवीबी) में कम से दो बातें समान दिख रही हैं। पहली बात तो यह कि वे खास ग्राहकों के साथ कारोबार को अधिकत वज्जो दे रहे हैं और दूसरा अहम पहलू यह है कि लघु एवं मझोले उद्यमों (एसएमई) को ऋण मुहैया कराना उनके कारोबार की खूबी रही है। एसएमई एक ऐसा खंड है जो अर्थव्यवस्था की चाल पर खासा निर्भर रहता है। जब अर्थव्यवस्था की गति सुस्त रहती है तो एसएमई पर सबसे पहले असर पड़ता है और इसे पटरी पर आने में भी सबसे अधिक समय लगता है। इसका संकेत भी मिलने लगा है क्योंकि एसएमई को आवंटित बैंक ऋणों के भुगतान में देरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही में सालाना आधार पर सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में 30-120 आधार अंक की तेजी आई है। बैंकों के ऋण खातों में एसएमई ऋण की हिस्सेदारी 10 से 30 प्रतिशत होती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आरबीएल, केवीबी, डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक के शेयरों में इस साल अब तक इतनी गिरावट क्यों आई है। इनके शेयरों का प्रदर्शन सीएनएक्स निफ्टी और निफ्टी प्राइवेट बैंक सूचकांकों के मुकाबले कमजोर रहा है।

हाल में प्रकाशित मूडीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एसएमई खंड में परेशानी जारी है और इसके मद्देनजर निवेशकों को अधिक मुश्किलों के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि बैंकों का कहना है कि यह असर पिछली बार की तरह नुकसानदायक साबित नहीं होगा। इस बारे में एक बैंकर ने कहा, 'हम कुछ तिमाही पहले ही एमएसई ऋण को लेकर सतर्क हो गए थे, इसलिए हमें नहीं लगता कि ऐसे ऋणों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है।' मझोले आकार के बैंक एसएमई कारोबार में किसी तरह की मंदी की भरपाई के लिए अपने कारोबार में तेजी ला रहे हैं। मिसाल के तौर पर फेडरल बैंक का खुदरा पोर्टफोलियो सितंबर तिमाही में 25 प्रतिशत बढ़ा है, जिसमें आवास एवं स्वर्ण ऋणों (गोल्ड लोन) की अधिक भूमिका रही है। बैंक अपना असुरक्षित एवं वाणिज्यिक वाहन ऋण कारोबार भी बढ़ा रहा है। जेफरीज के विश्लेषकों ने वित्त वर्ष 2020 के अपने अनुमानों में 2.0 से 2.5 प्रतिशत कमी की है, लेकिन वे फेडरल बैंक के ऋण वृद्धि एवं शुद्ध ब्याज मार्जिन की वृद्धि को लेकर आशावान है। जेफरीज ने इनमें क्रमश: 20 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत तेजी आने का अनुमान व्यक्त जताया है।

आरबीएल बैंक ने फंसे ऋण का आंकड़ा 1,800 करोड़ रुपये रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि यह क्रेडिट कार्ड और सूक्ष्म वित्त ऋणों से कारोबार वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। बैंक को उच्च-वृद्धि-उच्च मार्जिन देने वाला बैंक माना जाता है, इसलिए इसके शेयर को लेकर एमके ग्लोबल का रुख सकारात्मक है। इस ब्रोकरेज कंपनी ने वित्त वर्ष 2020 और 2021 के लिए आय का अनुमान 13 प्रतिशत कम कर दिया है, लेकिन उन्हें लगता है कि बैंक का रिटर्न प्रोफाइल वित्त वर्ष 2021 की जून तिमाही तक सामान्य हो जाएगा।

अजय मोहंती

बैंकों के ऋण खातों में एसएमई ऋण की हिस्सेदारी 10 से 30 प्रतिशत होती है

एक दूसरे बैंक सीयूबी की हालत थोड़ी अलग है। एसएसमई ऋणों में इसका हिस्सा 33 प्रतिशत है और वृद्धि कमजोर पड़ रही है। दूसरी तिमाही की ऋण वृद्धि दर सालाना आधार पर 12 प्रतिशत रही, जो पहली तिमाही में 14 प्रतिशत दर्ज हुई थी। एमके ग्लोबल के विश्लेषकों ने वित्त वर्ष 2020 के लिए आय अनुमान 1.2 प्रतिशत कम कर दिया है, लेकिन सीयूबी अपने पास उपलब्ध पूंजी और आय अर्जित करने के मजबूत रिकॉर्ड की बदौलत नुकसान सहने के लिहाज से मजबूत स्थिति में है। जहां तक निवेशकों की बात है तो शेयर द्वारा दर्ज लाभ के मद्देनजर वे कुछ मुनाफावसूली कर सकते हैं। जो लोग शेयर में निवेश करना चाहते हैं वे थोड़ा इंतजार कर सकते हैं।

फेडरल बैंक, सीयूबी और आरबीएल बैंक संभावित एसएसमई संकट से निपटने की बेहतर स्थिति में नजर आते हैं, वहीं केवीबी और डीसीबी बैंक के लिए मुश्किलें, खासकर वृद्धि के मोर्चे पर अधिक हो सकती हैं। पिछले दस वर्षों के दौरान डीसीबी बैंक अपने बहीखाते में सालाना 22 प्रतिशत सालाना दर से इजाफा कर रहा है, लेकिन अगले दो से तीन वर्षों में यह कम होकर 17-18 प्रतिशत रह सकता है। जेएम फाइनैंशियल ने वित्त वर्ष 2020 में बैंक के लिए अनुमान 8 प्रतिशत तक कम कर दिया है। हालांकि विश्लेषकों को परिसंपत्ति गुणवत्ता में और गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन सुस्ती अधिक समय तक रहने से स्थितियां बदल सकती हैं।

केवीबी की परिसंपत्ति गुणवत्ता और वृद्धि दर पर नुकसान का खतरा सबसे अधिक मंडरा रहा है। 8 प्रतिशत सकल एनपीए के साथ इसकी परिसंपत्ति गुणवत्ता सबसे कमजोर है। बैंक खुदरा खंड पर अधिक जोर दे रहा है और हिसाब से ऋण खाते में बदलाव कर रहा है। यही वजह है कि दूसरी तिमाही में खुदरा ऋण खंड 33 प्रतिशत बढ़ने के बाद भी समग्र ऋण खाते में केवल 1 प्रतिशत तेजी आई। वित्त वर्ष 2020 के शेष हिस्से में भी यही हालात रह सकते हैं, इसलिए इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार वित्त वर्ष 2022 में जाकर दिख सकता है। निवेशकों के लिए इससे फिलहाल दूर रहना ही बेहतर है।

दुनिया

लोकतंत्र की नई परिभाषा

13 दिसंबर

ब्रेक्जिट से निकासी का समझौता संसद में कई बार पारित नहीं हो पाया और यूरोपीय संघ (ईयू) ने बाहर निकलने की अंतिम तिथि को दो बार बढ़ाया। इसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में टेरेसा मे की जगह लेने वाले बोरिस जॉनसन ने आम चुनाव कराए। ये चुनाव कंजरवेटिव पार्टी ने 80 सीट के भारी बहुमत से जीते हैं। इससे ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से 31 जनवरी 2020 को निकलना सुनिश्चित हो गया है, लेकिन ईयू के साथ नए समझौते की अंतिम तिथि अब भी चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है।

18 दिसंबर

डॉनल्ड ट्रंप पर महाभियोग प्रतिनिधि सभा में पारित हो गया है। इस तरह वह महाभियोग का सामना करने वाले तीसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। यह प्रक्रिया एक व्हिसल ब्लोअर की शिकायत पर शुरू हुई, जिसने आरोप लगाया कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को धमकी दी कि अगर उन्होंने 2020 में डेमोकेट्रिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन के खिलाफ जांच शुरू नहीं की तो वह उनकी मदद रोक देंगे। ट्रंप को पद से हटाना रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाले सीनेट में मुख्य न्यायाधीश की अगुआई में मत परीक्षण पर निर्भर करेगा। सीनेट में ट्रंप के पक्ष में मतदान होने की संभावना है। मत परीक्षण को लेकर गतिरोध बना हुआ है क्योंकि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच महाभियोग के प्रारूप पर असहमति है।

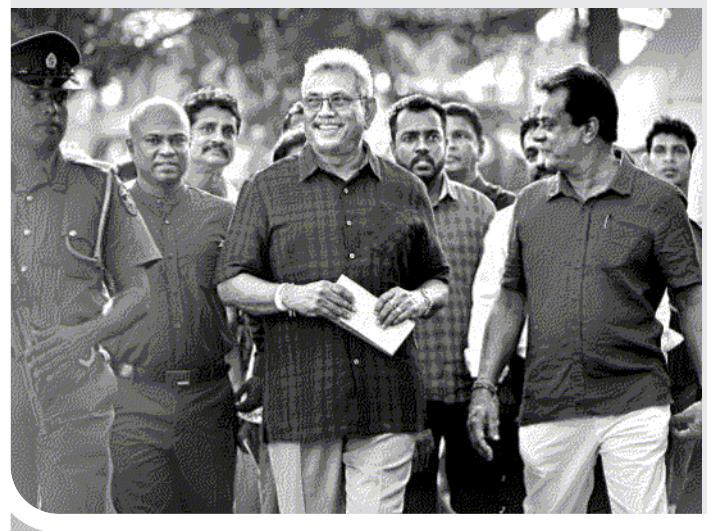

16 नवंबर

श्रीलंका में पूर्व रक्षा मंत्री गोटाभाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है। इससे इस देश के तमिल और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए नई चुनौती पैदा हो गई है। गोटाभाया श्रीलंका के ताकतवर राजनीतिक परिवार के सदस्य हैं। उनकी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) को हराने की रणनीति बनाने में अहम भूमिका रही है। उनका पहला कदम अपने भाइयों को अंतरिम कैबिनेट में शामिल करना रहा है।

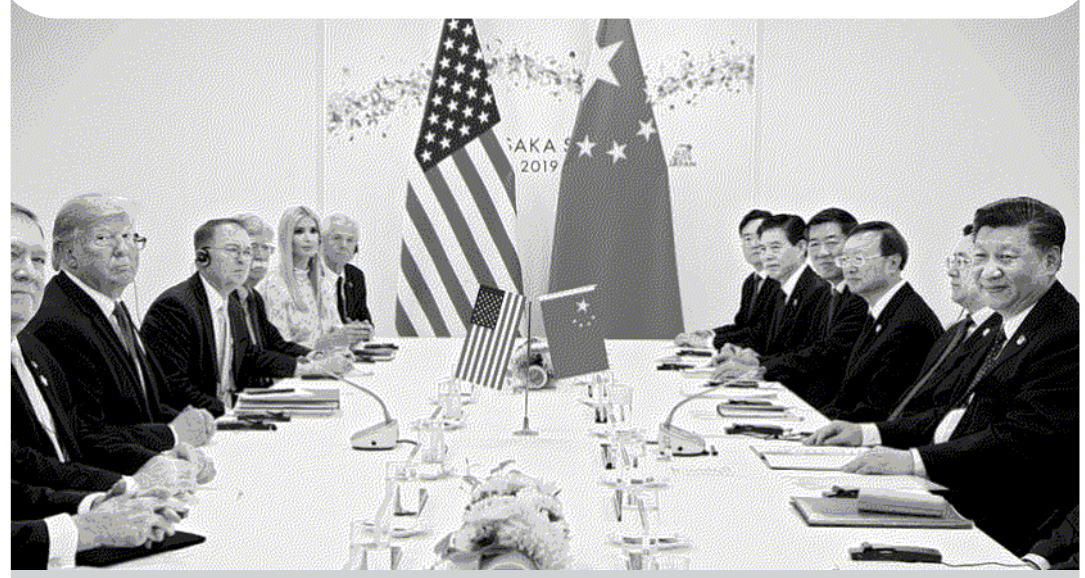

31 अक्टूबर

अमेरिका और चीन ने पिछले डेढ़ साल के दौरान एक-दूसरे के आयात पर शुल्क बढ़ाए हैं। इससे विश्व की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे पड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कंपनियां प्रभावित हुई हैं। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने एक प्रारूप समझौते की घोषणा की है। इसमें चीन ने अमेरिका के ज्यादा कृषि उत्पादों की खरीद का वादा किया है। वहीं अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले उत्पादों पर शुल्क घटाने का वादा किया है। दोनों पक्ष शर्तों की पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पक्ष ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वर्ष 2020 अहम साबित हो सकता है।

5 दिसंबर

शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की घोषणा के दो साल बाद और हवाई हमले में अपने अहम संयंत्रों को नुकसान पहुंचने के तीन महीने बाद विश्व की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी सऊदी अरामको 25.6 अरब डॉलर जुटाने के लिए आरंभिक सार्जनिक निर्गम (आईपीओ) लेकर आई। यह इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ है। यह शेयर 11 दिसंबर को सऊदी सिक्योरिटीज एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हुआ।

1 जनवरी

कट्टर दक्षिणपंथी और पूर्व सैन्य अधिकारी जायर बोलसोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। समलैंगिक और महिलाओं के अलावा उनके विवादास्पद राजनीतिक विचारों में से एक एजेंडा अमेजन के जंगलों और आदिवासी भूमि को कृषि कारोबार में तब्दील करना है। अमेजन के जंगल विश्व के सबसे बड़े वर्षावन हैं और बड़े स्तर पर कार्बन को अवशोषित करते हैं।

23 सितंबर

किशोरी महिला कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की अनदेखी करने के लिए वैश्विक नेताओं की कड़ी आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति और जलवायु परिवर्तन समझौते से असहमत डॉनल्ड ट्रंप ने थनबर्ग को ट्रोल किया।

4 दिसंबर

दो दशक पहले गूगल की स्थापना करने वाले स्टैनफर्ड के स्नातक छात्रों लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन ने घोषणा की कि वे गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट में कार्याधिकारी की भूमिकाओं से इस्तीफा देंगे। भारत में जन्मे गूगल के मुख्य कार्याधिकारी सुंदर पिचाई (दाएं) गूगल और अल्फाबेट दोनों के प्रमुख बनेंगे।

13 अक्टूबर

एक विवादास्पद फैसले में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने उत्तरी सीरिया से अमेरिकी फौजों को वापस बुलाने का आदेश दिया। इस फैसले से क्षेत्र में सीरिया सरकार और रूस का नियंत्रण खत्म हो जाएगा और इस्लामिक स्टेट का फिर से उभार हो सकता है।

23 अक्टूबर

लगातार चार महीनों के विरोध-प्रदर्शन के बाद हॉन्ग-कॉन्ग प्रशासन ने विवादास्पद प्रत्यर्पण विधेयक वापस ले लिया, लेकिन ज्यादा लोकतंत्र की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इन विरोध-प्रदर्शनों के कारण चीन को सैन्य दखल भी देना पड़ा। वहीं नवंबर में स्थानीय चुनावों में लोकतंत्र समर्थक पार्टी की प्रचंड जीत से चीनी प्रशासन के लिए सिरदर्दी पैदा हो गई है।

ग्राहकों के लिए सुनहरा और दूरसंचार क्षेत्र के लिए बुरा दौर

पिछले दशक में ग्राहकों दूरसंचार सेवाओं की बहुत कम कीमतों का फायदा मिला है, जबकि बहुत सी दूरसंचार कंपनियां खस्ताहाली की वजह से मैदान छोड़ गईं

सुरजीत दास गुप्ता

ग्राहकों के लिए यह सुनहरा दौर रहा है। इस दशक की शुरुआत में सक्रिय ग्राहक वॉयस कॉल के लिए औसतन 50 पैसे प्रति मिनट का भुगतान करते थे और उनका मासिक बिल औसतन 140 रुपये प्रति महीना था। दशक के अंत में वॉयस कॉल लगभग मुफ्त हैं और उनके मासिक बिल 20 फीसदी घटकर 113 रुपये पर आ गए हैं। उन्हें फिल्म, खेल और टीवी चैनल देखने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा मिल रहा है।

दशक दूरसंचार का प्रदर्शन

दूरसंचार कंपनियों के लिए यह दौर बड़ी कंपनियों के छोटी कंपनियों का सफाया करने जैसा रहा है। सरकार के नए लाइसेंस जारी करने की वजह से 2010 में बड़ी विदेशी कंपनियों समेत करीब आधा दर्जन कंपनियां दूरसंचार बाजार में उतरी थीं। उन्होंने कीमतों को लेकर प्रतिस्पर्धा छेड़ी क्योंकि उन्हें बाजार में हिस्सेदारी हासिल करनी थी। उस समय यह माना जाता था कि भारतीय बाजार में मोबाइल सेवाओं के लिए वृद्धि की भरपूर संभावनाएं हैं।

कंपनियों को बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण दशक की समाप्ति तक विलय और कारोबार बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। एक समय इस क्षेत्र में 15 कंपनियां थीं, जिनकी संख्या घटकर अब चार पर आ गई है। अब इस बात के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं कि वोडाफोन-आइडिया के प्रवर्तक अपने कारोबार में और पैसा नहीं झोंकना चाहते हैं। ऐसे में कंपनियों की संख्या चार से घटकर तीन पर आ सकती है। हालांकि अब भारत में दूरसंचार ग्राहकों की तादाद 110 करोड़ हो गई है।

> एक समय इस क्षेत्र में 15 कंपनियां थीं, जिनकी संख्या घटकर अब चार पर आ गई है

वॉयस सेवाओं पर आधारित बाजार महज एक दशक में डेटा पर आधारित हो गया है। यह सब

इस बाजार में रिलायंस जियो के प्रवेश के कारण हुआ है। कंपनी ने दूरसंचार क्षेत्र में नई इबारत लिखी है। कंपनी ने 2016 में ग्राहकों को 4जी नेटवर्क पर मामूली दरों पर डेटा मुहैया कराना शुरू किया। इसके नतीजतन देश में इंटरनेट का उपयोग 100 गुना बढ़ा है।

कंपनी ने जो बुनियादी बदलाव शुरू किया है, वह कन्वर्जेन्स को बढ़ावा देना है। उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल डिवाइस टीवी की जगह वीडियो, फिल्म, खेल और मनोरंजन का वैकल्पिक प्लेटफॉर्म बन गए हैं। अचानक बहुत से घरों में मोबाइल दूसरा व्यक्तिगत टेलीविजन बन गया है। अब 10 करोड़ से अधिक सक्रिय ग्राहक मनोरंजन और समाचारों के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

ये सभी बदलाव ग्राहकों के लिए अच्छे रहे। लेकिन वोडाफोन, टेलीनॉर, मैक्सिस, सिस्तेमा और एतिसलात जैसी विदेशी कंपनियों ने भारत में निवेश किया था, लेकिन उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। वे नियामकीय बदलावों, गला-काट प्रतिस्पर्धा, कर अधिकारियों या अदालतों में अपना पक्ष नहीं रख पाए। टेलीनॉर और एमटीएस (जिसने दूसरी बार वापसी की कोशिश की) जैसी कंपनियों को भारी घाटा उठाना पड़ा। उनमें से ज्यादातर ने अपना कारोबार औने-पौने दामों पर बेच दिया। इसके नतीजतन विदेशी दूरसंचार कंपनियों को 25 अरब डॉलर से अधिक का घाटा उठाना पड़ा। वोडाफोन ने कहा है कि उसे अपना कारोबार बंद करना पड़ सकता है।

इस प्रतिस्पर्धा में खुद को बचाने में सफल रहने वाली कंपनियों का कर्ज बढ़कर बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। उन्हें महंगी कीमत पर स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ा, जिसकी आधार कीमत कृत्रिम रूप से ऊंची रखी गई थी ताकि सरकार मोटी कमाई कर सके।

यही वजह है कि उद्योग का कर्ज पिछले एक दशक में सात गुना बढ़कर सात लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जो वर्ष 2010 में महज 1.2 लाख करोड़ रुपये था। इस वजह से रिलायंस कम्यूनिकेशंस और एयरसेल को ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) से गुजरना पड़ा क्योंकि वे अपने ऋणों को चुकाने की स्थिति में नहीं थीं।

इस समस्या की गंभीरता का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि एबिटा के प्रतिशत के रूप में उद्योग का ब्याज का बोझ दोगुना हो गया है। यह वित्त वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में 41 फीसदी था, जो 2019 की चौथी तिमाही में 80 फीसदी हो गया।

हालांकि यह सही है कि ग्राहकों की तरह सरकार को भी फायदा मिला है। हालांकि उद्योग का सरकारी खजाने में योगदान 2019 की चौथी तिमाही में घटकर 31 अरब रुपये पर आ गया, जो 2017 की पहली तिमाही में 51 अरब रुपये था। इसकी वजह यह है कि कंपनियों

का राजस्व घटा है, उन पर ब्याज का बोझ बढ़ा और लाभ में गिरावट आई है। संचार मंत्री ए राजा के दो फैसलो से उठापटक वाले दशक की शुरुआत हुई। वर्ष 2009 के अंत में पहली बड़ी नीलामी में महज 5 मेगाहर्ट्ज 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई। इस तरह ए राजा ने कड़ी प्रतिस्पर्धा की नींव रख दी थी। दूरसंचार कंपनियों ने 67,000 करोड़ रुपये खर्च किए। इसके बावजूद एयरटेल जैसी कंपनियों को देश भर में स्पेक्ट्रम नहीं मिल पाए। इस फैसले ने तीन काम किए। इससे दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए ज्यादा कर्ज लेना, जिससे कर्ज का चक्र शुरू हुआ और यह कभी खत्म ही नहीं हुआ। इससे 3जी सेवाओं की दरें ऊंची बनी रहीं, जिससे डेटा का उपयोग आकर्षक नहीं रह गया। इससे मोबाइल सेवाओं की शुरुआत धीमी पड़ गई। राजा के दूसरे फैसले का विनाशकारी असर पड़ा। उन्होंने नए ऑपरेटरों को लाइसेंस देने के लिए नियम बदल दिए। उन्होंने पहले आओ, पहले पाओ का नियम लागू किया। माना जाता है उन्होंने यह कदम कथित रूप से अपने दोस्तों की मदद के लिए उठाया। इस क्षेत्र में चार-पांच नई कंपनियों के आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ी। जब 15 कंपनियां दरें घटाकर बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश कर रही थीं, उस समय जून 2010 में दूरसंचार कंपनियों

दूरसंचार उद्योग का कर्ज पिछले एक दशक में 7 गुना बढ़कर सात लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जो वर्ष 2010 में महज 1.2 लाख करोड़ रुपये था

का औसत एआरपीयू गिरकर 100 रुपये से नीचे आ गया। लेकिन सबसे बुरा दौर उस समय आया, जब सीएजी की रिपोर्ट का संज्ञान लेकर उच्चतम न्यायालय ने 122 लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया। इन लाइसेंस में टेलीनॉर, सिस्तेमा और एतिसलात के लाइसेंस भी शामिल थे। राजा को जेल जाना पड़ा। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लाइसेंस और स्पेक्ट्रम मुफ्त में देने से सरकारी खजाने को 1,76,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

जो कंपनियां वजूद बचा पाईं, उन्हें इस बात से राहत मिली कि लाइसेंस रद्द होने के बाद दूरसंचार कंपनियों की संख्या में कमी आई है। वे अब ग्राहक गंवाए बिना शुल्क बढ़ा सकेंगी और अपनी आमदनी सुधार सकेंगी। लेकिन अब यह साफ हो गया था कि सभी स्पेक्ट्रम का आवंटन सरकार करेगी। यूएएसएल लाइसेंस शुरू करने से स्पेक्ट्रम को सेवाओं से हटाया जाएगा ताकि दूरसंचार कंपनियां किसी भी सेवा के लिए कोई भी स्पेक्ट्रम-2जी, 3जी या 4जी इस्तेमाल कर सकेंगी।

इसके बाद 2015 में 900 मेगाहर्ट्ज बैंड की नीलामी में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जिसमें कीमतें तीन से पांच गुना बढ़ गईं। मौजूदा कंपनियों के लिए इस बैंड का लाइसेंस खत्म हो रहा था, लेकिन यह 4जी के लिए लोकप्रिय बैंड था। सभी दूरसंचार कंपनियों ने महज दो वर्षों 2015-2016 में स्पेक्ट्रम पर 1,75,000 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि उन्होंने दूरसंचार सेवाएं शुरू करने से लेकर अब तक 1,50,000 करोड़ रुपये ही खर्च किए थे। इस वजह से उन पर कर्ज बढ़ा।

दूसरी चुनौती जियो की शुरुआत से पैदा हुई। इसने वॉयस मुफ्त और डेटा 95 फीसदी सस्ती दरों पर मुहैया कराया। महज एक साल में डेटा का इस्तेमाल आठ गुना बढ़ गया। नियामक ने भी जियो को छह महीनों तक मुफ्त सेवाएं मुहैया कराने की मंजूरी दे दी, जिसका पहले से मौजूद ऑपरेटरों पर बुरा असर पड़ा। मौजूदा कंपनियों के पास शुल्क दरें घटाकर जियो के बराबर स्तर पर लाने और 4जी सेवाओं के लिए निवेश बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। भारती एयरटेल नुकसान उठाकर भी अपनी राजस्व हिस्सेदारी बनाए रखने में कामयाब रही। वोडाफोन आइडिया ने विलय किया और उसे ग्राहक और राजस्व हिस्सेदारी के मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनी कर्ज में भी डूबती जा रही है।

रही-सही कसर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने पूरी कर दी। अदालत ने दूरसंचार कंपनियों को एजीआर बकाये के रूप में 1,44,000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि चुकाने का निर्देश दिया है। वोडाफोन आइडिया ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने भुगतान में कोई राहत नहीं मुहैया कराई तो वह परिचालन बंद कर देगी। भारती एयरटेल बेहतर स्थिति में है। वह यह बकाया चुकाने के लिए डेट और इक्विटी के रूप में तीन अरब डॉलर जुटा रही है। दोनों कंपनियां अदालतों में अपनी पुनर्विचार याचिका सुने जाने का इंतजार कर रही हैं। हालांकि दूरसंचार कंपनियों ने शुल्क 15 से 40 फीसदी तक बढ़ाए हैं। लेकिन यह उच्चतम न्यायालय की चोट को भरने में पर्याप्त नहीं है। इस बाजार का भविष्य दो चीजों पर निर्भर करता है। अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो जाती है तो रिलायंस जियो और भारती एटरटेल उसके 30 करोड़ से अधिक ग्राहक हासिल कर सकती हैं। यह इस चीज पर निर्भर करता है कि उच्चतम न्यायालय पुनर्विचार याचिका पर अनुकूल फैसला देता है या नहीं और सरकार एजीआर बकाये को कई किस्तों में चुकाने की सुविधा देती है या नहीं।

देश में सत्ता के बदले समीकरण

आदिति फडणीस

राजनीतिक बहसों और मनोरंजन दोनों पर आधारित फिल्मों के ग्रीक-फ्रेंच निदेशक कोस्टा-गवरस को पिछले 10 साल की भारतीय राजनीति पर फिल्म बनाने के लिए कहा जाए तो यह उसके लिए सुखद अनुभव होगा। उनकी सबसे अधिक चर्चित फिल्म 'जेड' है। यह फिल्म राजनीतिक हत्या के बारे में है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार और उदार लोकतंत्र की सीमाओं का संदेश भी छिपा है। उनकी नई फिल्म ईडन इज वेस्ट यूरोप में ऐसे एक अवैध प्रवासी के बारे में है, जिसका सपना पेरिस पहुंचना है। इसमें प्रवासियों से भरी एक नाव के बहुत से लोग अपने पहचान के दस्तावेज नाव के बाहर फेंक देते हैं ताकि वे अपने अतीत को पीछे छोड़कर बिना कागजात वाले लोगों की जमात में शामिल हो सकें।

मोदी सरकार ने जब ऐसे फैसले लिए जो सही और सुविचारित नहीं थे, तब भी जनता नरेंद्र मोदी के पक्ष में मजबूती से खड़ी रही

वर्ष 2010 से 2020 तक भारत इन सभी स्थितियों से गुजरा है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के दूसरे कार्यकाल (2009-2014) की शुरुआत शानदार रही, लेकिन समाप्ति बदनामी के साथ हुई। इस अवधि की शुरुआत सामाजिक सुरक्षा की दूरदर्शी पहलों जैसे सभी के लिए शिक्षा और रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि के साथ हुई। लेकिन इसकी समाप्ति राष्ट्रमंडल खेलों में बड़े घोटाले के उजागर होने के साथ हुई। इसमें सामने आया कि सरकार घोटाले के बारे में जानती थी, लेकिन इसे रोकने में असहाय थी। सरकार पर 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में घूस के भी आरोप लगे। वहीं सांठगांठ का स्तर चौंकाने वाला था। इसका पता सीबीआई की उस रिकॉर्डिंग से चलता है, जिसमें जनसंपर्क एजेंसी की मालिक नीरा राडिया की राजनेताओं, अफसरों और पत्रकारों से बातचीत सुनाई दे रही है।

अनुभव और प्रशासनिक ज्ञान की बदौलत संप्रग के दूसरे कार्यकाल में व्यापक प्रशासनिक सुधार और पुनर्गठन की संभावनाएं थीं। इस बात की उम्मीद थी कि सरकार जनांकिक लाभ का ज्यादा से ज्यादा उठाने के लिए तरीके खोजेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय एक युवती के साथ दरिंदगी और सरकार की बेबसी के कारण दिल्ली में लोगों का विरोध शुरू हो गया। ऐसे में नरेंद्र मोदी के भाजपा के पुराने नेतृत्व को किनारे करने पर कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। वह 2014 में उस पार्टी की ताकत से सत्ता में आए, जिसे अपनी महत्त्वाकांक्षाएं पूरी करने के तरीके से बनाया गया था। उन्होंने इस बात को लेकर तुरंत फैसला ले लिया था कि वे पिछली सरकार जैसा कोई घोटाला नहीं होने देंगे। अपने दायरे से बाहर जाने वाले किसी गठबंधन साझेदार को नहीं रखा जाएगा और किसी भी को सरकार को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा।

शिव सेना भाजपा से 2014 से ही नाखुश है। उस समय सेना ने मंत्रिमंडल में मंत्री पद के लिए नामित अनिल देसाई को मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में न जाने और वापस घर लौटने को कहा था क्योंकि सेना का मानना था कि उसे अपना वाजिब हिस्सा नहीं मिला। दोनों दलों के बीच इन दरारों को भरा गया, लेकिन ये बनी रहीं। मंत्रियों ने पाया कि नरेंद्र मोदी के कार्यालय-पीएमओ की मंत्रालयों पर नजर और दखल अधिक है। ऐसे बहुत से मंत्री जो खुद को अनुभवी प्रशासक मानते हैं, उन्हें भी यह तकलीफदेह लगता था कि पीएमओ उनके मंत्रालयों की छोटी-छोटी चीजों का प्रबंधन करता है। पीएमओ प्रस्तावों पर उनसे सवाल करता था और उनके मंत्रालय के लिए अधिकारियों की पसंद को नकार देता था।

लेकिन मोदी ने अरुण जेटली जैसी सहयोगियों की सलाह पर कार्य किया, जो यह जानते थे कि दिल्ली के सत्ता के गलियारों से गुजरना शॉर्क से भरे समुद्र में तैरने के समान है। ऐसे सलाहकारों की सलाह से ही मोदी ने भारत के पुनर्गठन का काम किया। हालांकि पहला कदम नाकाम रहा। भूमि अधिग्रहण कानून को संशोधित करने की कोशिश की गई ताकि उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण आसान बने। भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल का शुरुआती डेढ़ साल इस कानून को बदलने की कोशिश में ही व्यर्थ कर दिया। हालांकि उन्हें पहले से ही यह बात पता थी कि यह कानून राज्य सभा में पारित नहीं होगा, जहां उसका बहुमत नहीं है। आखिरकार सरकार वहीं आ गई, जहां से उसने शुरुआत की थी। उसने भूमि अधिग्रहण और निवेश के लिए उद्योग को आमंत्रित करने का मसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया।

इससे सबक लेते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने ऐसे लोकप्रिय कार्यक्रमों की शुरुआत की, जिन पर कोई राजनीतिक बहस या विवाद नहीं हो सकता था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह बात स्वीकार की थी कि उज्ज्वला और स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों को जनता ने पसंद किया है और विपक्ष का इनकी आलोचना करना राजनीतिक रूप से गलत है। मोदी की हिम्मत को यह तथ्य बयां करता है कि बहुत कम लोगों को यह याद होगा कि कैसे असल में स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी की अगुआई वाली राजग सरकार और फिर संप्रग सरकार के निर्मल भारत अभियानों की रीपैकेजिंग थी।

मोदी इतने उत्साह के साथ स्वच्छता की मुहिम छेड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने ऐसे मसले को जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया, जो न केवल लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि अछूतता और मैला ढोने की प्रथा पर प्रहार था। जन धन योजना और सेवाओं की डिजिटल डिलिवरी ने सरकार को लोगों के बीच पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई।

इनका सरकार को फायदा मिला। जब उनकी सरकार ने ऐसे फैसले लिए जो सही और सुविचारित नहीं थे, तब भी जनता नरेंद्र मोदी के पक्ष में मजबूती से खड़ी रही। वर्ष 2016 की नोटबंदी और उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हमेशा भारतीय राजनीति के इतिहास में पहेली बने रहेंगे।

नोटबंदी से लोगों की जीविका छिन गई, लेकिन फिर भी उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में तन मन से मोदी के पक्ष में मत दिया। मोदी ने नीति-निर्माताओं और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर लोगों को दिखा दिया कि उन्होंने उनमें भरोसा दिखाकर सही काम किया है।

जब 2019 के आम चुनाव नजदीक आए तो भाजपा की नोटबंदी के देरी से दिखने वाले असर को लेकर चिंता बढ़ने लगी। राष्ट्रीय सुरक्षा की दो मिसाइलों- पुलवामा में आतंकी हमले और और उसके जवाब में बालाकोट में आतंकवादियों पर बम गिराने की कार्रवाई ने मई 2019 में और प्रचंड जीत सुनिश्चित कर दी। इसे एक राजनीतिक विमर्श से रेखांकित किया गया। नए हिंदू भारत की कहानी गढ़ी और इसे तर्कसंगत ठहराया, जिसमें अल्पसंख्यकों को अपनी जगह दिखाने की जरूरत है। आज हम जो देख रहे हैं, वह उस विमर्श की ही तर्कसंगत परिणति है।

स्मार्ट डिजाइन और एसयूवी का बोलबाला

बीते दशक में देश का वाहन उद्योग बदल गया। एक ओर डीजल वाहनों का बाजार सिमटता गया वहीं तकनीक आधारित स्मार्ट डिजाइन और खासकर एसयूवी वाहन बाजार पर छा गए।

पवन लाल

टाटा मोटर्स द्वारा दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो के लॉन्च के साथ भारतीय वाहन उद्योग के लिए बीता दशक बहुत उत्साहवर्धक ढंग से शुरू हुआ था। नैनो को देसी डिजाइन की कार माना गया। बिक्री के मामले में कार ने भले ही कमाल नहीं किया लेकिन फिर भी इसके पीछे के विचार को सफल माना गया। इसके कारण अन्य वाहन कंपनियों को भी कार निर्माण के तौर तरीकों का नए सिरे से आकलन करना पड़ा।

रेनो का क्विड मॉडल जिसकी 5 लाख कारें बिक चुकी हैं और जिसे दुनिया भरमें बेचा जा रहा है, वह स्वयं नैनो से प्रेरित है। यह बात निसान-रेनो के मुखिया कार्लोस घोन स्वयं एक अंतरराष्ट्रीय मोटर शो में कह चुके हैं। अंतर केवल यह था कि क्विड भले ही सस्ता विकल्प थी लेकिन इसे दुनिया भर के मेट्रो शहरों में रहने वाले ग्राहकों को देखते हुए डिजाइन किया गया था।

उसी साल देश के 13 बड़े शहरों में बीएस 4 मानक लागू कर दिए गए थे और पेट्रोल कीमतों को नियंत्रणमुक्त किया गया था। इससे कार कंपनियों में डीजल इंजन वाले मॉडल लाने की होड़ मच गई। सन 2013 तक देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजूकी ने स्विफ्ट डिजायर लॉन्च की। इसने चार मीटर से कम लंबाई वाले कॉम्पैक्ट सिडैन सेगमेंट का विस्तार किया। बाद में होंडा ने अमेज के साथ इस बाजार में दखल दिया।

2013 में दो और पश्चिमी कंपनियों ने एक के बाद एक स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल श्रेणी में प्रवेश किया। रेनो इंडिया ने डस्टर के साथ धमाकेदार शुरुआत की। बढ़िया सस्पेंशन, खासी जगह देने वाले इंटीरियर के कारण यह खूब मांग में रही। हालांकि जल्दी ही फोर्ड इंडिया ने इकोस्पोर्ट के साथ इसे टक्कर देनी शुरू की।

आईएचएस मार्किट्स के प्रमुख विश्लेषक सूरज घोष कहते हैं, 'वाहन क्षेत्र में अगला बदलाव ओला और उबर के आगमन के साथ हुआ। इससे एक नए तरह की मांग तैयार हुई लेकिन इसने कार की मांग को लेकर उपभोक्ताओं का व्यवहार भी बदला।'

सन 2014 तक डीजल कीमतें भी नियंत्रणमुक्त हो गईं और साथ ही डीजल कारें पिछड़ने लगीं। परंतु अब तक मारुति सेलेरियो एएमटी

जैसी कारों ने ग्राहकों को कम कीमत पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का चस्का लगा दिया था। अन्य कंपनियां भी लाजिमी तौर पर इस होड़ में शामिल हो गईं।

2015 में हुंडै ने अपनी एसयूवी क्रेटा लॉन्च की। यह दाव कारगर रहा और क्रेटा जल्द ही बेहद लोकप्रिय हो गई और इसकी 2 लाख कारें बिक चुकी हैं। वाहन क्षेत्र के लेखक गौतम सेन कहते हैं, 'अगर आप करीबी निगाह डालें तो हैच बैक से सिडैन और एसयूवी तक यह बदलाव टाटा इंडिगो से लेकर स्विफ्ट डिजायर तथा अन्य उत्पादों तक घटित हुआ। यह ध्यान देने वाली बात है कि एक बार बाजार के परिपक्व हो जाने पर सबसे सस्ता विकल्प सबसे ज्यादा बिकने वाला नहीं रह जाता।'

दो दशक पहले जहां देश में केवल चंद कार कंपनियां थीं वहीं अब दो दर्जन से अधिक कंपनियां हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि कारों का बिकना भी आसान हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माताओं में से एक जनरल मोटर्स ने 2017 में शेवरलेट ब्रांड बंद करके भारत में कारोबार समेट लिया।

परंतु इससे अन्य कंपनियां हतोत्साहित नहीं हुईं। फिएट क्राइसलर की जीप ने अपनी प्रीमियम कंपास एसयूवी भारत में लॉन्च की जिसकी जमकर शुरुआती बुकिंग हुई। इधर महिंद्रा ऐंड महिंद्रा ने एक्सयूवी 300, किया ने सेल्टोस और हुंडै ने वेन्यू कार लगभग एक साथ लॉन्च की। ये सभी कारें अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों वाली तथा विभिन्न फीचर्स से लैस थीं।

सन 2018 में देश में कुल 40 लाख चार पहिया वाहन बिके। लेकिन बीएस 6 मानक को अपनाने का दबाव बढ़ने तथा सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देने के बीच 2019 में कारों का उत्पादन और बिक्री दोनों में कमी आई। मंदी ने भी इसमें योगदान दिया।

टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक गुंटेर बशेक कहते हैं, 'इस वर्ष इस उद्योग को अप्रत्याशित मंदी का सामना करना पड़ा। सुधार कब तक होगा यह कह पाना मुश्किल है लेकिन हमारा ध्यान खुदरा बिक्री पर रहा है। ताकि स्टॉक कम हो, कीमतें कम हों और पूंजी प्रवाह बना रहे।'

टाटा मोटर्स के लिए साल 2020 अहम है। बशेक कहते हैं, 'टाटा मोटर्स के लिए बीएस 6 मानक पर किया गया निवेश अब तक का सबसे बड़ा एकल निवेश है। हम बदलाव की योजना के साथ तैयार हैं और हमारे बीएस 6 वाहन जनवरी 2020 से बाजार में आ जाएंगे।'

हुंडै इंडिया के प्रबंध निदेशक एसएस किम कहते हैं, 'भारत के वाहन क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। भविष्य में अधिक स्वच्छ, कनेक्टेड और साझे में चलने वाली कारों पर जोर होगा।' न केवल हुंडै बल्कि समूचा वाहन उद्योग इन बातों का ध्यान रखेगा।

नए वर्ष में वाहनों की लागत बढ़ सकती है क्योंकि कच्चे माल की कीमत बढ़ी है। बीएस 6 के अनुपालन के कारण भी लागत बढ़ी है। घोष के मुताबिक कीमतों में औसतन 3.5 फीसदी का इजाफा हो सकता है। दोपहिया वाहनों की लागत भी बढ़ेगी।

सन 2020 में वाहन उद्योग के उत्पादन और बिक्री में मामूली सुधार हो सकता है। लेकिन ऐसा बिक्री में सुधार के कारण नहीं होगा बल्कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 2019 में बिक्री बेहद कम रही। माना जा रहा है कि उत्पादन और बिक्री को 2018 के स्तर पर पहुंचने में कम से कम दो वर्ष लग सकते हैं।

पिछले दशक का का घटनाक्रम

- 2010- बीएस 4 उत्सर्जन मानक लागू। टाटा नैनो की बिक्री आरंभ।
- 2012- मारुति सुजूकी ने 4 मीटर से कम लंबाई वाली कॉम्पैक्ट सिडैन स्विफ्ट डिजायर पेश की।
- 2013- फोर्ड ने ईकोस्पोर्ट पेश की जो देश में 4 मीटर से कम लंबाई की एसयूवी में अग्रणी बनी।
- 2014-डीजल की कीमत नियंत्रण मुक्त, मारुति ने सेलेरियो एएमटी पेश की। ग्राहकों को कम कीमत में ऑटोमेटिक कार मिलनी शुरू हुई।
- 2015- हुंडई ने क्रेटा पेश की, एसयूवी को लेकर ग्राहकों का रुख मजबूत हुआ।
- 2016- सरकार ने अप्रैल 2020 तक बीएस 6 मानक पर जाने की घोषणा की। कार निर्माताओं में बदलाव की होड़ मची।
- 2017-जीप कंपास का बाजार में आगमन हुआ और कॉम्पैक्ट एसयूवी की मांग ने जोर पकड़ा। जनरल मोटर्स ने भारत से कारोबार समेटा। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के आगमन को लेकर बयान दिए।
- 2018- राजनीतिक स्थिरता और उद्य बाजार निवेश के कारण वाहन उद्योग में उछाल। लेकिन वर्ष समाप्त होने तक रुख फिर पलटा।
- 2019- बीएस 6 लागू करने की तारीख करीब आने के साथ वाहन बाजार में मंदी।

स्रोतः आईएचएस ऑटो मार्केट, बीएस रिसर्च

सितारों की चमक बरकरार तो छोटी फिल्में भी रहीं जानदार

सोहिनी दास

यह वर्ष छोटे बजट की चौंकाने वाली फिल्मों और भारी बजट वाली फ्रेंचाइजी फिल्मों के नाम रहा। इस वर्ष देश में सिनेमा के परदों पर इनका जादू सर चढ़कर बोला। बॉलीवुड की बात करें तो यहां फ्रेंचाइजी फिल्मों में हाउसफुल 4 और दबंग 3 रिलीज हुईं जबकि हॉलीवुड में डिज्नी-मारवल का दबदबा रहा। बहरहाल, आश्चर्य की बात यह है कि सुपरहीरो फ्रेंचाइजी में डिज्नी की ताजातरीन रिलीज फिल्म राइज ऑफ स्काईवाकर बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित सफलता नहीं हासिल कर सकी हालांकि अभी डिज्नी स्टूडियो को शुरुआती सप्ताहांत के कारोबार के आंकड़े जारी करने बाकी हैं। इन बड़े नामों के मुकाबले बॉलीवुड की कई छोटे बजट की फिल्मों ने कमाल का प्रदर्शन किया। ड्रीम गर्ल से लेकर बाला तक ये एकदम अलग कथावस्तु वाली फिल्में थीं।

मारवल की अवेंजर्स फ्रेंचाइजी हॉलीवुड की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म रही जबकि बॉलीवुड में यह सेहरा हृतिक रोशन की वॉर के सर बंधा। दबंग 3 की कमाई के आंकड़े अभी सामने आने बाकी हैं। परंतु सप्ताहांत पर 81 करोड़ रुपये का शुरुआती आंकड़ा बताता है कि फिल्म भले ही इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों जैसा प्रदर्शन न करे लेकिन यह अच्छी खासी कमाई करेगी।

डिज्नी इंडिया के स्टूडियो एंटरटेनमेंट के प्रमुख विक्रम दुग्गल ने पूर्व में बिज़नेस स्टैंडर्ड को दिए एक साक्षात्कार में कहा था, 'हॉलीवुड भारत में जो क्रांति घटित होती देख रहा है उसके मूल में मार्वेल है। यदि आप इस वर्ष बॉलीवुड तथा अन्य क्षेत्रीय फिल्म उद्योगों की नंबर एक फिल्म पर नजर डालेंगे तो सबसे सफल फिल्म है अवेंजर: एंडगेम। मार्वेल की किस्सागोई की जबरदस्त मांग है।'

ऐसा नहीं है कि केवल मारवल की फिल्म ही कमाई कर रही है। अन्य फ्रेंचाइजी मसलन कंज्यूरिंग सिरीज और एनाबेल सिरीज भी पसंद की जा रही हैं। द नन और एनाबेल कम्स होम जैसी फिल्मों ने तो बॉलीवुड की धीमी हिट आर्टिकल 15 से भी अधिक पैसे कमाए।

इन तमाम फिल्मों की बात करें तो रिलीज के समय की गई मार्केटिंग की गतिविधियों के अलावा सोशल मीडिया पर निरंतर चर्चा और इन पर केंद्रित वस्तुओं के कारोबार ने अहम भूमिका निभाई। हॉलीवुड की फिल्मों को कथानक को संदर्भित करने और स्थानीयकरण की नीतियों से बहुत मदद मिली। फिर चाहे मामला मार्केटिंग योजना और प्रमोशन को हो या प्रख्यात कलाकारों से क्षेत्रीय संस्करणों के संवाद बुलवाना हो। एंडगेम के लिए बने एक गीत को ए आर रहमान ने अपना स्वर दिया। फिल्म अंग्रेजी के साथ तीन भारतीय भाषाओं हिंदी, तमिल और तेलगू में रिलीज हुई। 2,800 स्क्रीन पर

- **बॉलीवुड में हृतिक रोशन की वॉर ने सबसे अधिक कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया**
- **बॉलीवुड की फ्रेंचाइजी फिल्मों में हाउसफुल 4 और दबंग 3 रिलीज हुई जबकि हॉलीवुड में डिज्नी-मारवल का दबदबा**
- **ड्रीम गर्ल से लेकर बाला जैसी अलग कहानियों वाली फिल्मों का दिखा कमाल**

इसके औसतन 1,300 शो रोजाना चले। भारी-भरकम फिल्मों के अलावा छोटे बजट की फिल्मों ने भी खूब चौंकाया। कुछ बड़े बजट की फिल्में ऐसी भी रहीं जिनकी पटकथा एकदम अलग थी। गली बॉय इसका उदाहरण रही। आयुष्मान खुराना की फिल्म 'बाला' (116 करोड़ रुपये) और 'ड्रीम गर्ल' (139.7) करोड़ रुपये की कमाई की। दोनों को सुपरहिट करार दिया गया। ये फिल्में क्रमश: 27 करोड़ रुपये और 30 करोड़ रुपये के कम बजट में बनी थीं। फिल्मों की रिलीज के पहले ऑनलाइन जगत में इन्हें लेकर खूब चर्चा हुई। इस वर्ष की अन्य अधिक कमाई वाली फिल्में मसलन 'हाउसफुल 4', 'वॉर' और 'भारत' क्रमश: 75 करोड़ रुपये, 150 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये के भारी बजट से बनी थीं। इन फिल्मों की मार्केटिंग का बजट भी अच्छा खासा था।

बीते दो वर्षों में दर्शकों की प्रकृति और फिल्मों का कारोबार दोनों काफी बदल गए हैं। देश में ओटीटी के दर्शक बढ़ रहे हैं और नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम और हॉटस्टार (प्रीमियम) जैसे सबस्क्रिप्शन वाले प्लेटफॉर्म का कारोबार बढ़ा है। इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस को नए सितारे और नए कथानक भी मिले हैं। फिल्म निर्माण की आर्थिकी पर भी नए सिरे से विचार हो रहा है। उदाहरण के लिए चार करोड़ रुपये में बनी 'ताशकंद फाइल्स' ने 16.75 करोड़ रुपये कमाए और आर्थिक रूप से सार्थक साबित हुई जबकि करन जौहर और साजिद नादियाडवाला की 'कलंक' 150 करोड़ रुपये में बनी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी।

आने वाले वर्ष में फिल्मों और फिल्मकारों की एक नई पौध अपनी छाप छोड़ेगी। उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे 2019 के सबकों को किस प्रकार ग्रहण करते हैं।

2019 में रुपहले पर्दे पर किन फिल्मों का दबदबा?

ऑनलाइन टिकट बुकिंग मंच बुकमाईशो की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अंग्रेजी फिल्में ज्यादा देखते हैं। 'शो ऑफ दि इयर' नाम के इस रिपोर्ट में भारतीयों द्वारा 2019 में देखी गई फिल्मों और लाइव इंटरटेनमेंट शो के रुझान का जायजा लिया गया है और यह विश्लेषण इस मंच की बुकिंग के आधार पर किया गया है। बुकमाईशो के मंच पर विभिन्न भाषाओं की 1,880 फिल्मों का विकल्प दिया गया। हालांकि इस साल अंग्रेजी फिल्मों में दर्शकों ने काफी दिलचस्पी दिखाई और मारवल स्टूडियो की सुपरहीरो सीरीज की फिल्मों का दबदबा देश के बॉक्स ऑफिस पर दिखा। एवेंजर्स: एंडगेम ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले और बुकमाईशो पर इस फिल्म के 86 लाख से ज्यादा टिकट बिके। इस तरह यह सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई। एंडगेम के बाद बुकमाईशो पर विक्की कौशल अभिनीत फिल्म, 'उरी- दि सर्जिकल स्ट्राइक' के 57 लाख टिकट बिके।

सोहिनी दास

10 प्रमुख फिल्में

(बुकमाईशो पर बिकने वाले फिल्मों के टिकट के आधार पर)

1. अवेंजर्स: एंडगेम
2. उरी-दि सर्जिकल स्ट्राइक
3. कबीर सिंह
4. साहो
5. वॉर
6. दि लॉयन किंग
7. मिशन मंगल
8. सिंबा
9. गली बॉय
10. छिछोरे

सिनेमा के पर्दे पर लंबे समय तक टिकने वाली फिल्में (दिन)

फिल्म	दिन	भाषा
अलादीन	179	(अंग्रेजी)
अयोग्य	125	(तमिल)
कबीर सिंह	102	(हिंदी)
महर्षि	99	(तेलुगू)

2019 के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय इवेंट

- यू2: दि जोशुआ ट्री टुअर 2019
- एनबीए इंडिया गेम्स 2019
- अजीज अंसारी - रोड टू नोव्हेयर
- मारवल एवेंजर्स एस.टी.ए.टी.आई.ओ.एन.
- दि ग्रब फेस्ट

समयसीमा: 1 दिसंबर 2018 से 30 नवंबर 2019

यू2 इवेंट: मुंबई में होने वाले इस कंसर्ट के लिए 26 फीसदी लोग एनसीआर, बेंगलूरु, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद से गए

एनबीए गेम्स: इसे देखने वाले दर्शकों की तादाद 100 फीसदी रही और इस इवेंट की टिकट कीमत औसतन 12,000 रुपये थी

पिछले साल के मुकाबले **हिंदी फिल्मों** की मांग में **25 फीसदी की बढ़ोतरी** हुई

मलयालम फिल्मों की मांग में **108 फीसदी** की बढ़ोतरी और इसके बाद **अंग्रेजी फिल्मों** की मांग में **45 फीसदी** की बढ़ोतरी दिखी

अंग्रेजी फिल्मों के कुल टिकट मूल्य में साल दर साल **56 फीसदी** की वृद्धि हुई

अक्षय कुमार की फिल्मों के **92 लाख टिकट** बिके जबकि **आयुष्मान खुराना** की फिल्मों के **63 लाख टिकट** बिके। इन दोनों अभिनेताओं की तीन-तीन फिल्में इस साल आईं और इनके लिए साल अच्छा रहा

हैदराबाद में **सिनेमा दर्शकों की तादाद सबसे ज्यादा** रही इसके बाद **मुंबई** और **बेंगलूरु** का स्थान रहा। हैदराबाद 2018 के चौथे पायदान से चढ़कर शीर्ष स्तर पर पहुंचा

सिनेमा प्रेमियों ने हर बार औसतन **2.6 टिकट** खरीदे

इस साल बुकमाईशो पर **अग्रिम टिकट बिक्री** में **11 फीसदी** की वृद्धि हुई जो 2 करोड़ टिकट से कम है वहीं फिल्म रिलीज होने से पहले 11 फीसदी फिल्म टिकट खरीदे गए

बुकमाईशो पर **अंतरराष्ट्रीय लाइव इवेंट्स** की तादाद बढ़कर **62 फीसदी** हो गई

मुंबईवासियों ने लाइव मनोरंजन का लुत्फ उठाने के लिए मोटरस्पोर्ट्स **पोल पोजिशन** का आयोजन कराया और बाद में इसका आयोजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और चेन्नई में भी कराया गया

म्यूजिक फेस्टिवल सनबर्न का दायरा इस साल काफी बढ़ा हुआ नजर आया और इस फेस्टिवल में शिरकत करने वाले प्रशंसकों की तादाद बढ़कर **3,00,000** हो गई

नियामकीय चुनौतियों के डर से जूझता रहा घरेलू दवा उद्योग

घरेलू बाजार की मांग में उतार-चढ़ाव की स्थिति नजर आई जबकि प्रमुख दवाइयों की कीमतें बढ़ाने के दवा उद्योग के दबाव के आगे झुकती दिखी सरकार

सोहिनी दास

इस साल देश का दवा उद्योग घटनापूर्ण रहा। देश के प्रमुख निर्यात बाजार अमेरिका में वहां के नियामक के डर की वजह से चीन और जापान जैसे नए क्षेत्रों में नई संभावनाएं तलाशने की कोशिश तेज हुई। इसके अलावा घरेलू बाजार में वृद्धि दर के लिहाज से अच्छा-खासा उतार-चढ़ाव देखा गया। इस क्षेत्र में कैंसर को बढ़ावा देने वाले पदार्थ की चिंता ज्यादा बढ़ती दिखी जो आमतौर पर एंटासिड्स और मधुमेह से जुड़ी दवाइयों में मौजूद हो सकता है। हालांकि इस साल उद्योग को भारतीय औषधि मूल्य नियंत्रक की तरफ से थोड़ी राहत मिली जिसने ज्यादा लागत का दबाव झेल रही कुछ प्रमुख दवाइयों की न्यूनतम कीमत एक बार बढ़ाने की इजाजत दी।

अगर इस क्षेत्र की दवा कंपनियों के शेयरों की कीमत के लिहाज से उनके प्रदर्शन का आकलन किया जाए तब सन फार्मा, ल्यूपिन और सिप्ला जैसी बड़ी दवा कंपनियों के शेयरों में एक साल पहले की अवधि के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई। अच्छे प्रदर्शन से हैरान करने वाली कंपनियों में डिवीज लैबोरेटरीज भी शामिल रही। हैदराबाद की इस कंपनी की शेयर कीमतों में 2019 में 22 फीसदी से अधिक की उछाल देखी गई। नियामकीय चुनौतियों के बावजूद लागत का बेहतर इस्तेमाल करने वाले उपायों और अमेरिका से जुड़ी योजना की वजह से हैदराबाद की दूसरी दवा कंपनी डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।

रेटिंग एजेंसी इक्रा के मुताबिक देश के दवा उद्योग में स्थिरता है। इस क्षेत्र पर इक्रा ने ताजा टिप्पणी करते हुए कहा है, 'दुनिया के सबसे नियंत्रित बाजार अमेरिका में कीमतों के दबाव जैसी विपरीत परिस्थिति पर नियंत्रण बनाने के साथ ही, स्वास्थ्य सेवा खर्च में बढ़ोतरी और इन सेवाओं तक अच्छी पहुंच के जरिये भारतीय बाजार में अच्छी वृद्धि के हालात हैं। अब मुमकिन है कि देश की दवा कंपनियों के लिए अच्छी वृद्धि की संभावना बने।' इक्रा का कहना है कि घरेलू दवा कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2019-2022 में सालाना चक्रवृद्धि दर करीब 10-12 फीसदी तक रह सकती है।

2019 साल के आइने में

नियामकीय जांच में तेजी

अमेरिकी खाद्य एवं दवा प्रशासक की जांच चलने की वजह से भारतीय निर्यातकों के लिए यह साल मुश्किल भरा रहा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि नियामकीय मुद्दों की वजह से इस क्षेत्र का प्रदर्शन बेहद खराब रहा।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2019 की पहली छमाही में नियामकीय मुद्दों, वृद्धि की कमी के साथ अस्थिर अमेरिकी कारोबार, ऊंची कीमतों में कटौती से इस क्षेत्र का प्रदर्शन शेयर बाजार में अच्छा नहीं रहा। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा, 'देश के संयंत्रों को पहले के 7-10 पत्रों के चालू वित्त वर्ष 2019 में मुकाबले 15 चेतावनी भरे पत्र मिले क्योंकि देश में संयंत्रों और आवेदन की तादाद बढ़ रही है।'

विश्लेषकों का मानना है कि देश की कंपनियां अमेरिका में जटिल दवाओं के लिए ज्यादा आवेदन दे रही हैं ऐसे में यूएसएफडीए की जांच-पड़ताल और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं।

अमेरिका में निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की एक इकाई औषधि निर्यात संवर्द्धन परिषद के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही के दौरान देश का कुल दवा निर्यात 11 फीसदी बढ़ा। फार्मेक्सिल के मुताबिक जून की तिमाही के दौरान अमेरिकी निर्यात में 28 फीसदी की वृद्धि दिखी। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर कंपनियों ने अपने कारोबारी मॉडल को जोखिम से निकालने के लिए अपने प्रमुख उत्पाद तैयार करने के लिए पिछले कुछ सालों में वैकल्पिक जगहों और संयंत्रों को तैयार किया।

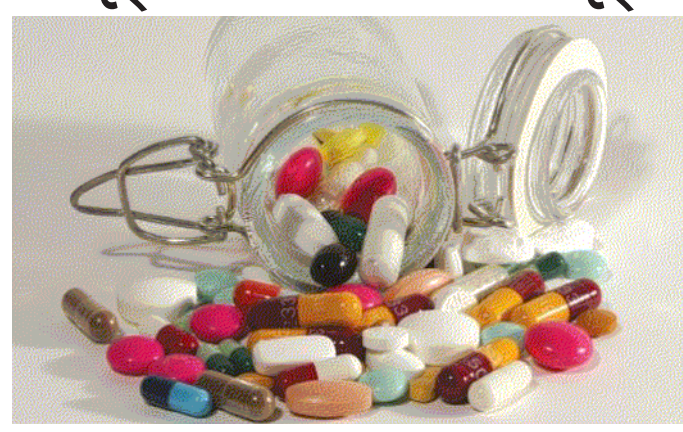

हालांकि बड़े खिलाड़ी जिनमें सन फार्मा भी शामिल है उसने यह संकेत दिया है कि उनका इरादा जापान और चीन जैसे नियंत्रित बाजारों पर ध्यान देने का है। ल्यूपिन जैसी कुछ कंपनियों ने जेनेरिक दवाओं वाली अपनी जापानी सहयोगी इकाइयों को बेच दिया है और उनका कहना है कि वे विशेष तरह की दवाइयों में साझेदारी पर ध्यान देंगी।

दवा उद्योग ने चीन-जापान में नई संभावनाएं तलाशने की कोशिश की

उतार-चढ़ाव

देश के 1.3 लाख करोड़ रुपये के घरेलू बाजार में इस साल उतार-चढ़ाव की स्थिति देखी गई। जून की तिमाही में घरेलू बाजार में सालाना वृद्धि जून 2014 के बाद सबसे कम रही। इसके बाद बाजार में मॉनसून में तेजी आई और एंटी-इफेक्टिव जैसी श्रेणियों की दवाइयों की बिक्री में वृद्धि रही। जुलाई-सितंबर की तिमाही के दौरान बाजार में 11.5 फीसदी की वृद्धि देखी गई और यह वृद्धि कारोबार और कीमत दोनों में देखी गई। हालांकि इसके तुरंत बाद वृद्धि दर अक्टूबर में फिसल कर 5.1 फीसदी के स्तर पर चला गया और नवंबर में इसमें और तेजी आई।

घरेलू बाजार में कारोबारी वृद्धि में गिरावट दिख रही है और कीमतों पर नियंत्रण का दबाव बढ़ने से कंपनियों का जोर ज्यादा मुनाफा देने वाले ब्रांडों पर है। लागत बढ़ने की वजह से दवा निर्माताओं के लिए कुछ उत्पाद का इस्तेमाल करना मुश्किल होने लगा। केंद्र सरकार ने इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए दवा कीमत नियंत्रण आदेश, 2013 के पैराग्राफ 19 को हटा लिया ताकि 21 फॉर्म्यूलेशंस की न्यूनतम सीमा 50 फीसदी तक बढ़ाई जा सके। उद्योग ने काफी लंबे समय से इसकी मांग की थी क्योंकि चीन की तरफ से आपूर्ति बाधित होने से सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) की कीमतें पिछले दो सालों में 10-88 फीसदी तक बढ़ गईं।

केंद्र ड्रग मैन्युफैक्चरिंग पार्क तैयार करने की दिशा में काम कर रही है ताकि स्थानीय स्तर पर दवा तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और चीन पर निर्भरता कम हो जिसका हमारे एपीआई आयात में लगभग 70 फीसदी की हिस्सेदारी है। अब पूरा जोर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और असम चार बड़ा ड्रग पार्क तैयार करने पर है।

कैंसर का डर

घरेलू बाजार में मांग में उतार-चढ़ाव, अमेरिकी नियामक से जुड़ी चिंताओं के अलावा देश की दवा कंपनियों को सामान्य एंटासिड रानीटिडाइन और डायबिटीज की दवा मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयों की सामग्री में कैंसर के संभावित पदार्थ की चिंता है। यूएसएफडीए द्वारा चेतावनी जारी किए जाने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा सहित कई कंपनियों ने रानीटिडाइन उत्पाद वैश्विक स्तर पर हटा दिया गया। देश का नियामक भी सक्रिय हो गया है और इसने इन दवाइयों में कार्सीनोजेन (एनडीएमए) की मौजूदगी की जांच करवानी शुरू कर दी।

2020 की राह

विश्लेषक 2020 को लेकर आशावादी हैं। आईसीआईसीआई का कहना है, 'दवा क्षेत्र के लिए अगला साल सकारात्मक रहने की उम्मीद है और हम देश में 10-11 फीसदी वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। लागत नियंत्रण उपायों से मार्जिन में मदद मिलने के साथ-साथ कीमतों में कटौती से अमेरिकी बिक्री में सकारात्मक वृद्धि होगी। हमने जिन दवा कंपनियों का विश्लेषण किया उनकी शेयर कीमतों में एफडीए से जुड़े मुद्दे बढ़ने और अमेरिकी बिक्री में कमी की वजह से पिछले एक साल में औसतन 11 फीसदी की गिरावट देखी गई।'

आने वाले दिनों में एफडीए की अक्सर होने वाली निगरानी की नियामकीय बाधाओं, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और जरूरी दवाइयों की राष्ट्रीय सूची (जिनकी कीमतों पर सरकार का नियंत्रण होता है) में ज्यादा दवाइयों को शामिल किए जाने जैसे जोखिम बढ़ेंगे।

तकनीकी विस्तार में 4जी ने दिखाया कमाल

पृष्ठ 1 का शेष

कोई भी तकनीक 4जी कनेक्टिविटी के बिना इतनी कुशल, प्रभावी या लोकप्रिय नहीं हो पाती। सभी तरह की जानकारी तक पहुंच बनाने वाले सर्वर, भोजन से लेकर फैशन तक सभी जरूरतों के लिए खोज और कहीं भी सफर पर जाने के लिए राह दिखाने वाला इंटरनेट 4जी मोबाइल नेटवर्क के जरिये डेटा के अथाह भंडार तक पहुंच उपलब्ध कराने से ही संभव हो पाता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर हम सभी की अधीरता का समय घटकर केवल कुछ सेकंड तक सीमित हो गया है। गूगल मैप पर किसी जगह जाने के लिए रास्ते की खोज में मामूली देरी होने पर हमें गुस्सा आ जाता है। यह सब 4जी पर हमारी निर्भरता के चलते हो रहा है। 4जी तकनीक को दिसंबर 2009 में लॉन्च किया गया और इसने पिछले 10 वर्षों में तीसरी पीढ़ी की मोबाइल कनेक्टिविटी की गति 10 गुना तक बढ़ा दी है। फोन निर्माताओं ने तेजी से उपकरणों का उन्नयन किया है और ऑनलाइन कारोबार बढ़ने से पारंपरिक कारोबारी मॉडल लगभग खत्म हो गया है। वर्ष 2014 में 1.3 लाख करोड़ डॉलर से बढ़कर 2023 तक इसका अनुमानित आकार 6.5 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगा। 4जी तकनीक ने पूरे विश्व में लाखों ग्राहकों को केबल से मुक्ति दे दी है क्योंकि अब मनोरंजन कारोबार उपग्रह व्यवस्था ले बदलकर स्ट्रीमिंग तकनीक पर आ चुका है।

साझा कारोबार:

इंटरनेट कनेक्टिविटी ने साझी अर्थव्यवस्था तथा साझी सोसायटी की अवधारणा को जन्म दिया। उबर ने इस अवसर को भुनाया। राइड साझा करना एक उद्योग बन गया और उत्पाद तथा सेवा प्रदाताओं ने अपना कारोबारी मॉडल विकसित किया। एयरबीएनबी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए लोगों को अपना घर साझा करने की सुविधा दी। नए युवा उत्पाद खरीदने के बजाए साझा करने को वरीयता देने लगे। कार, फर्नीचर, घर और कार्यस्थल तक साझा होने लगे।

हमारे सामाजिक व्यवहार में साझा करने की प्रवृत्ति शामिल है। 'साझा करें' स्वयं एक आइकन है। ऑनलाइन उपलब्ध कोई भी सामग्री 'साझा करें' वाले विकल्प के बिना अधूरी सी लगती है। साझा करना केवल सेवाओं तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें विचार, राय और रेटिंग भी शामिल है। यह ग्राहक संबंधी उद्योगों में सेवाओं तथा ग्राहक अनुभव को तेजी से बदल रही हैं। बुकिंग डॉट कॉम, ट्रिप एडवाइजर और गुड रीड्स ने उत्पाद समीक्षा का लोकतांत्रिकरण किया और विशेषज्ञों के स्थान पर ग्राहकों द्वारा समीक्षा कराई जाने लगी। प्रत्येक सेवा तथा उत्पाद ऑनलाइन रेटिंग पर निर्भर करता है और ये समीक्षाएं सार्वजनिक हैं एवं ग्राहकों द्वारा साझा की जाती हैं। साझा अथवा गिग अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2023 तक 455 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। पिछले एक दशक में हुए बदलाव अगली शताब्दी तक हमारे साथ रहेंगे। एआई तथा संबंधित तकनीक की मदद से साझा कारोबार तथा क्लाउड कंप्यूटिंग की अवधारणा तेजी से आगे बढ़ेगी। अब भविष्य 5जी पर निर्भर करेगा। कोई भी उपकरण शायद भौतिक अवस्था में नहीं रहेगा। एक्स-रे मशीन हमारे मोबाइल में लगे कैमरे की तरह एक ऐप मात्र हो सकता है। लैपटॉप समाप्त होकर केवल प्रोजेक्टेड कीबोर्ड में बदल सकते हैं। आने वाला दशक कई अप्रत्याशित आश्चर्यों से भरा होगा। उम्मीद है कि पिछले एक दशक का अनुभव हमें अकल्पनीय भविष्य के लिए तैयार करेगा।